₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

सितम्बर 2025

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

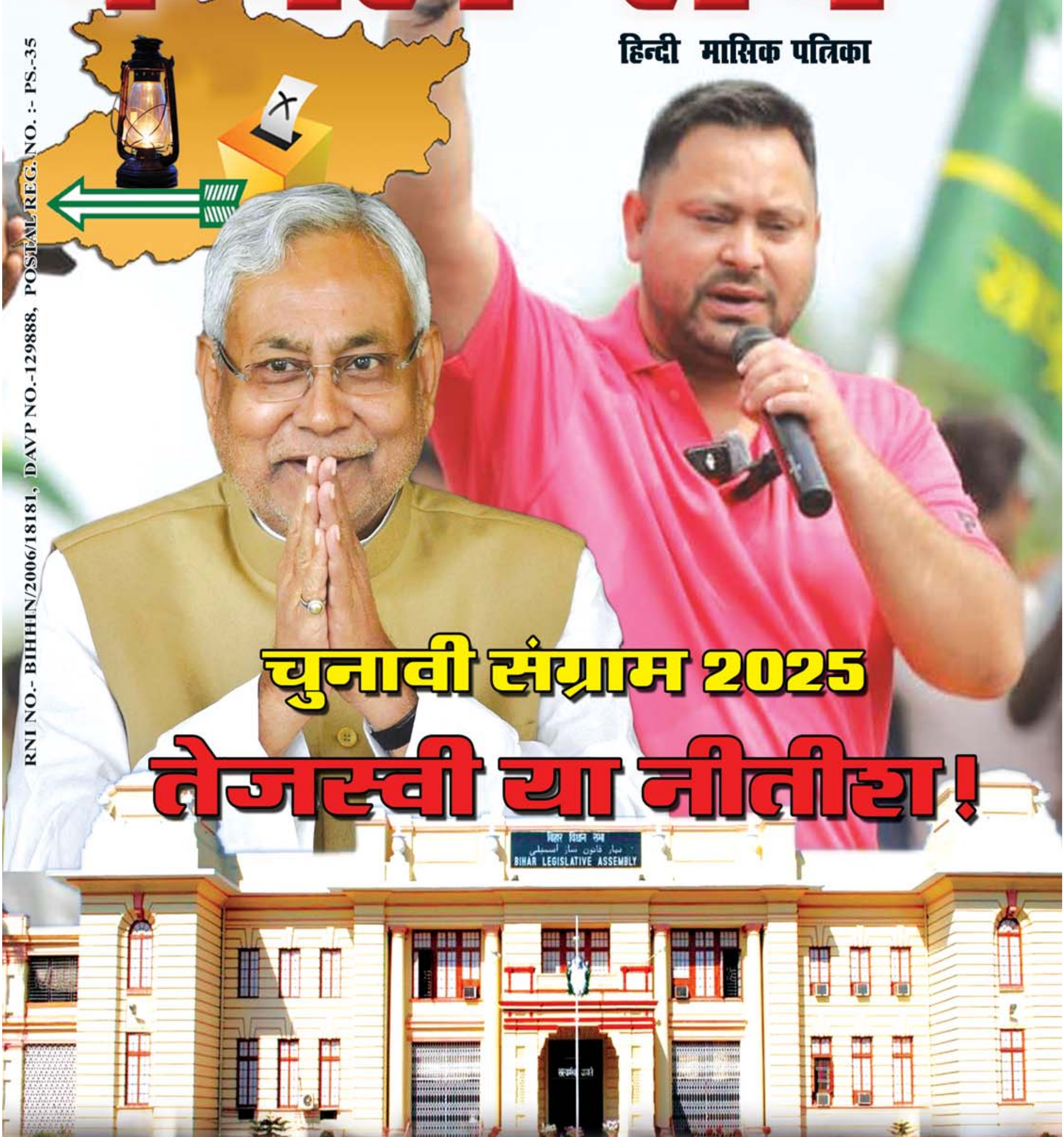

चुनावी संग्राम 2025

तेजस्वी या नीतीश!

RNI NO.- BIHHIN/2006/18181, DAVP NO.-129888, POSTAL REG. NO. :- PS.-35

जन-जन की आवाज है केवल सच

निर्भीकता हमारी पहचान
केवल सच
हिन्दी मासिक पत्रिका

Kewalsachlive.in
वेब पोर्टल न्यूज
24 घंटे आपके साथ

Kewalsach news
Kewalsach news
Mob.: 9431073769, 9308815605
खबर वहीं, जो केवल सच हो

केवल सच TIMES

आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

BHIM | UPI
G Pay Paytm

www.kewalsach.com www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,
कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

विवेक ओबेरॉय
03 सितम्बर 1976

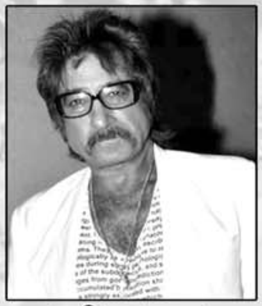
शक्ति कपूर
03 सितम्बर 1952

ऋषि कपूर
04 सितम्बर 1952

यशवंत सिन्हा
06 सितम्बर 1937

आशा भोसले
08 सितम्बर 1933

अक्षय कुमार
09 सितम्बर 1967

रामजेठ मलानी
10 सितम्बर 1923

महिमा चौधरी
13 सितम्बर 1973

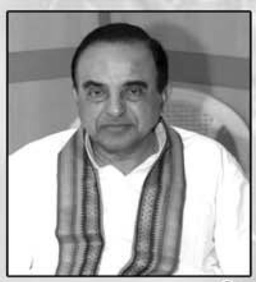
सुब्रमणयम स्वामी
15 सितम्बर 1939

भूपिंदर सिंह हुड्डा
15 सितम्बर 1947

पी. चिदम्बरम
16 सितम्बर 1945

नरेन्द्र मोदी
17 सितम्बर 1950

महेश भट्ट
20 सितम्बर 1948

करीना कपूर
21 सितम्बर 1980

प्रेम चोपड़ा
23 सितम्बर 1935

कुमार सानू
23 सितम्बर 1957

मनमोहन सिंह
26 सितम्बर 1932

यश चोपड़ा
27 सितम्बर 1932

लता मंगेसकर
28 सितम्बर 1929

रणवीर कपूर
28 सितम्बर 1982

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha, A-68, 1st Floor, Nageshwar Talla Shastri Nagar, New Delhi - 110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
E-mail:- kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube, 131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

जिद्द में गिरा रहे हैं साख

जिद्द किसी भी व्यक्ति के पत्तन का मुख्य कारण बनता है क्योंकि वह अपनी जिद्द को पूरा करने के लिए पूरे सिस्टम के साथ खिलवाड़ करता है। बिहार में 01 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी है लेकिन प्रदेश के भीतर शराबबंदी का मजाक उड़ा रहे माफिया के सामने पुलिस बौना साबित हो रही है। 2009 एवं 2018 बैच के थाना प्रभारी की संपत्ति की जांच होगी तो इससे खुलासा हो जायेगा कि शराबबंदी से किसको लाभ हुआ है। लगभग 6 हजार करोड़ का राजस्व का क्षति झेल रही बिहार सरकार अपनी जिद्द की वजह से बिहार के माफियाओं और पुलिस विभाग के साथ - साथ उत्पाद एवं मद्य निषेद्य विभाग के अधिकारी अकूट संपत्ति अर्जित करने में कामयाबी हासिल किया है। माफियाओं की हिम्मत इतनी बढ़ती जा रही है कि पुलिस के जवानों को भीड़ बनकर ऑन विडिओ पीट रही है। शराबबंदी सिर्फ नीतीश कुमार की व्यक्तिगत जिद्द है ताकि प्रदेश की जनता को वह स्वस्थ रख सकें लेकिन उनका पुलिस - प्रशासन शराब माफियाओं के सामने आर्थिक लाभ के कारण घुटने टेक चुकी है। शराबबंदी बिहार विधानसभ चुनाव 2025 में चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है और प्रशांत किशोर ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो शराबबंदी से बिहार को मुक्त कर दिया जायेगा। जिद्द के कारण बिहार की छवि धूमिल हो रही है और पुलिस की गिर रही है साख।

ब्रजेश मिश्र, संपादक
8340360961, 9431073769

बिहार में बहार है, नीतीशे कुमार है का स्लोगन से आगे निकल चुका बिहार का एनडीए यह कह रहा है 2025 फिर से नीतीश। महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2015 प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की थी और सरकार बनने के 04 महीने बाद 01 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी हो गयी और बिहार सरकार को प्रतिवर्ष हजारों करोड़ का राजस्व की क्षति होने लगा लेकिन नीतीश कुमार का जिद्द हो गया कि किसी भी सूरत में शराबबंदी से बिहार मुक्त नहीं होगा। कई सभाओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा है कि **''जो पीयेगा, वह मरेगा''** इस बात को विपक्ष मुद्दा बना रहा है। शराबबंदी से बिहार सरकार को भले ही राजस्व की क्षति हुई हो लेकिन राष्ट्रीय अपराध रिकॉड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं की प्रति घरेलू हिंसा, मारपीट, दुर्घटना में कमी आयी है। ज्ञात हो कि शराबबंदी को लेकर 2018 में नीतीश कुमार ने सर्वे कराया था जिसमें यह रिपोर्ट दिखाया गया कि 64 लाख लोगों ने शराब को छोड़ दिया है तथा दूसरा सर्वे 2023 में चाणक्य लॉ विश्वविद्यालय और एएन सिन्हा इंस्टिच्यूट ने संयुक्त रूप में किया और यह बताया गया कि 82 लाख लोगों ने शराब छोड़ दिया है। 99 प्रतिशत महिलाएं एवं 93 प्रतिशत पुरूष शराबबंदी के पक्ष में हैं जबकि विपक्ष और सत्ता में शामिल जीतन राम माँझी ने भी यह कहा है कि शराबबंदी नीतीश कुमार का सिर्फ व्यक्तिगत जिद्द है जिससे सरकार का खजाना भी खाली हो रहा है और लोग जहरीली शराब पीने को मजबूर होकर मर रहे हैं तथा माफियाओं का साम्राज्य कायम हो चुका है। जन सुराज के सुप्रीमों प्रशांत किशोर ने यहां तक कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले शराबबंदी कानून को रद्द करेंगे क्योंकि सीएम के जिद्द की वजह से गरीब वर्ग के लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं और माफियाओं का आतंक इतना बढ़ गया है कि पुलिस को खदेड़-खदेड़ कर पीट रही है। जमुई की वरहट की घटना ने पुलिस और सरकार दोनों की साख को मिट्टी में मिला दिया है कहना अनुचित नहीं होगा। शराबबंदी कानून की सख्ती ने जहां शराबियों का जीना हराम कर दिया और न्यायालय में इस वजह से काफी बोझ बढ़ गया है। शराबबंदी कानून के तहत 936949 से भी अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं जिसमें 14 लाख 32 हजार 837 से भी अधिक लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। शराबबंदी को कारगर बनाने के लिए विशेष न्यायालय बनाया गया है, वहां भी काफी बोझ बढ़ता जा रहा है। कई बार संशोधन भी हुए पर शराब माफियाओं का नेटवर्क के सामने सरकार वं पुलिस की साख गिरती जा रही है क्योंकि शराब माफियाओं का पुलिस के साथ दमदार गठजोड़ जिसकी वजह से 2009 एवं 2018 बैच के थाना प्रभारी की संपत्ति की जांच हो तो प्रदेश के आईपीएस भी शर्मा जायेंगे। दिखाने के लिए 9 साल में 100 से अधिक शराब माफिया को सलाखों के पीछे धकेला गया। अवैध शराब के मुहिम में 6.5 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा 147 लाख लीटर से अधिक शराब को जप्त किया गया। लेकिन हर घर शराब की उपलब्धता ने सरकार को सोचने पर विवश कर दिया जिसकी वजह से पहली बार शराब पीने वाले को बांड भरकर छोड़ने की पेशकश की है। शराब पीने से लगभग 200 प्रकार की बीमारी होने की संभावना प्रबल होती है। आत्महत्या करने वालों में शराबियों की भी संख्या अधिक होती है तथा सड़क दुर्घटना में भी इसका बड़ी भूमिका होती है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ताड़ी को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। शराबबंदी का कानून का मजाक उड़ा रहे माफिया एवं पुलिस ने नीतीश कुमार की व्यक्तिगत ब्रांडिंग की सोच पर ग्रहण लगा दिया है और नीतीश कुमार अपनी जिद्द लिए बैठे हैं कि मेरे रहते यह संभव नहीं है जबकि यह भी सत्य है कि शराबबंदी की वजह से बिहार में अमन-चैन कायम है और यह भय का माहौल है कि पीने के बाद वह हंगामा नहीं करता लेकिन जहरीली शराब की वजह से वह काल के भेंट चढ़ रहा है। बिहार प्रदेश में कहने के लिए शराबबंदी है पर पुलिस की जानकारी में बल्कि उनके संरक्षण में शराब माफिया कानून को ठेंगा दिखाने में कामयाब हो रहे हैं और शराब कितना सुलभ है इसको लेकर कई विडिओ वायरल हो रहे हैं। शराब माफियाओं की हिम्मत की दाद देनी होगी कि वह पुलिस को जानवरों की तरह आमजनता से पिटवाने में कामयाब भी हो रहे हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में शराबबंदी एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है और नीतीश कुमार यह जिद्द लिए बैठे हैं कि शराबबंदी से प्रदेश की महिलाओं की शक्ति बढ़ी है परन्तु जिद्द के चक्कर में साख पर कलंक भी लगता जा रहा है क्योंकि कई सफेदपोश लोग भी शराब के धंधे में मशगूल हैं। एक एसएसपी विवेक कुमार को कई वर्ष तक संट करके रखा गया तथा इस खेल में कई बड़े अधिकारी एवं नेताओं का संरक्षण की वजह से पुलिस अपना राजस्व भरने में सक्रिय है। अतिक्रमण और शराब के छोटे कारोबारियों से स्थानीय थाना का इतना बढ़िया साठ-गांठ है कि वह सबकुछ जानते हुए भी मौन रहती है। अगर नीतीश कुमार यह जिद्द रखते हैं कि शराबबंदी को समाप्त नहीं किया जायेगा और उनकी साख बरकरार रहे तो पुलिस पर सख्ती से पेश आना होगा और टारगेट करके माफियाओं को पकड़ना होगा जैसे आजकल यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले के साथ सख्ती किया जा रहा है अन्यथा जिद्द उनकी साख को धूमिल करने में कामयाब हो जायेगा।

अगस्त 2025

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

द्वारा:- ब्रजेश मिश्र

हमारा पता है :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28

कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308

हमारा ई-मेल

kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach_times@rediffmail.com

आजादी

ब्रजेश जी,

आपका संपादकीय आमलोगों की आवाज है क्योंकि साधारण भाषा में किसी भी मुद्दे की हकीकत को बिना तोड़ मोड़ के लिखते हैं। अगस्त 2025 अंक का संपादकीय **गाली देने की है आजादी** आलेख में वर्तमान भारत की राजनीति एवं कूटनीति से रूबरू कराया है। मुफ्त में मिली आजादी का महत्व बस इतना रह गया है कि भारतीय सेना की कार्रवाई पर भी संवेदनशील होने के बजाय सेना पर ही कटाक्ष करते हुए उसके धारदार ऑपरेशन पर उंगली उठाते हैं। इस प्रकार के गंभीर आलेख से अच्छी शिक्षा मिलती है।

✦ महेन्द्र श्रीवास्तव, करोल बाग, नई दिल्ली

वोटर अधिकार

ब्रजेश जी,

अगस्त 2025 अंक में पत्रकार अमित कुमार की आवरण खबर **वोटर अधिकार यात्रा पर युवराज** में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव ने मोदी और नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं पर एसआईआर के मुद्दे पर शिक्षित वोटर युवराज के चक्रव्यूह में नहीं फंसेगा जैसा माहौल दिख रहा है। यह खबर काफी विस्तार से लिखा गया जो पठनीय है तथा सोचकर निर्णय लेने पर विवश करती दिख रही है।

✦ मो गुलाब साबरी, टावर चौक, मुंगेर बिहार

गुरू जी

मिश्रा जी,

मैं आपकी पत्रिका का नियमित पाठक हूँ और इसकी सभी खबरों को पढ़ता हूं तथा अब पुलिस विभाग के अलावा राजनीति पर भी संवेदनशील खबरों को स्थान दिया जा रहा है। अगस्त 2025 में गुड्डी साव की खबर **गुरुजी एक युग का अंत** में झारखंड के लोकप्रिय एवं जुझारू नेता शिबू सोरेन की निधन पर यह आलेख झारखंडवासी को सोचने पर मजबूर करता है गुरु जी का योगदान सच में झारखंड के अस्तित्व को बचाने में मिल का पत्थर साबित हुआ है। नमन ऐसे व्यक्तित्व को जिसने बहुत संघर्ष करके आदिवासी समाज को बहुत आगे बढ़ाया है। नमन है गुरु जी।

✦ मनोज उराँव, बिरसा मुंडा चौक, राँची

एक पर एक यूपी

मिश्रा जी,

अगस्त 2025 अंक में उत्तरप्रदेश की एक पर एक खबरों को पत्रकार बंधुओं ने लिखा है जो सटीक जानकारी के साथ जनहित में उपयोगी लग रहा है। पहली खबर राजनीतिक गलियारों में पंचायत चुनाव की सरगर्मी में अजय कुमार ने भाजपा के साथ अन्य दलों की हकीकत सामने रख दिया है। वहीं अजय कुमार की खबर सपा में काफी पुराना है महिला अपमान का सिलसिला भी गंभीर आलेख है तो पत्रकार संजय सक्सेना की खबर डिंपल की तौहीन पर अखिलेश की चुप्पी की मजबूरी को सटीक समीक्षा की है। यूपी की ऊर्जा मंत्री का बयान वाली खबर भी काफी करंट वाला है। यूपी की खबरों को प्राथमिता से छापें।

✦ प्रदीप पाठक, अस्सी घाट, बनारस, यूपी

सुप्रीम कोर्ट

संपादक जी,

संजय सिन्हा की खबर फिर पलटा सुप्रीम कोर्ट कुत्ते मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अजब गजब में न्यायालय की भूमिका पर दमदार कटाक्ष करते हुए लिखा है जो बधाई योग्य है। कुत्तों को पकड़कर नसबंदी करके वहीं छोड़ देने के मामले को लेकर अलग अलग जजों का फैसला आया है. यह जानकर हैरत हुआ कि 70 प्रतिशत कुत्तों का ही नसबंदी किया जाएगा अब उन 30 प्रतिशत कुत्तों को क्यों छोड़ दिया है. रेबीज कुत्तों से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है. भले ही यह खबर कुत्तों पर केंद्रित था लेकिन अच्छा लगा यह खबर पढ़कर.

✦ रामपुकार सिंह, अशोक नगर, नई दिल्ली

छात्रा बरामद

संपादक जी,

झारखंड की पुलिस प्रशासन की खबरों को प्राथमिकता के साथ ओम प्रकाश प्रति महीने लिखते हैं जिससे सही जानकारी मिलती है। अगस्त माह 2025 अंक में ओम प्रकाश की खबर अपहरण के दो घंटे बाद छात्रा बरामद में पुलिस की सक्रियता की वजह से अपराधियों की प्लानिंग पर पानी फेर दिया जबकि पूरी कहानी को पढ़ने से ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय से उस छात्रा की रेकी किया गया और परिजनों की आर्थिक स्थिति का भी मूल्यांकन किया गया है। पुलिस वास्तव में इस उद्भेदन के लिए बधाई की पात्र है।

✦ शंकर वर्मा, हरमू चौक, गली नं-01, राँची

अन्दर के पन्नों में

28

39

संघर्ष से कौन बनेगा करोड़पति के मंच...58

आशा की किरण या आंख में धूल.......94

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, DAVP No.- 129888

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 20	अंक:- 232	माह:- सितम्बर 2025	मूल्य:- 20/- रू

फाउंडर

श्रद्धेय गोपाल मिश्र
श्रद्धेय सुषमा मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769 8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

अरूण कुमार बंका (एडमिन)	7782053204
सुरजीत तिवारी	9431222619
निलेन्दु कुमार झा	9431810505, 8210878854
सच्चिदानन्द मिश्र	9934899917
रामानंद राय	9905250798
डॉ० शशि कुमार	9507773579

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र	9430888060, 8873004350
अमोद कुमार	9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9308815605, 9122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल	9430000482, 9798874154
मनीष कुमार कमलिया	9934964551, 8809888819

उप-संपादक

प्रसुन्न पुष्कर	9430826922, 7004808186
ब्रजेश सहाय	7488696914
ललन कुमार	7979909054, 9334813587
पंकज कुमार सिंह	9693850669, 9430605967

राजनीतिक संपादक

सुमित रंजन पाण्डेय	7992210078
संतोष कुमार यादव	8210487516

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू'	9905244479, 7979075212
राजीव कुमार शुक्ला	9430049782, 7488290565
काशीनाथ गिरी	9905048751, 9431644829
अविनाश कुमार	7992258137, 9430985773
कुमार अनिकेत	9431914317

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह	8210772610, 9431253179
मिथिलेश कुमार	9934021022, 9431410833
नवेन्दु कुमार मिश्र	9570029800, 9199732994
ऋषिकेश पाण्डेय	7488141563, 7323850870

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र	9608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा	9386901616, 7762089203

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि	9308454485
रवि कुमार पाण्डेय	9507712014

चीफ क्राइम ब्यूरो

सैयद मो० अकील	9905101976, 8521711976
आनन्द प्रकाश	9508451204, 8409462970

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार	9905244479

amit.kewalsach@gmail.com

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव	8002647553, 9060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार	9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०)	:- श्रीधर पाण्डेय	9470709185
(म०)	:- गौरव कुमार	9472400626
(ग्रा०)	:- मुकेश कुमार	9473038020
बाढ़	:-	
भोजपुर	:- गुड्डू कुमार सिंह	8789291547
बक्सर	:- बिन्ध्याचल सिंह	8935909034
कैमूर	:-	
रोहतास	:- अशोक कुमार सिंह	7739706506
	:-	
गया (श०)	:- सुमित कुमार मिश्र	7667482916
(ग्रा०)	:-	
औरंगाबाद	:-	
जहानाबाद	:- नवीन कुमार रौशन	9934039939
अरवल	:- संतोष कुमार मिश्रा	9934248543
नालन्दा	:-	
	:-	
नवादा	:- अमित कुमार	9162664468
	:-	
मुंगेर	:-	
लखीसराय	:-	
शेखपुरा	:-	
बेगूसराय	:-	
	:-	
खगड़िया	:-	
समस्तीपुर	:-	
जमुई	:- अजय कुमार	09430030594
वैशाली	:-	
	:-	
छपरा	:-	
सिवान	:-	
	:-	
गोपालगंज	:-	
	:-	
मुजफ्फरपुर	:- .	
	:-	
सीतामढ़ी	:-	
शिवहर	:-	
बेतिया	:- रवि रंजन मिश्रा	9801447649
बगहा	:-	
मोतिहारी	:- संजीव रंजन तिवारी	9430915909
दरभंगा	:-	
	:-	
मधुबनी	:-	
	:- प्रशांत कुमार गुप्ता	6299028442
सहरसा	:-	
मधेपुरा	:-	
सुपौल	:-	
किशनगंज	:-	
	:-	
अररिया	:- अब्दुल कय्यूम	9934276870
पूर्णिया	:-	
कटिहार	:-	
भागलपुर,	:-	
(ग्रा०)	:- रवि पाण्डेय	7033040570
नवगछिया	:-	

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर,
नई दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो०- 9868700991, 9431073769

उत्तरप्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
.................................., स्टेट हेड

सम्पर्क करें
9308815605

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो०- 9433567880, 9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो०- 8109932505,

झारखंड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव,
द्वितीय त्तल, फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 7903856569, 6203723995

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,

.................................., स्टेट हेड
सम्पर्क करें
8340360961

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या.- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ e-mail:- kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☛ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☛ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☛ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☛ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ **सभी पद अवैतनिक हैं।**

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- Punjab National Bank
IFSC Code :- PUNB0060020
PAN No. :- AAJFK0065A

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- State Bank of India
IFSC Code :- SBIN0003564
PAN No. :- AAJFK0065A

प्रधान संपादक

....
....

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो

....

झारखण्ड सहायक संपादक

अभिजीत दीप	7004274675, 9430192929
ब्रजेश मिश्र	7654122344, 7979769647
अनंत मोहन यादव	9546624444, 7909076894

उप संपादक

अजय कुमार 6203723995, 8409103023
....

संयुक्त संपादक

....

विशेष प्रतिनिधि

भारती मिश्रा 8210023343, 8863893672
....
....

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची	:- अभिषेक मिश्र	7903856569
	:- ओम प्रकाश	9708005900
साहेबगंज	:-	
खूँटी	:-	
जमशेदपुर	:- तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता	9304824724
हजारीबाग	:-	
जामताड़ा	:-	
दुमका	:-	
देवघर	:-	
धनबाद	:-	
बोकारो	:-	
रामगढ़	:-	
चाईबासा	:-	
कोडरमा	:-	
गिरीडीह	:-	
चतरा	:- धीरज कुमार	9939149331
लातेहार	:-	
गोड्डा	:-	
गुमला	:-	
पलामू	:-	
गढ़वा	:-	
पाकुड़	:-	
सरायकेला	:-	
सिमडेगा	:-	
लोहरदगा	:-	

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,
लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक "**मगध इंटरनेशनल स्कूल**" टेकारी

" **केवल सच** " पत्रिका **एवं** " **केवल सच टाइम्स** "

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

व्यवसायी

पटना, बिहार

7360955555

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो		
पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	**धर्मेन्द्र सिंह**	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि	
महेश चौधरी	9572600789, 9939419319
आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
सूमन सौरभ	9471492480, 7004952447
शालनी झा	9031374771, 7992437667
बेंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
राजीव नयन	9973120511, 9430255401
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417
कुमार राजू	9310173983
रजनीश कांत झा	9430962922, 7488204140

छायाकार	
त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	9386899670,
कृष्णा प्रसाद	9608084774, 9835829947

झारखंड राज्य प्रमंडल ब्यूरो		
राँची	गुड्डी साव	6299470142
हजारीबाग		
पलामू		
दुमका		
चाईबासा		

चुनावी संग्राम 2025
तेजस्वी या नीतीश!

● **अमित कुमार**

बिहार में इन दिनों वर्ष के आखिरी में त्यौहारों के बीच बड़ा त्यौहार यानि होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का इंतजार सभी राजनीतिक पार्टियां बेशर्बी से कर रही है, बस चुनाव की तारिखों का ऐलान करना रह गया है, पर तैयारियां जोरों पर है। सभी के पास अपने-अपने मुद्दे है और उन मुद्दों के बदौलत बिहार की कुर्सी पर बैठने की जद्दोजहद जारी है। बीते कुछ महीनों से वोट चोरी का मुद्दा इंडी एलायंस ने खूब उठाया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 'वोटर अधिकार यात्रा' भी जोरदार तरीके से की गई। अब चूकि समय कम है तो जनता के बीच विकास और लुभावन घोषणाओं को लेकर प्रचार जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहले से ही प्रगति यात्रा के अगले फेज की यात्राएं जारी है। चूकि चुनाव का समय है और समय कम, तो इस बार भी चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर बुक होने शुरू हो गये हैं।

विदित हो कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष का मोर्चा तेजस्वी यादव संभाल रहे थे। वो रोजाना 14 से 16 जनसभाएं कर रहे थे। एक दिन तो उन्होंने 19 जनसभा करने का रिकॉर्ड बना दिया था। ये संभव हुआ 'उड़न खटोले' यानी हेलीकॉप्टर की वजह से। अब साल 2025 के चुनाव में राजनीतिक दल फिर से सियासत की ऊंची उड़ान भरने के लिए उड़न खटोले का ताबड़तोड़ इस्तेमाल करने वाले है। राजनीतिक दलों की ओर से इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है। साल 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार स्टेट हैंगर से हर रोज 20 चॉपर उड़ान भरेंगे। एनडीए और महागठबंधन की ओर से हेलीकॉप्टर की एडवांस बुकिंग कर ली गई है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू गठबंधन की ओर से दर्जन भर से ज्यादा हेलीकॉप्टर बुक कराए गए हैं। स्टेट हैंगर से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, एनडीए के नेता रोज 14 से 15 हेलीकॉप्टर का उपयोग करेंगे। इसमें बीजेपी जहां 12 या 13 हेलीकॉप्टर का यूज करेगी। वहीं जदयू की ओर से हर रोज दो हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। इन हेलीकॉप्टर्स में एनडीए के घटक दल के नेताओं को भी जगह दी जाएगी। एनडीए के बरअक्स महगठबंधन की ओर से भी हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराई जा रही है। जानकारी के मुताबिक महागठबंधन के घटक दल पांच हेलीकॉप्टर के जरिए चुनाव प्रचार को गति देंगे। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी के दो हेलीकॉप्टर हवाई उड़ान भरेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी दो हेलीकॉप्टर की बुकिंग की गई है. वहीं गठबंधन के एक और सहयोगी मुकेश सहनी भी हेलीकॉप्टर के जरिए चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि चुनाव के समय हेलीकॉप्टर की बढ़ती मांग के चलते किराए में भी जबरदस्त

उछाल आ जाता है। सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर का किराया जहां सवा गुना हो जाता है, वहीं डबल इंजन हेलीकॉप्टर का किराया 2 गुना बढ़ जाता है। सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर के लिए एक लाख से 2 लाख प्रति घंटा किराया चुकाना होता है। वहीं डबल इंजन हेलीकॉप्टर का किराया तीन से चार लाख रुपए प्रति घंटा तक पहुंच जाता है। राजनीतिक दलों और नेताओं को हर रोज हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए ऊंची कीमत चुकानी पड़ती है। हर रोज हेलीकॉप्टर बुक करने वाले दल या नेताओं को 3 घंटे का फ्लाइंग चार्ज देना होता है और 18 प्रतिशत जीएसटी भी चुकाना होता है। इस हिसाब से एक हेलीकॉप्टर के लिए राजनीतिक दलों को हर रोज लगभग 11 लाख रुपये चुकाने होंगे।

खैर! सबसे अहम इस बात को लेकर है कि 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव कितने फेज में कराये जायेंगे और कब तक तारिखों की घोषणा हो सकती है, तो बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। राज्य में तीन फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। नए विधानसभा के गठन के लिए नवंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में वोटिंग संभव है। दुर्गापूजा के बाद अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते की

शुरुआत में चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर सकता है। बिहार में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग को इस तारीख से पहले नए विधानसभा के गठन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। चुनाव आयोग दीवाली और छठ पूजा के बाद बिहार में वोटिंग कराने की तैयारी में है। तारीखों का एलान करते समय कार्तिक पूर्णिमा पर्व का भी ध्यान रखा जाएगा। सूत्रों के अनुसार राज्य में तीन फेज में वोटिंग कराए जाने की संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए 5 से 15 नवंबर के बीच वोटिंग कराए जाने की संभावना है। वहीं काउंटिंग और नतीजे 20 नवंबर से पहले ही आ जाएंगे। साल 2020 में भी बिहार की 243 सीटों के लिए तीन फेज में चुनाव हुए थे। इनमें 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर, 3 नवंबर को 94 सीटों पर और 7 नवंबर को 78 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, जबकि नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए गए थे। वहीं साल 2015 में पांच फेज में वोटिंग कराई गई थी। बिहार के चुनावी रण में इस बार एनडीए और इंडिया ब्लॉक आमने-सामने होंगे। वहीं प्रशांत किशोर इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का खेमा एक और कार्यकाल की उम्मीद में है। वहीं राजद के नेतृत्व वाला विपक्षी खेमा कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर उन्हें सत्ता से बेदखल करने की कोशिशों में जुटा है।

बहरहाल, आगामी चुनाव को लेकर हलचल तेज है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस वक्त चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी बिहार के सभी 243 विधानसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन पर बनी फिल्म को लोगों को दिखाएगी। इसी को लेकर बीजेपी ने 'चलो जीते हैं' रथ को पटना से रवाना किया है। चुनाव को देखते हुए मिशन बिहार को देखते हुए इसे बीजेपी का नया अभियान बताया जा रहा है। दरअसल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। बीजेपी इसे सेवा पखवाड़ा के तौर पर मना रही है। बिहार बीजेपी

ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर अपने इस अभियान की जानकारी दी है। बीजेपी ने लिखा, सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत हर विधानसभा क्षेत्र तक जाने के लिए गांधी मैदान, पटना से "चलो जीतें हैं" अभियान के तहत 243 सेवा रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये सेवा रथ केवल वाहनों का काफिला नहीं हैं, बल्कि यह संगठन के उस विचार का प्रतीक हैं, जिसमें हर नागरिक तक सेवा और समर्पण का संदेश पहुँचाने का संकल्प है। आने वाले दिनों में ये रथ बिहार के हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले तक जाकर जनता को यह अहसास कराएँगे कि राजनीति का असली उद्देश्य सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि समाज की सेवा और अंतिम व्यक्ति तक बदलाव पहुँचाना है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी बचपन और संघर्षों पर आधारित फिल्म "चलो जीते हैं" भी बिहार की सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शित की जाएगी। यह फिल्म हर नागरिक को यह सिखाएगी कि कठिनाइयों से जूझकर भी सेवा, संघर्ष और संकल्प की राह चुनने वाला ही समाज का सच्चा सेवक होता है। भारतीय जनता पार्टी का यह अभियान समाज में नई सोच और नई ऊर्जा भरने वाला है। दूसरी तरफ जदयू ने अपनी 50 विधानसभा सीटों के लिए खास रणनीति बनायी है। इन सीटों को जीतने के लिए पार्टी ने सभी पदाधिकारियों व प्रकोष्ठों को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। इनमें से अधिसंख्य वे सीटें हैं, जिनपर पिछली बार उसके उम्मीदवारों की साजिश तथा भीतरघात से हार हुई थी। पार्टी ने कई स्तरों पर समीक्षा के बाद इन सीटों की पहचान की है। 2020 के विस चुनाव में जदयू के लिए अपने ही पुराने सहयोगी चिराग पासवान की लोजपा और उपेन्द्र कुशवाहा की रालोसपा ने कई सीटों पर हार का रास्ता प्रशस्त किया। दोनों ने जदयू के आधारवोट में सेंधमारी की थी। इससे जदयू को नुकसान हुआ था। ऐसी सीटों की संख्या 40 से अधिक है। इस समय बदली परिस्थिति में चिराग पासवान और उपेन्द्र कुशवाहा दोनों जदयू के सहयोगी दल हैं और एनडीए के घटक दल हैं। ऐसे में आधारवोट में सेंधमारी का तो खतरा नहीं है, लेकिन इन सीटों पर पुराने सहयोगियों के बागी होकर मैदान में उतरने का खतरा अवश्य है। लिहाजा, पार्टी इनके लिए अपने स्तर से कोई कोताही नहीं करना चाहती। वही पिछले दिनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा व प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने संगठन की बैठक में सभी सीटों को लेकर प्रदेश पदाधिकारियों को टास्क सौंपा। इसके बाद प्रदेश कमेटी ने उन सीटों की पहचान शुरू की। पार्टी ने हर बूथ पर 10-10 लोगों को तैयार करने की योजना पर काम किया, लेकिन बाद में इसका स्वत: विस्तार हो गया। पार्टी का दावा है कि हर बूथ पर उसने लक्ष्य से अधिक लोग तैयार किये हैं। हर प्रकोष्ठ की अपनी तैयारी है ताकि एनडीए जीत सुनिश्चित की जाए। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हमने कुछ सीटों की पहचान कर वहां अधिक ध्यान देने की योजना बनायी है। पार्टी कार्यकर्ताओं को कई जिम्मेवारी दी गयी है। यहां बूथ मैनेजमेंट पर सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है। बूथ के हर लोगों से संपर्क किया जा रहा है। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदाताओं से बेहतर समन्वय स्थापित कर काम करने को कहा गया है। वही पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी कहते हैं कि पिछला विधानसभा चुनाव अब हमारे लिए बीती बात है। हम आगे बढ़ चुके हैं। पार्टी हर सीट पर मेहनत कर रही है। कुछ सीटों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है और हम ऐसा कर भी रहे हैं। इस बार सहयोगी दलों के साथ एनडीए एकजुट है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई विवाद नहीं। सब मिलकर लड़ेंगे। हमारी सम्मलित मेहनत का लाभ पूरे एनडीए को होगा।

संजय झा

उमेश कुशवाहा

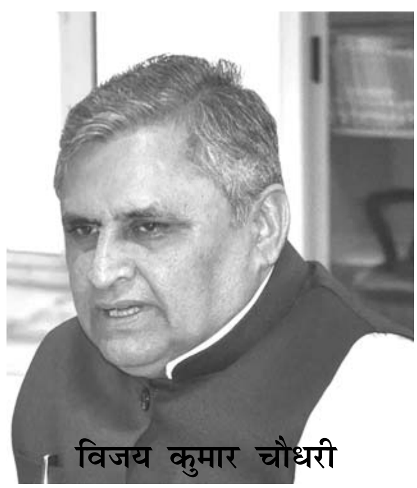
विजय कुमार चौधरी

परिणाम एनडीए के पक्ष में होगा। सबकी सीटें बढ़ेंगी।

लब्बोलुआब है कि एक तरफ एनडीए ने चुनाव को लेकर पूरा पोर्टफोलियो तैयार कर काम कर रही है। ऐसे में आरजेडी की भी तैयारी जोरो पर है। बीते माह एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा बनाकर राहुल गांधी और तेजस्वी ने जनता के बीच 'वोटर अधिकार यात्रा' की थी और अब एक बार फिर से तेजस्वी जनता के बीच एनडीए के किए कार्यो को विफल बताने को लेकर 'बिहार अधिकार यात्रा' कर रहे हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने 'बिहार अधिकार यात्रा' की शुरुआत कर दी है। इस यात्रा के जरिये वे उन जिलों तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर निकले हैं, जो अब तक उनकी 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान छूट गए थे। तेजस्वी ने इस मौके पर कहा कि यह यात्रा सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि बेरोजगार नौजवानों, किसानों, मजदूरों और आम जनता की यात्रा है। उन्होंने कहा कि "आज से हम लोग 'बिहार अधिकार यात्रा' के लिए निकल रहे हैं और बाकी के जिले जो छूट गए थे उन्हें हम कवर कर रहे हैं। नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी को हटाने के लिए, किसान व मजदूर के सम्मान के लिए, मां-बहनों की सुरक्षा के लिए और बिहार में कारखाने और उद्योग लगाने के संकल्प के साथ हम इस यात्रा पर निकले हैं"। तेजस्वी ने बताया कि यात्रा का पहला कार्यक्रम जहानाबाद में हुआ और उसके बाद नालंदा में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया।

गौरतलब है कि तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से हुई है और इसका समापन वैशाली में होगा। 5 दिन की यात्रा में तेजस्वी यादव का प्रदेश के 10 जिलों जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली को कवर करेंगे। बता दें कि तेजस्वी यादव की यात्रा का आगाज जहानाबाद से हुआ है। यह आरजेडी का मजबूत गढ़ माना जाता है। इस जिले में जहानाबाद, मकदूमपुर और घोसी आती हैं। इन सभी विधानसभा सीटों पर महागठबंधन का दबदबा था। दो सीटों पर आरजेडी ने बाजी मारी थी और एक सीट पर सीपीआई एमएल ने जीत दर्ज की थी। जहानाबाद विधानसभा सीट पर आरजेडी के सुदय यादव 33,902 वोटों से जीते थे। वहीं, मकदूमपुर सीट से आरजेडी के सतीश कुमार ने 22,565 वोटों से जीत हासिल की और घोषी से रामबाली यादव विनर रहे थे। वही बिहार की राजधानी पटना की 14 सीटों की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल ने 6 सीटों पर बाजी मारी थी और 2 सीटों पर माले और एक पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। मोकामा सीट आरजेडी के अनंत सिंह ने जीती थी। जीत का मार्जिन था 35,757 वोट। वहीं मसौढ़ी से राष्ट्रीय जनता दल की रेखा देवी चुनाव जीती थीं। जीत का मार्जिन 32,227 वोट था। वैशाली जिले की तीन विधानसभा सीटों पर आरजेडी का कब्जा है। महुआ से मुकेश कुमार रोशन 13,687 वोटों से जीते थे। वहीं राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव 38,174 वोटों से जीते थे। महनार सीट से बीना सिंह 7,947 वोटों से जीती थीं। समस्तीपुर जिले में 10 सीटें आती हैं। इसकी 10 में से पांच सीटों पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी। समस्तीपुर विधानसभा सीट पर आरजेडी के अख्तरुल इस्लाम ने 4,714 वोटों से जीत दर्ज की थी। वहीं मोरवा की सीट से आरजेडी के रनविजय साहू ने 10,671 वोट से जीत हासिल की थी। सबसे

सुदय यादव

सतीष कुमार

रामबाली यादव

अनंत सिंह

रेखा देवी

मुकेश कुमार रोशन

तेजस्वी प्रसाद यादव

बीना सिंह

अख्तरूल इस्लाम

रणविजय साहू

RJD

आलोक कुमार मेहता

तेजप्रताप यादव

राकेश कुमार रौशन

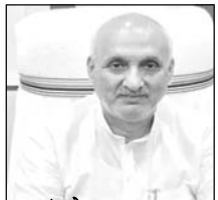
चंद्रशेखर यादव

चंद्रहास चौपाल

युसूफ सलाउद्दीन

ज्यादा वोट मार्जिन का अंतर तो उजियारपुर में देखने को मिला था। यहां पर आरजेडी के आलोक कुमार मेहता ने 23,268 वोटों से जीत दर्ज की थी। इसमें से एक सीट हसनपुर से तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव के पास भी थी। वह 21,139 वोटों से जीते थे। वही नालंदा जिला अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती हैं। यहां पर बेहद ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला था। आरजेडी को इस जिले में केवल इस्लामपुर विधानसभा सीट ही मिली थी। इस सीट पर राकेश कुमार रौशन ने 3,698 वोटों से जीत दर्ज की थी। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। वहीं बात अब अगर बेगूसराय जिले की करें तो यहां पर मुकाबला टक्कर का था। 7 विधानसभा सीटों में से आरजेडी के पास दो सीटें और सीपीआई के पास दो सीटें हैं। बाकी बची हुई तीन सीटों में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया और एक पर लोजपा ने जीत दर्ज की। मधेपुरा जिले में चार विधानसभा सीटे आती हैं। इसमें से दो सीटें आरजेडी के खाते में गई थीं। मधेपुरा से आरजेडी के नेता चंद्रशेखर यादव ने 15,072 वोट से जीत दर्ज की थी। 2020 के चुनाव में सिंहेश्वर सीट से आरजेडी के चंद्रहास चौपाल ने जदयू के रमेश ऋषिदेव को करीब मुकाबले में मात दी थी। 5573 वोटों से जीत दर्ज की थी। वहीं यादव बहुल सहरसा जिले के 4 विधानसभा में एक पर राष्ट्रीय जनता दल जीता था। सुपौल में तो पार्टी का खाता तक नहीं खुल सका था। खगड़िया जिले की चार विधानसभा सीटों में से दो पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी। यहां पर यादव, कुशवाहा, मल्लाह और मुसलमान निर्णायक फैक्टर हैं। सहरसा जिले की चार विधानसभा सीटों में से महज एक पर ही आरजेडी ने कब्जा जमाया था। सिमरी बख्तियारपुर सीट पर आरजेडी नेता युसूफ सलाउद्दीन जीते थे। यहां पर तेजस्वी यादव अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सनद् रहे कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार के जिन 10 जिलों से होकर गुजरेंगे, उनमें 66 विधानसभा सीटें आती हैं। ये बिहार की कुल 243 सीटों का 27 फीसदी होता है। 2020 में इन 66 सीटों पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच लगभग बराबर की लड़ाई थी। सुपौल जिले में महागठबंधन का खाता नहीं खुला था तो जहानाबाद में एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली थी। 2020 के चुनावी लिहाज से देखें तो दस जिलों की 66 सीटों में से एनडीए 34 सीटें जीतने में कामयाब रही थी तो महागठबंधन 32 सीटें जीती थी। अलग-अलग राजनीतिक दलों के नजरिए से देखें तो जेडीयू 19 सीटें, बीजेपी 15 और एक सीट एलजेपी ने जीती थी, जो बाद में जेडीयू में शामिल हो गए थे। महागठबंधन ने 32 सीटें जीती थीं, जिसमें 23 सीटें आरजेडी, 3 कांग्रेस और छह सीटें लेफ्ट पार्टी जीती थीं। खैर, 'बिहार अधिकार यात्रा' के दौरान तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है। उन्होंने दावा किया कि जिस भी जिले और गांव में वे जा रहे हैं, वहां लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और अपराध की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि बिहार को भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त सरकार दी जाए। राजद नेता ने आगे कहा कि यह यात्रा केवल राजनीतिक संदेश भर नहीं है बल्कि जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों की आवाज है। उन्होंने इसे नौजवानों की बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों और मजदूरों के सम्मान और उद्योग-कारखानों की स्थापना की दिशा में बड़ा अभियान बताया। उनके अनुसार, बिहार में आज भी विकास और रोजगार का अभाव सबसे बड़ी समस्या है और इसी मुद्दे को लेकर वे जनता के बीच जा रहे हैं। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि राज्य की मौजूदा सरकार पूरी तरह विफल है और जनता इससे त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा, "ये सरकार लाठी-डंडे की सरकार है। जनता कह रही है-'2025! बहुत हुए नीतीश' लोग अब बदलाव चाहते हैं और यह बदलाव निश्चित तौर पर होगा"। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रतिबद्धता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नीतीश ने हाल ही में एनडीए में बने रहने की बात कही है, लेकिन यही नीतीश पहले महागठबंधन के साथ साझा रैली कर चुके थे। उसी पूर्णिया में उन्होंने हमारे साथ भी रैली की थी और वही बातें उस समय भी कह रहे थे जो कल कह रहे थे। अब उन्हें इंडया गठबंधन में शामिल कौन कर रहा है? असल में तो भाजपा के लोग ही उन्हें भगाना

चाहते हैं। हम उनका सम्मान करते हैं लेकिन सच्चाई यह है कि वे बिहार संभालने की स्थिति में नहीं हैं।

बहरहाल, राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा से बिहार कांग्रेस में एक नई जान फूंक दी है। अब उसी तर्ज पर तेजस्वी यादव भी अपनी 'बिहार अधिकार यात्रा' के जरिए आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने की रणनीति अपनाए हैं। यही वजह है कि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी के यात्रा का संदेश सिर्फ पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भेजा गया है। तेजस्वी अपनी यात्रा के जरिए एक तरफ जहाँ अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ-साथ जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी नेता संजय यादव कहते हैं कि राहुल गांधी के साथ जो यात्रा थी, वो एसआईआर के मुद्दे पर थी। वह वोटर अधिकार यात्रा थी और अब तेजस्वी बिहार के अधिकार के लिए यात्रा पर निकले हैं। संजय कहते हैं कि तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के दौरान किसान, नौजवान, महिलाएँ, बुजुर्ग और रोजगार के मुद्दे को उठाएंगे और लोगों के साथ संवाद करेंगे। चुनाव के दौरान हर पार्टी अपने लिहाज से रणनीति बनाती है, उसी तरह आरजेडी ने अपनी रणनीति बनाई है। तेजस्वी का यह कदम आरजेडी की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तेजस्वी अपने पिता आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तरह जनता से सीधे तौर पर संवाद और उनसे जुड़ना चाहते हैं। लालू यादव भी हमेशा यात्राओं और

रैलियों के जरिए लोगों से सीधे संवाद करते थे। तेजस्वी की यह यात्रा लालू की उस विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। आरजेडी ने तेजस्वी की यात्रा को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने सभी जिलाध्यक्षों और विधायकों को साफ निर्देश दिया है कि वे तैयारी में कोई कसर न छोड़ें। यात्रा जिन-जिन विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी, वहाँ पर भीड़ जुटाएँ ताकि तेजस्वी यादव जनता से सीधे संवाद कर सकें। खास बात यह होगी कि हर इलाके के लिए एक ही जगह पर कार्यक्रम तय किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होकर यात्रा का हिस्सा बन सकें। विश्लेषकों के अनुसार तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा के सियासी मकसद को बारिकी से समझना होगा। इसे समझने के लिए जान लें कि तेजस्वी यादव अपनी यात्रा का आगाज जहानाबाद से किया, जो आरजेडी का मजबूत गढ़ माना जाता है। पिछले चुनाव में एनडीए का यहां सफाया कर दिया था। इसके बाद नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा जिले से होकर गुजरेंगे तो गिरिराज सिंह के गढ़ बेगूसराय और पप्पू यादव के मधेपुरा और सुपौल की यात्रा भी करेंगे। तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा के दौरान महागठबंधन के इलाके को मजबूत बनाए रखने के साथ कमजोर गढ़ में सियासी आधार बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। नालंदा, समस्तीपुर, सुपौल और मधेपुरा जैसे इलाके बीजेपी और जेडीयू का मजबूत गढ़ माना जाता है। इस तरह से एक बात साफ है कि तेजस्वी 'बिहार अधिकार यात्रा' के जरिए अपने कमजोर माने जाने वाले गढ़ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर आरजेडी के पक्ष में सियासी माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। जातीय समीकरण के लिहाज से भी देखें तो यादव, भूमिहार और अतिपिछड़ी जातियों का इन इलाकों में दबदबा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह यात्रा न सिर्फ राजद कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेगी बल्कि तेजस्वी यादव को पूरे बिहार में एक मजबूत विपक्षी चेहरा स्थापित करने का

अवसर भी देगी। बेरोजगारी, महंगाई, कानून-व्यवस्था और विकास की कमी जैसे मुद्दों को जनता के बीच ले जाकर वे एनडीए सरकार की नीतियों को सीधे चुनौती दे रहे हैं।

गौरतलब है कि महागठबंधन में शामिल घटक दलों में सीट बंटवारे को लेकर खींचातानी तेज हो गई है। विपक्षी गठबंधन में शामिल सभी घटक दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस बीच राजद नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक बयान ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। उन्होंने मंच से सीधे तौर पर कहा कि आप समझ लीजिए कि बिहार की 243 सीटों पर तेजस्वी चुनाव लड़ रहा है। तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर के कांटी हाई स्कूल में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया और अपने पिता लालू यादव की उपलब्धियों को गिनवाया। इसके बाद आखिर में उन्होंने कहा, हम फिर आएंगे। आप सब यह समझ लीजिए कि बिहार की हर सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ रहा है। मेरी आपसे अपील है कि आप तेजस्वी के नाम पर वोट करें। तेजस्वी बिहार को आगे ले जाने के लिए काम करेगा। तेजस्वी यादव ने खासतौर पर मुजफ्फरपुर की सीट का भी उदाहरण दिया, जहां से कांग्रेस का विधायक है। उनके इस बयान के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का एक तरीका भर है या फिर राजद की तरफ से कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति है। तेजस्वी यादव का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राजद और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर तनाव की खबरें चल रही हैं। इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को पीएम फेस बताया था। लेकिन राहुल गांधी से मुख्यमंत्री के चेहरे के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने इस सवाल को टाल दिया था। राहुल गांधी के इस रुख से राजद सुप्रीमो लालू यादव भी नाराज बताए जा रहे हैं। खबर है कि लालू यादव ने सीट बंटवारे की कमान खुद संभाल ली है और वो कांग्रेस को 50-55 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं हैं। तेजस्वी यादव का यह बयान इन अटकलों को और भी मजबूत करता है। ऐसा लगता है कि राजद कांग्रेस को यह साफ संदेश देना चाहती है कि बिहार में महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव ही हैं और इस पर उन्हें कोई समझौता मंजूर नहीं है। तेजस्वी यादव ने जिस अंदाज में मुजफ्फरपुर की सभा में खुद को केंद्र में रखा, उससे एक चीज साफ है कि वो 2025 की लड़ाई में वह ड्राइविंग सीट चाहते हैं। राजद बिहार में खुद को बड़े भाई की भूमिका में देखता है और उनकी ये चाहत होती है कि कांग्रेस और दूसरे दल उनके नेतृत्व को बिना किसी शर्त के स्वीकार करें। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहकर तेजस्वी ने यह संकेत दिया है कि महागठबंधन में राजद ही टर्म डिक्टेट करेगा।

लब्बोलुआब है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर एक राय बनती नहीं नजर आ रही है। विपक्षी गठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल राजद जहां तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस ने इस पर चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने 10 सितंबर को सीएम फेस के सवाल पर कहा कि

कृष्णा अल्लावरू

बिहार का सीएम जनता तय करेगी। इससे पहले राहुल गांधी भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी के सीएम कैंडिडेट वाले सवाल से कन्नी काट चुके हैं। दिल्ली में 10 अगस्त को बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान ने संयुक्त तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कृष्णा अल्लावरू से पत्रकारों ने महागठबंधन के सीएम चेहरे पर सवाल पूछा तो अल्लावरू पहले तो यह सवाल टाल गए, फिर हंसते हुए कहा कि बिहार का सीएम बिहार की जनता तय करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कृष्णा अल्लावरू ने कांग्रेस के लिए सम्मानजनक और मजबूत सीटों पर दावा किया। उन्होंने कहा, गठबंधन में नए साथी के आने के बाद हर एक पार्टी को अपने हिस्से की कुछ सीटें छोड़नी होंगी। सीट बंटवारे में संतुलन भी होना चाहिए। हर प्रदेश में अच्छी और खराब सीटें होती हैं। ऐसा नहीं हो कि किसी एक को सभी अच्छी सीटें मिले, दूसरे को खराब। इस पर बातचीत चल रही है। बिहार कांग्रेस प्रभारी ने पशुपति कुमार पारस की पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को महागठबंधन में शामिल किए जाने पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सकारात्मक बातचीत चल रही है और बहुत जल्द इस पर औपचारिक घोषणा हो सकती है। सीट शेयरिंग को लेकर अल्लावरू ने बताया कि कांग्रेस ने अपनी लिस्ट राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे को सौंप दी है। इस मुद्दे पर समन्वय समिति में चर्चा जारी है। उन्होंने भरोसा जताया कि जल्दी ही सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला हो जाएगा। वही बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अलग से अपना कोई घोषणापत्र नहीं निकालेगी। अल्लावरू ने बताया कि मेनिफेस्टो महागठबंधन की ओर से संयुक्त रूप से जारी किया जाएगा। महागठबंधन की कॉर्डिनेशन कमेटी इस पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि घोषणापत्र लेकर कांग्रेस हर घर अधिकार यात्रा निकालेगी और सबको इसके बारे में जानकारी देगी। वही कृष्णा अल्लावरू ने महागठबंधन में नए साथियों की एंट्री का स्वागत किया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में जगह देने या नहीं देने का फैसला लालू यादव के पाले में डाल दिया है। कांग्रेस नेता ने साफ कहा कि औवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल करने की चर्चाओं से कांग्रेस का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने को लेकर लालू यादव को पत्र लिखा है, इसलिए इस पर वही स्पष्टीकरण देंगे, कांग्रेस का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरी तरफ राजद साफ कर चुकी है कि ओवैसी की महागठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में तेजस्वी यादव का खेल खराब करने वाले असदुद्दीन ओवैसी इस बार हर हाल में राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन करना चाहते हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान 11 सितंबर को अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़े लेकर लालू यादव के आवास पर पहुंच गए और 'लालू-तेजस्वी कान खोलो, गठबंधन के लिए दरवाजे खोलो' जैसे नारे लगाने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अख्तरूल ईमान ने इससे पहले लालू यादव को पत्र लिखकर एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल करने की मांग की थी, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद अख्तरुल ईमान 11 अगस्त को अपने नेताओं और समर्थकों के साथ लालू यादव से मिलने पटना के 10 सर्कुलर रोड

स्थित लालू-राबड़ी आवास पहुंच गए। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बाहर ही रोक लिया। ये लोग लालू यादव से मिलकर गठबंध न पर बात करना चाहते थे। एआईएमआईएम के नेता अपने हाथों में बड़े-बड़े पोस्टर लेकर पहुंचे थे। वही एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वोटों का बिखराव ना हो, इसके लिए वो लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एआईएमआईएम इंडिया गठबंधन से जुड़े। उन्होंने बताया, इसको लेकर लालू यादव और इंडिया गठबंधन के घटक दलों को पत्र भी लिखा गया, लेकिन उस पर गौर नहीं किया गया। हम लोग चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में वोटों का बंटवारा न हो इसलिए जिस पार्टी ने हमारे चार विधायकों को तोड़ा, उसके साथ भी दिल पर पत्थर रखकर गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इंडिया गठबंधन से उनकी सिर्फ तीन मांग है-उनको 6 सीट दी जाए, साथ ही सरकार बनने पर सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हो और विशेष पैकेज दिया जाए। इसके अलावा दलित और अल्पसंख्यकों के लिए आबादी के हिसाब से आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए। हालांकि तेजस्वी यादव मीडिया से बातचीत में कई बार बता चुके हैं कि उन्हें एआईएमआईएम की तरफ से आए पत्र की कोई जानकारी नहीं है। अख्तरुल ईमान ने उन पर तंज करते हुए कहा कि बड़े लोगों की चमड़ी मोटी होती है। इसलिए हम ढोल नगाड़े के साथ उनके घर के बाहर ये बताने आए हैं कि एआईएमआईएम विधानसभा चुनाव में वोटों का बिखराव रोकने के लिए इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहती है। एआईएमआईएम के बिहार प्रमुख ने फरवरी 2005 में हुए विधानसभा का जिक्र करते हुए कहा कि उस विधानसभा चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला था। रामविलास पासवान को 29 सीटें मिलीं थीं। उस समय पासवान ने लालू यादव को विकल्प दिया था कि किसी अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो वह उन्हें समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन लालू यादव को मंजूर नहीं हुआ। ईमान ने आगे कहा कि आज वैसी ही स्थिति है। लालू यादव को बीजेपी की सरकार मंजूर है, लेकिन इंडिया गठबंधन में एआईएमआईएम नहीं। बता दें कि साल 2020 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल इलाके की मुस्लिम बहुल पांच सीटों पर जीत दर्ज की थी। अख्तरुल ईमान अमौर से विधायक बने थे, जबकि बायसी से रुकनुद्दीन अहमद, कोचाधामन से इजहार असफी, बहादुरगंज से अंजाम नईमी और जोकीहाट से शाहनवाज आलम विधायक बने थे। हालांकि कुछ महीने बाद अख्तरुल ईमान को छोड़कर सभी चारों विधायक राजद में शामिल हो गए थे।

बहरहाल, बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान में ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन चुनावी मैदान में उतरने के लिए कमर कस चुके दोनों प्रमुख गठबंधनों में सीट शेयरिंग को लेकर अबतक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। बात एनडीए की करें या फिर महागठबंधन की, दोनों खेमों का हाल एक जैसा ही नजर आ रहा है। एनडीए में सीट बंटवारे से पहले एक तरफ जहां छोटे घटक दलों के बीच खींचतान दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में वोटर अधिकार यात्रा के बाद आरजेडी और कांग्रेस अपने-अपने सिंगल प्लान को एक्टीवेट कर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग

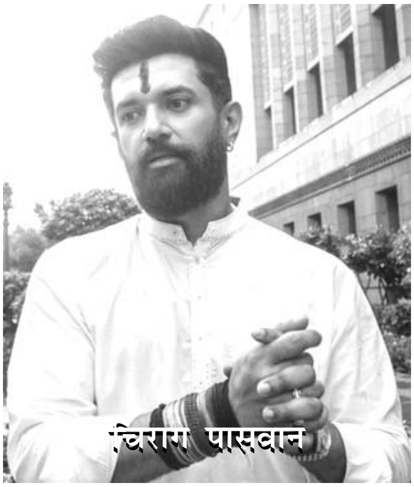

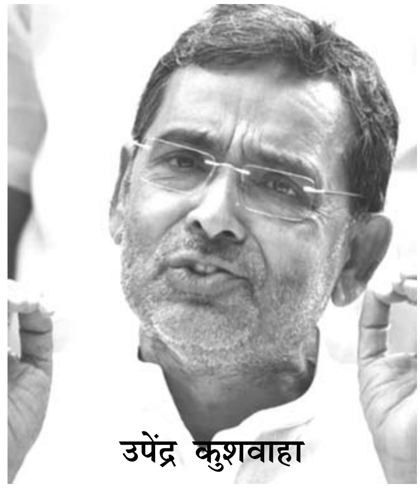

को लेकर अबतक बैठकों का दौर भी शुरू नहीं हुआ है, जबकि महागठबंधन के घटक दलों के बीच बैठकें तो हो रही हैं लेकिन कोई फॉर्मूला सामने नहीं आ पा रहा। सबसे पहले बात एनडीए गठबंधन की करते हैं। एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, इसे लेकर तस्वीर साफ है। चुनावी तैयारी को लेकर एनडीए का विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलनों का दौर भी जारी है। एनडीए के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि चुनावी बिगुल बजने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग-अलग कार्यक्रमों से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं में जोश भी भर रहा है, लेकिन बात अगर सीट शेयरिंग को लेकर करें तो अबतक एनडीए में घटक दलों के बीच बैठकों का दौर भी शुरू नहीं हो पाया है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जिस फॉर्मूले की चर्चा सियासी गलियारे में है उसके मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के बराबर-बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। चर्चा ये भी है कि ये दोनों बड़े घटक दल सौ-सौ से ज्यादा सीटों पर अपना उम्मीदवार देंगे। एनडीए में शामिल चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेन्द्र कुशवाहा की पार्टी को भी उनकी ताकत के हिसाब से सीटें दिए जाने की चर्चा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा सीट बंटवारे पर अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं हैं, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी ने शुरुआती दौर में 40 सीटों पर दावेदारी की थी। चिराग पासवान चाहते हैं कि उनकी पार्टी की सीटों की संख्या कम से कम इतनी हो की एवरेज स्ट्राइक रेट से भी वो इस स्थिति में रहें कि बिहार की सियासत में उनकी अहमियत बनी रहे। हालांकि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर जिस फॉर्मूले की चर्चा सियासी गलियारे में है उसके मुताबिक चिराग पासवान की पार्टी को 20 के आसपास सीटें दी जा सकती हैं। संभव हो कि इतनी सीटों पर चिराग को राजी करवाने के लिए बीजेपी

कोई और ऑफर भी दे। एनडीए के अंदर सीट बंटवारे पर फंसे पेंच को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चिराग की ही हो रही है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान किस तरह एनडीए से बाहर रहकर मैदान में उतरे थे और इसका खामियाजा जेडीयू को उठाना पड़ा था, यह शायद ही कोई भूला है। हालांकि बीते दिनों जे.पी. नड्डा के बिहार दौरे पर बात बनती नजर नहीं आयी थी किन्तु अमित शाह के आने के बाद नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच बंद कमरे में काफी देर चर्चा हुई, कयास लगाये जा रहे हैं की सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। वही बिहार में महागठबंधन की तरफ से मिल रही चुनौतियों को देखते हुए बीजेपी और जेडीयू दोनों में से कोई भी यह नहीं चाहेगा कि चिराग एक बार फिर से 2020 से वाली राह पर जाएं। वही चिराग ने एनडीए के अंदर जो प्रेशर पॉलिटिक्स अपनाई है शायद उसी का असर है कि अब जीतन राम मांझी भी अपनी पार्टी की तरफ से मुखर होकर दावेदारी कर रहे हैं। मांझी ने भी अपनी पार्टी के लिए 15 से 20 सीटों की दावेदारी मीडिया के जरिए सामने रख दी है। मांझी इसके लिए जो तर्क दे रहे हैं वह उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के लिए मिलने वाले वोट परसेंटेज से जुड़ा है। जीतन राम मांझी ने ऐलान कर दिया है कि अगर उम्मीद के मुताबिक के सीटों की संख्या नहीं हुई तो उनकी पार्टी बिहार चुनाव में कम से कम 100 सीटों पर उम्मीदवार देगी। चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी इन दोनों के बयानों पर फिलहाल जेडीयू और बीजेपी ने चुप्पी साथ रखी है। एनडीए के दोनों बड़े घटक दलों के नेता यही कह रहे हैं कि सीट बंटवारे को लेकर हमारे गठबंधन में कोई रार नहीं है और फैसला बड़ी आसानी से हो जाएगा। जाहिर है एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर भले ही बैठकों का दौर खुले तौर पर नहीं हो रहा हो, लेकिन अंदरखाने में घटक दलों के दावे और उन्हें फॉर्मूले पर मनाने को लेकर बातचीत का दौर जारी है। बीजेपी की कोशिश यह नजर आती है कि घटक दलों के साथ साझा बैठक करने की बजाय अलग-अलग सहयोगी दलों के नेताओं से बातचीत कर सहमति बनाई जाए। पर्दे के पीछे जब सहमति बन जाए तो फिर सीट बंटवारे के फॉर्मूले के साथ साझा बैठक और फिर साझा ऐलान हो। चर्चा यह भी है कि एनडीए में कई सीटों पर एडजस्टमेंट को लेकर

मुकेश सहनी

दीपांकर भट्टाचार्य

डी. राजा

पशुपति कुमार पारस

भी पेच फंसा हुआ है।

दूसरी तरफ सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के अंदर की कहानी भी कम पेचीदा नहीं है। बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से कराए गए एसआईआर को मुद्दा बनाते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अन्य सहयोगी दलों के नेताओं के साथ मिलकर भले ही वोटर अधिकार यात्रा की हो, लेकिन सीट शेयरिंग पर महागठबंधन को गाड़ी भी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही। बिहार विधानसभा चुनाव में एकजुटता और एनडीए को पटखनी देने के मकसद से महागठबंधन ने शुरुआती दौर से गजब कमिटमेंट दिखाया। महागठबंधन की शुरुआती बैठकों के बाद कॉर्डिनेशन कमेटी समेत अन्य कमेटियों का गठन कर दिया गया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कॉर्डिनेशन कमेटी का प्रमुख तो बनाया गया लेकिन कांग्रेस तेजस्वी के सीएम कैंडिडेट होने पर ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को अगली बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन राहुल से जब तेजस्वी के सीएम कैंडिडेट होने को लेकर सवाल किया गया तो वह इसे टाल गए। इतना ही नहीं कांग्रेस के जो नेता तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन की बैठकों के बाद मीडिया से बातचीत के लिए मौजूद रहते हैं उन्होंने भी हर बार इस सवाल से कन्नी काटी है। कांग्रेस के नेता लगातार यह कहते रहे हैं कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा यह जनता तय करेगी, हमारा पूरा फोकस चुनाव जीतने पर है। जाहिर है सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला हुए बगैर कांग्रेस तेजस्वी के नाम का ऐलान नहीं होने देना चाहती। तेजस्वी के नाम के ऐलान पर कांग्रेस के नकारात्मक रूप के सियासी कारण भी हो सकते हैं। बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए थे। 5 साल बाद अब महागठबंधन की तस्वीर बदली हुई है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के अलावा पशुपति पारस की आरएलजेपी और हेमंत सोरेन की जेएमएम को भी महागठबंधन में सीटें देनी हैं। इस वजह से आरजेडी के साथ-साथ कांग्रेस को

भी अपनी सीटें कम करनी पड़ सकती हैं। तेजस्वी यादव खुद कह चुके हैं कि उनकी पार्टी पहले से कम सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी, क्योंकि नए सहयोगी दलों को एडजस्ट करना है। कांग्रेस भी इस बात को भली भांति समझ रही है। लेकिन सीट कम होने का सवाल पैदा होते ही कांग्रेस दांवपेच में उतरती दिख रही। जानकार बता रहे हैं कि कांग्रेस 60 से कम सीटों पर तैयार नहीं है। अगर सीटों की संख्या 60 से कम होती है तो कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के बयान के मुताबिक कड़े मुकाबले वाली सीटों पर सिर्फ कांग्रेस के उम्मीदवार ही नहीं बल्कि सहयोगी दलों के भी उम्मीदवारों को मैदान में किस्मत आजमानी चाहिए। वही एनडीए की मजबूत सीटों का बंटवारा सभी सहयोगी दलों के बीच करने की शर्त कांग्रेस ने रख दी है। बीते विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के अंदर 70 सीट लेने वाली कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। इसके बाद आरजेडी की तरफ से कांग्रेस की डिमांड को लेकर सवाल भी खड़े किए गए थे, तब आरजेडी के सीनियर नेताओं ने यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस ने अपनी क्षमता से ज्यादा सीटें लीं। हालांकि कांग्रेस के नेता इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका तर्क है कि बीते विधानसभा चुनाव में 70 में से 22 ऐसी सीटें कांग्रेस को दी गई, जहां पिछले तीन चुनाव से एनडीए ही जीत हासिल करती रही थी। इस बार कांग्रेस का फोकस सिर्फ शहरी विधानसभा सीटों पर नहीं बल्कि ऐसी ग्रामीण सीटों पर भी है जहां उसका प्रदर्शन पहले से सुधर सके। तेजस्वी यादव खुद समझ रहे हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव उनके लिए कितना खास है। कांग्रेस ने भले ही तेजस्वी के नाम पर मुहर नहीं लगाई हो लेकिन तेजस्वी अब नीतीश कुमार को डुप्लीकेट और खुद को ओरिजिनल सीएम बताते हुए दावेदारी कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव ने खुद महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चुप्पी तोड़ी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता ही मुख्यमंत्री बनाती है और सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में कोई कनफ्यूजन नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा, 'हमारे गठबंधन में कोई कनफ्यूजन नहीं है। जनता बदलाव चाहती है। बिहार की मालिक जनता है और वो मुख्यमंत्री बनाती है। अब वो बदलाव चाहती है। आप बिहार के किसी व्यक्ति से जाकर पूछिए या सर्वे कराइए, जवाब मिल जाएगा। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई कनफ्यूजन नहीं है, समय पर

घोषित कर दिया जाएगा।' वाम दलों को भी तेजस्वी के नाम पर कोई एतराज नहीं है। मुकेश सहनी भी तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट बनाए जाने के पक्ष में है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर फंसे पेच ने तेजस्वी के नाम पर आधिकारिक घोषणा को रोक रखा है। मुकेश सहनी ने तो यहां तक कह दिया है कि तेजस्वी के सीएम कैंडिडेट के तौर पर नाम की घोषणा में देरी हुई तो इसका नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है। सहनी एक तरफ जहां तेजस्वी का नाम मुख्यमंत्री के लिए आगे कर रहे हैं तो वहीं खुद को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बता रहे हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जो खींचतान चल रही है उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। वहीं महागठबंधन में कांग्रेस के बाद अब वाम दलों की दावेदारी ने राजद की टेंशन बढ़ा दी है। बिहार में लेफ्ट पार्टियां पिछले विधानसभा चुनाव की सफलता को ध्यान में रखकर उत्साहित हैं और इस बार ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर रही हैं। सीपीआई एमएल (एमएल) ने जहां राजद को 40 सीटों की लिस्ट सौंपी है, वहीं सीपीआई भी इस बार सीटों की संख्या दहाई के आंकड़े तक पहुंचने की कवायद में जुटी है। 8 सितंबर से शुरू हुए सीपीआई के राज्य सम्मेलन में भी पार्टी नेताओं ने मजबूत दावेदारी पेश करने की पुरजोर वकालत की। ज्ञात हो कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में वाम दलों का प्रदर्शन शानदार रहा था। तीनों दलों को मिलाकर 16 सीटों पर जीत मिली थी। इसमें माले ने 19 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें जीतीं, वहीं सीपीआई ने 6 और सीपीआई (एम) ने 4 सीटों पर लड़कर 2-2 सीटों पर जीत दर्ज किया। बछवाड़ा विधानसभा सीट से सीपीआई प्रत्याशी अवधेश राय मात्र 484 वोट से पिछड़ गए, नहीं तो ये आंकड़ा और बेहतर होता। पिछले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन को आधार बनाकर ही वाम दल इस बार ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं।

दिगर बात है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भले ही एक साथ वोटर अधिकार यात्रा की हो लेकिन अब तेजस्वी 16 सितंबर से बिहार अधिकार यात्रा पर अकेले निकल गये हैं। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा उन 13 जिलों से होकर गुजरेगी, जहां वे राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा के दौरान नहीं जा पाए थे। खास बात यह है कि यह पूरी तरीके से आरजेडी की यात्रा होगी। तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी का दमखम दिखाने के लिए इस यात्रा में एक दिन के अंदर दो-दो जिलों में कई जनसभाओं का कार्यक्रम तय कर रखा है। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए कांग्रेस ने महागठबंधन में जिस तरह अपनी ताकत का एहसास कराया है, संभव है कि तेजस्वी अब बिहार अधिकार यात्रा के जरिए यह मैसेज देना चाहें कि बिहार में बड़े भाई की भूमिका आरजेडी की है और सबसे बड़ा जनाधार भी उन्हीं के पास है। हालांकि राहुल गांधी के बिहार दौरे के बाद कांग्रेस का उत्साह भी चरम पर है। कांग्रेस ने अब सिंगल प्लान के तहत अपने नए कैंपेन की रूपरेखा भी तय कर ली है। कांग्रेस अब 'हर घर अधिकार' अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान के तहत कांग्रेस के बड़े से लेकर छोटे नेता तक बिहार के मतदाताओं के घर तक जाएंगे। जिसका मकसद विधानसभा स्तर पर वोटर्स को कांग्रेस के साथ जोड़ना है। इस अभियान के जरिए कांग्रेस अपनी प्रस्तावित 'माई-बहन सम्मान योजना' के लिए हर विधानसभा क्षेत्र से कम से कम 50 हजार भरे हुए आवेदन पत्र लेगी। इस पूरे अभियान के जरिए कांग्रेस की नजर राज्य की महिला वोटर्स पर है। कांग्रेस ने महिला वोट बैंक को साधने के लिए अपने गठबंधन की सरकार बनने पर हर महिला को 2500 रुपये हर महीने देने का वादा किया है। आरजेडी और कांग्रेस का यह सिंगल प्लान एक तरफ जहां महागठबंधन में अपनी-अपनी ताकत दिखाने का तरीका है तो वहीं दूसरी तरफ सीट बंटवारे में अपने दावे को मजबूत करने का जरिया भी है। फिलहाल दोनों गठबंधनों के अंदर जो हालात दिख रहे है वो यही संकेत देते हैं कि पर्दे के पीछे हो या सामने, प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर अभी कई सियासी रंग दिखाएगा। उसके बाद ही सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ होगी।

बिडम्बना देखिए की 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में दिलचस्प माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जो बात निकलकर आयी है, उसमें सबसे अहम बात है कि इस बार एनडीए और इंडिया एलायंस के वैसे उम्मीदवार जो 70 के उम्र पार वाले हैं, उनके टिकट कट सकते हैं। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025

में एनडीए और महागठबंधन के कई उम्रदराज विधायकों को अपना टिकट कटने का डर सता रहा है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल में 70 पार वाले विधायकों की लिस्ट लंबी है। बिहार में मौजूदा 243 विधायकों में विभिन्न दलों के ऐसे 68 विधायक हैं, जिनकी उम्र 65 पार है। वहीं, इनमें 31 की आयु 70 से 80 साल के बीच है। कई-कई बार जनता द्वारा चुनकर आए इन विधायकों पर इस बार तलवार लटकी है। वे खुद संशय में हैं कि पार्टी उन्हें टिकट देगी या नहीं। 2025 के समर में वे मैदान में उतर पाएंगे या नहीं। क्षेत्र में दूसरे कई दावेदार फील्डिंग करते नजर आ रहे हैं। पार्टियों में भी अंदरखाने ऐसे कई विधायकों की जगह युवा, नए तथा दूसरे तेजतर्रार कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाने की चर्चा है। अपनी उम्मीदवारी पर तलवार लटकता देख इनमें से कइयों ने अपने पुत्र-पुत्री को आगे कर दिया है। हालांकि यह तो टिकट बंटवारे के बाद ही पता चलेगा कि पैंसठ-सत्तर पार कितने उम्मीदवार मैदान में फिर उतरने में कामयाब रहे, कितने अपने पुत्र-पुत्रियों को उतार पाए, कितने की सीट किसी और कार्यकर्ता के हाथ चली गई, पर निगाहें टिकी हैं। वैसे, उम्रदराज नेताओं में ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव जैसे भी कई हैं जिनका फिर मैदान में उतरना तय माना जा रहा है। उधर, पार्टियों ने भी उम्रदराज नेताओं की दावेदारी को लेकर फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं किया है। एनडीए के एक शीर्ष नेता ने पूछे जाने पर बताया कि उम्रदराज नेताओं की सीट पर उनकी जीत की संभावना तलाशी जाएगी। भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया, अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। बात 70 पार वाले नेताओं की करें तो भाजपा में इनकी भरमार है। इस पार्टी के दर्जनभर विधायक 70 से 78 साल के बीच के हैं। इनमें मंत्री तथा 8 बार के विधायक डॉ. प्रेम कुमार, 7 बार के विधायक तथा विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से लेकर पूर्व मंत्री तथा पांच बार जीते अमरेन्द्र प्रताप सिंह तक शामिल हैं। दूसरे नंबर पर 8 विधायकों संग राजद, 7 विधायकों के साथ जदयू तीसरे नंबर पर है। इस सूची में इनमें 9 बार जीते हरिनारायण सिंह तो 8-8 बार जीते बिजेंद्र प्रसाद यादव और डॉ. प्रेम कुमार के अलावा कांग्रेस और सीपीआई विधायक भी शामिल हैं। भाजपा में उम्रदराज विधायकों की लिस्ट में छपरा से डॉ. सीएन गुप्ता (78), आरा से अमरेंद्र प्रताप सिंह (78), रामनगर से भागीरथी देवी (75), कुम्हरार से अरुण कुमार सिन्हा (74), बड़हरा से राघवेंद्र प्रताप सिंह (73), राजनगर से रामप्रीत पासवान (72), जमुई से रामनारायण मंडल (72), पटना साहिब से विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव (72), वजीरगंज से वीरेंद्र सिंह (72), गया से डॉ. प्रेम कुमार (70), नरपतगंज से जयप्रकाश यादव (70), बगहा से श्रीराम सिंह (70) शामिल हैं। वही आरजेडी में 70 पार की उम्र वाले विधायकों की सूची में रफीगंज से मो. नेहालुद्दीन (73), सीवान से अवध बिहारी चौधरी (71), रघुनाथपुर से हरिशंकर यादव (70), चेरिया बरियारपुर से राजवंशी महतो (70),

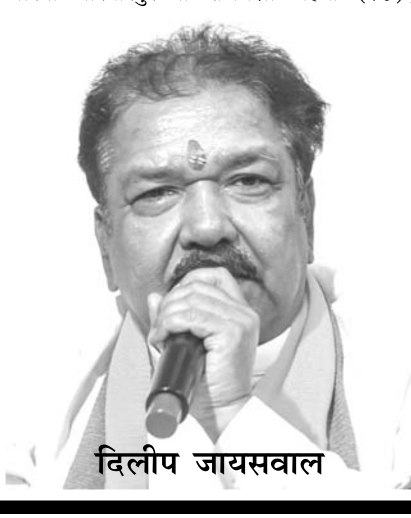
दिलीप जायसवाल

नाथनगर से अली अशरफ सिद्दीकी (71), जगदीशपुर से रामविशुन सिंह (71), कुर्था से बागी कुमार वर्मा (71), फतुहा से डॉ. रामानंद यादव (70) शामिल हैं। जेडीयू में उम्रदराज विधायकों में हरनौत से हरिनारायण सिंह (80), सुपौल से बिजेंद्र प्रसाद यादव (79), बेलदौर से पन्नालाल पटेल (77), निर्मली से अनिरुद्ध प्रसाद यादव (76), महिषी से गुंजेश्वर साह (76), आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव (74), हिलसा से कृष्णमुरारी शर्मा उर्फ प्रेम मुखिया (73) हैं। कांग्रेस के 70 पार वाले विधायकों में महाराजगंज से विजय शंकर दुबे (77), मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह (76 साल), भागलपुर से अजीत शर्मा (71) का नाम है। वही सीपीआई में भी तेघड़ा से रामरतन सिंह (74) का नाम आता है। सनद् रहे कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और माले विधायक दल के नेता महबूब आलम अगले साल 70 के हो जाएंगे। 65 पार वाले विभिन्न दलों के मौजूदा विधायकों में श्रीनारायण प्रसाद, रेणु देवी, प्रमोद कुमार सिन्हा, शशिभूषण सिंह, लालबाबू प्रसाद गुप्ता, विनोद नारायण झा, अरुण शंकर प्रसाद, समीर कुमार महासेठ, भारत भूषण मंडल, मो. आफाक आलम, विजय कुमार खेमका, मिश्रीलाल यादव, मुरारी मोहन झा, बिजेन्द्र चौधरी, रामप्रवेश राय, कुसुम देवी, सुनील कुमार, जनक सिंह, डॉ. रामानुज प्रसाद, वीणा सिंह, अशोक कुमार, विजय कुमार चौधरी, सुरेन्द्र मेहता, ललित नारायण मंडल, भूदेव चौधरी, अजय कुमार सिंह, प्रह्लाद यादव, श्रवण कुमार, ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू, भरत बिंद, जयकुमार मंडल, अनिल कुमार, दामोदर रावत आदि हैं। अब ऐसे उम्रदराज विधायकों की 2025 के चुनाव में दावेदारी खुद को कितना साबित कर पाती है, ये चुनाव बतायेगा। इनकी टिकटे कटती है या पुन: ये चुनावी मैदान में होंगे, बहुत जल्द ये बातें स्पष्ट हो जायेगी किन्तु उम्रदराज नेताओं के टिकट काटे जाने की चर्चा की खबर अभी गर्म है।

सुनील कुमार

सुरेंद्र मेहता

सुमित कुमार सिंह

विदित हो कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 एनडीए और महागठबंधन में कांटे की लड़ाई थी। दोनों गठबंधन के बीच महज 15 सीट और 11 हजार 150 वोट का फासला था। कई विधानसभा सीटों पर भी बेहद करीबी मुकाबला हुआ। उनमें 11 विधानसभा सीटें ऐसी रहीं, जिनमें हार-जीत का अंतर एक हजार वोट से भी कम था। इन सीटों पर 12 वोट से लेकर 951 वोट के अंतर से विजेता चुने गए। इनमें से 6 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी मामूली अंतर से चूक गए। वहीं 5 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों की किस्मत उनसे रूठ गई। हजार से कम अंतर से जीतने वाले तीन नेता तो नीतीश कुमार कैबिनेट की शोभा बढ़ा रहे हैं-शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार। सबसे रोचक मुकाबला रहा नालंदा जिले की हिलसा सीट पर हुआ। यहां से राजद के शक्ति यादव 12 वोट से हार गए, जबकि बरबीघा में कांग्रेस के गजानन मुन्ना शाही 113 वोट से पीछे रह गए। अब एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। चुनाव आयोग सितंबर महीने के अंत तक तारीखों का एलान कर सकता है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा कर चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार इन सीटों पर समीकरण बदलेंगे जहां हार-जीत का अंतर बेहद मामूली रहा था।

पहले बात हिलसा की करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में आने वाले हिलसा विधानसभा सीट पर पिछली बार सबसे रोचक मुकाबला हुआ था। यहां जदयू के कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया ने राजद के अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव को 12 वोटों के अंतर से हराया। प्रेम मुखिया को कुल 61, 848 वोट मिले, जबकि शक्ति सिंह यादव के खाते में 61, 836 वोट आए। इस बार की दावेदारी की बात करें तो राजद की ओर से शक्ति यादव का नाम सबसे आगे है। शक्ति यादव अभी पार्टी के प्रवक्ता हैं और तेजस्वी यादव के करीबी लोगों में शामिल हैं। शक्ति यादव साल 2015 में इस सीट से विधायक भी रहे हैं। इनके अलावा राजद से महेश यादव और सुनील यादव भी टिकट के दावेदारों में हैं। वहीं जदयू की बात करें तो सीटिंग विधायक प्रेम मुखिया इस बार भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं एक नाम नालंदा के वरिष्ठ पत्रकार कमल किशोर प्रसाद का भी है। इस सीट के सामाजिक समीकरण की बात करें तो यहां कुर्मी जाति की आबादी सबसे ज्यादा है। वहीं यादव मतदाता की संख्या उनसे थोड़ी ही कम है। इसके अलावा मुस्लिम और भूमिहार वोटर भी इस सीट पर निर्णायक संख्या में हैं।

दूसरा बरबीघा सीट की बात करें तो 2020 में विधानसभा चुनाव में हिलसा के बाद सबसे करीबी मुकाबला बरबीघा विधानसभा सीट पर हुआ। यहां जदयू के सुदर्शन कुमार ने कांग्रेस के गजानन्द शाही 'मुन्ना' को 113 वोट से हराया था। सुदर्शन कुमार को 39,878 वोट मिले, जबकि गजानन शाही को 39,765 वोट आए। बरबीघा विधानसभा सीट पर भूमिहार जाति के वोटर्स सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा कुर्मी, पासवान और यादवों की संख्या भी अच्छी खासी है। बरबीघा काफी हाई प्रोफाइल सीट है। जदयू के कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी और उनके पिता महावीर चौधरी भी यहां से विधायक रह चुके हैं और इस बार भी उनकी नजर इस सीट पर है। चौधरी अपने दामाद सायन कुणाल

अत्री मुनि उर्फ शक्ति यादव

कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया

सुदर्शन कुमार

गजानन्द शाही

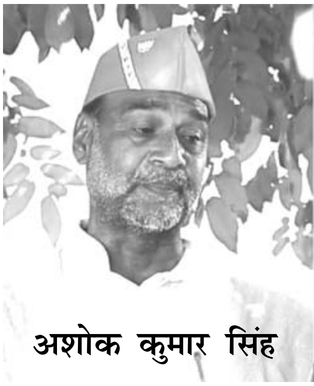
अशोक कुमार सिंह

सतीष कुमार यादव

राजकुमार सिंह

नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह

के लिए जदयू कोटे से ये सीट चाहते हैं, लेकिन उनका काम आसान नहीं है। क्योंकि वर्तमान विधायक सुदर्शन को राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का वरदहस्त प्राप्त है। इस साल की शुरुआत में बरबीघा सीट को लेकर सीएम नीतीश के घर ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच कहासुनी हुई थी। मामला ये था कि अशोक चौधरी बार-बार बरबीघा के दौरे पर चले जाते थे। ये बात ललन सिंह को रास नहीं आई, क्योंकि इस सीट से ललन सिंह के करीबी सुदर्शन सिंह विधायक हैं। सुदर्शन अपने समय के बड़े भूमिहार चेहरे रहे राजो सिंह के पोते हैं। साल 2005 में उनकी हत्या कर दी गई थी। अशोक चौधरी पर भी आरोप लगे थे, लेकिन इसमें कुछ ठोस नहीं निकला और फिर उनकी सुदर्शन से सुलह भी हो गई। जदयू से जहां सुदर्शन एक बार फिर से इस सीट से सबसे बड़े दावेदार हैं। वहीं अशोक चौधरी अपने दामाद को टिकट दिलाने की कोशिश में हैं। कांग्रेस की बात करें तो गजानन शाही 'मुन्ना' फिर से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं बरबीघा की स्थानीय राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले त्रिशूलधारी सिंह भी कांग्रेस में टिकट के लिए हाजिरी लगा रहे हैं। इनके अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सहजानंद सिंह अपने बेटे डॉ. ऋषभ के लिए टिकट के जुगाड़ में हैं। हालांकि उनके लिए पार्टी की बंदिश नहीं है। यानी जहां से मौका मिल जाए ठीक।

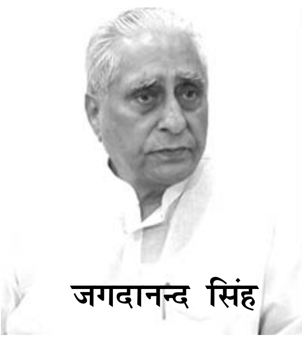
जगदानन्द सिंह

सुधाकर सिंह

अजीत सिंह

तीसरा रामगढ़ सीट की बात करें तो बक्सर के मौजूदा राजद सांसद सुधाकर सिंह कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा सीट से 189 वोट से जीते थे। उन्होंने बसपा के अंबिका सिंह यादव को हराया था। तीसरे नंबर पर रहे बीजेपी प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह भी ज्यादा पीछे नहीं रहे थे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सुधाकर सिंह बक्सर से सांसदी जीत गए। उनकी जगह राजद ने उनके भाई अजीत सिंह को टिकट दिया, लेकिन इस बार बाजी पलट गई। अजीत सिंह तीसरे नंबर पर चले गए। बाजी हाथ लगी पिछली बार तीसरे नंबर पर रहे अशोक कुमार सिंह को। उन्होंने बसपा के सतीश कुमार यादव को 1,362 वोटों से हराया। यह सीट सुधाकर सिंह की पारिवारिक सीट रही है। उनके पिता और राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह इस सीट से 1985 से 2005 तक लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं। साल 2009 में बक्सर से सांसद बनने के बाद जगदानंद सिंह ने ये सीट खाली की। उनके सीट छोड़ने के बाद हुए उपचुनाव में राजद से अंबिका यादव जीते। इसके बाद 2010 विधानसभा चुनाव में राजद उनके बेटे सुधाकर सिंह को टिकट देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया। मगर सुधाकर सिंह को यह बात रास नहीं आई। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का एलान कर दिया। बीजेपी ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए सुधाकर सिंह को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बना डाला, लेकिन बगावत पर उतरे सुधाकर को अपने पिता का साथ नहीं मिला। जगदानंद सिंह ने अपने बेटे के खिलाफ राजद उम्मीदवार अंबिका यादव का प्रचार किया। नतीजा हुआ कि सुधाकर सिंह हार गए और राजद उम्मीदवार की जीत हुई। इसके बाद 2015 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अशोक कुमार सिंह ने अंबिका यादव को हरा दिया। रामगढ़ के जातीय समीकरण की बात करें तो आबादी के हिसाब से राजपूत जाति के वोटर सबसे ज्यादा हैं। वहीं दूसरे नंबर पर मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा यादव और दलित वोटर्स की संख्या भी निर्णायक है। राजद की ओर से इस बार भी अजीत सिंह को ही टिकट मिलने की उम्मीद है। वहीं बीजेपी अपने सीटिंग विधायक अशोक कुमार सिंह के साथ ही जाती दिख रही है। इस सीट पर राजद और बीजेपी का खेल बिगाड़ने वाली बसपा इस बार किस उम्मीदवार पर भरोसा जताती है ये देखना दिलचस्प होगा।

चौथा सीट मटिहानी की बात करें तो साल 2020 में चिराग पासवान ने एनडीए से बगावत करके अकेले 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें से उनको सिर्फ मटिहानी विधानसभा सीट पर सफलता मिली थी। इस सीट से लोजपा के प्रत्याशी राजकुमार सिंह ने जदयू के नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह को 333 वोट से हराया था। तीसरे नंबर पर रहे सीपीआई (एम) कैंडिडेट राजेंद्र कुमार सिंह भी मात्र 765 वोट से ही पीछे रहे। लोजपा के टिकट पर चुनाव जीते राजकुमार सिंह ने चुनावों के तुरंत बाद पाला बदलकर जदयू की सदस्यता ले ली। मटिहानी विधानसभा सीट की स्थापना साल 1977 में हुई। यह बेगूसराय लोकसभा सीट का हिस्सा है। शुरुआती दौर पर यहां कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) का प्रभाव था। सीपीआई ने पहले सात में से पांच चुनाव जीते, बाकी दो बार

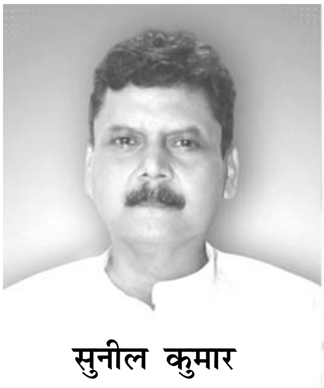
सुनील कुमार

जितेंद्र पासवान

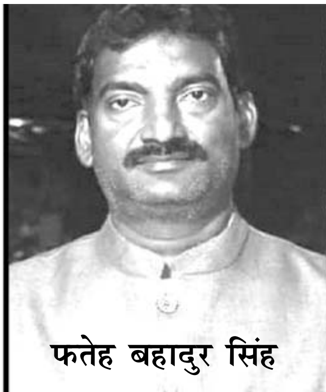
फतेह बहादुर सिंह

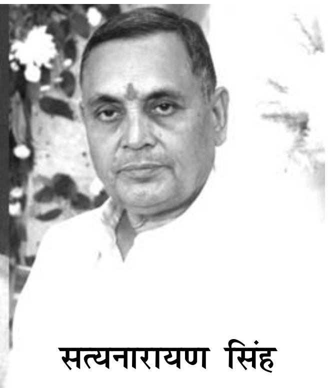
सत्यनारायण सिंह

कांग्रेस का कब्जा रहा, इसके बाद नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने चार बार लगातार इस सीट से जीत हासिल की। जिसमें दो बार उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी (2005 में दोनों बार) के तौर पर और दो बार जदयू (2010 और 2015) के टिकट पर चुनाव लड़ा। मौजूदा विधायक राजकुमार सिंह के पिता कामदेव सिंह भी बेगूसराय की राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं। उन पर कांग्रेस के लिए बूथ लूटने के आरोप लगते रहे हैं। कामदेव सिंह पर गांजे के तस्करी के आरोप भी लगे थे। साल 1980 में पुलिस एनकाउंटर में उनकी मौत हो गई थी। मटिहानी विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर भूमिहार वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके बाद अनुसूचित जाति और मुस्लिम वोटर्स भी अच्छी संख्या में हैं। वहीं पासवान, यादव और कोइरी वोट भी इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मटिहानी सीट से मौजूदा विधायक राजकुमार सिंह जदयू से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। उनके प्रतिद्वंद्वी बोगो सिंह ने इसी अंदेशा के चलते पार्टी बदल ली है, वह अब राजद में आ गए हैं। बोगो सिंह के राजद के साथ जाने से इस सीट को लेकर राजद और सीपीआई (एम) में खींचातानी हो सकती है। उनके प्रत्याशी राजेंद्र प्रसाद सिंह भले ही तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन उनकी हार का अंतर मात्र 765 वोट था। सीपीआई (एम) अपनी मजबूत पकड़ वाली सीट पर दावेदारी शायद ही छोड़े। ऐसे में हो सकता है कि राजद बोगो सिंह को किसी दूसरी सीट पर समायोजित करे।

पांचवें सीट भोरे की बात करें तो भोरे विधानसभा सीट गोपालगंज जिले में आती है। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट से जदयू के सुनील सिंह ने सीपीआई एमएल के जितेंद्र पासवान को 462 वोटों से हराया था। इस सीट पर तीसरे नंबर पर नोटा ने कब्जा जमाया था, जबकि चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदवार पुष्पा देवी चौथे स्थान पर रहीं। भोरे विधानसभा का गठन साल 1957 में हुआ था। साल 1977 में इसे अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित घोषित किया गया। इसके बाद से यहां अब तक 16 बार चुनाव हो चुके हैं। इनमें कांग्रेस ने आठ बार जीत दर्ज की है जबकि जनता दल, बीजेपी और राजद दो-दो बार इस सीट से जीत चुकी है। वहीं जनता पार्टी और जदयू एक-एक बार यहां जीत का स्वाद ले चुकी है। भोरे विधानसभा के जातिगत समीकरण की बात करें तो यहां रविदास (चमार) और कोइरी जाति के वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके अलावा मुस्लिम और यादव वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार नौकरशाही बैकग्राउंड से आते हैं। वो भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी रहे हैं। अगस्त 2020 में रिटायरमेंट के सिर्फ 29 दिन बाद उन्होंने जदयू ज्वाइन कर राजनीति में कदम रखा और कड़े मुकाबले में जितेंद्र पासवान को हराया। सुनील कुमार पहले उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बने और फिर मार्च 2024 में शिक्षा मंत्री बनाए गए। सुनील कुमार के भाई अनिल कुमार साल 1985, 2005 और 2015 में भोरे (सुरक्षित) सीट से विधायक रहे, लेकिन साल 2020 में भाई के जदयू में शामिल होने पर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। अनिल कुमार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। सुनील कुमार के पिता चंद्रिका राम इस विधानसभा क्षेत्र के पहले विधायक थे। कांग्रेस की सरकार में उनको कृषि मंत्री भी बनाया गया था। भोरे सीट पर इस बार किसी बदलाव की कम ही उम्मीद है। एनडीए की ओर से जदयू सुनील कुमार के साथ ही जाती दिख रही है। वहीं सीपीआई (एमएल) भी थोड़े वोटों से चूक गए जितेंद्र पासवान पर ही भरोसा जताती दिख रही है।

सुरेंद्र मेहता

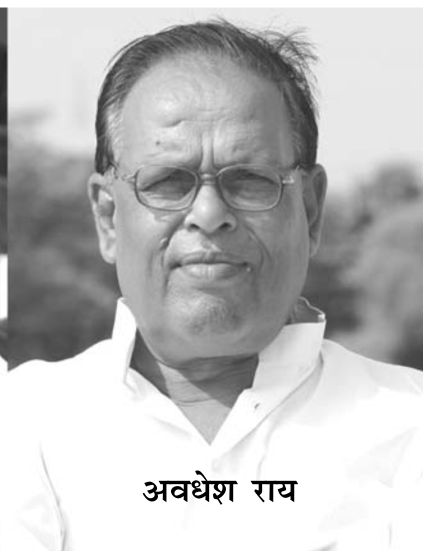
अवधेश राय

छठे सीट डेहरी की बात करे तो रोहतास जिले के डेहरी विधानसभा सीट से राजद के फतेह बहादुर सिंह ने बीजेपी के सत्यनारायण सिंह को महज 464 वोटों से हराया था।

सातवां सीट बछवाड़ा की करें तो बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी के सुरेंद्र मेहता ने सीपीआई के अवधेश राय को 484 वोटों से हराया। सुरेंद्र मेहता मौजूदा सरकार में खेल मंत्री हैं। वहीं अवधेश राय ने लोकसभा चुनाव 2024 में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को

सुमित कुमार सिंह

सावित्री देवी

अनिल कुमार सहनी

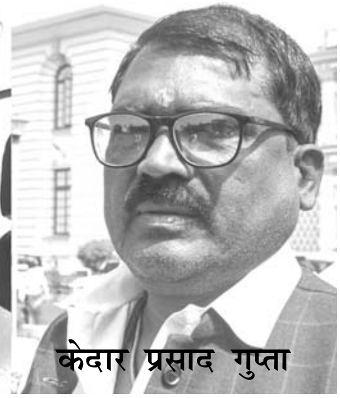
केदार प्रसाद गुप्ता

चुनौती दी थी।

आठवें सीट चकाई की करें तो जमुई जिले के चकाई सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे सुमित सिंह ने राजद के सावित्री देवी को 581 वोटों से हराया था। सुमित सिंह के पिता नरेंद्र सिंह जदयू के कद्दावर नेता और बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। नरेंद्र सिंह नीतीश कुमार के करीबी मित्रों में से थे। सुमित सिंह ने निर्दलीय जीतने के बाद जदयू को अपना समर्थन दिया और बदले में नीतीश कुमार ने उनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री की जिम्मेदारी दी। सुमित कुमार के इस बार जदयू से चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है।

नौवें सीटर कुढ़नी की बात करें तो मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी सीट से राजद के अनिल कुमार सहनी ने बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता को 712 वोटों से हराया था। बाद में इस सीट से चुनाव जीत कर केदार गुप्ता पंचायती राज मंत्री बन गए। इस बार भी उनको टिकट मिलने की पूरी संभावना है। महागठबंधन में इस सीट को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अगर मुकेश सहनी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो ये सीट उनके खाते में जा सकती है।

दसवें सीट बखरी की करें तो बेगूसराय का बखरी विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। इस सीट से सीपीआई के सूर्यकांत पासवान ने बीजेपी के रामशंकर पासवान को 777 वोटों से हराया था। इस बार भी दोनों पार्टियां अपने पुराने उम्मीदवारों के सहारे चुनावी मैदान में जाने की तैयारी में है।

ग्यारहवें सीट परबत्ता की करें तो खगड़िया जिले में आने वाले परबत्ता विधानसभा सीट से जदयू के डॉ. संजीव कुमार ने राजद के दिगंबर तिवारी को 951 वोट से हराया था। डॉ. संजीव कुमार नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद हुए बहुमत परीक्षण के दौरान चर्चा में आए थे। उस दौरान वो सदन से गायब रहे थे। बाद में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया था। ईओयू का नोटिस मिलने के बाद से संजीव कुमार ने बगावत का सुर तेज कर दिया है। अपनी जाति का समर्थन हासिल करने के लिए उन्होंने पिछले महीने पटना में ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन कराया था। संजीव भूमिहार जाति से आते हैं। इस बार जदयू से उनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। संजीव कुमार के पिता आरएन सिंह परबत्ता से चार बार विधायक रहे हैं। इसी साल उनका निधन हो गया। उनके पिता की मृत्यु के बाद तेजस्वी यादव भी शोक जताने पहुंचे थे। वहीं जदयू का कोई बड़ा नेता उनके यहां नहीं पहुंचा। परबत्ता सीट के सामाजिक समीकरण की बात करें तो इस सीट पर भूमिहार, कुशवाहा और मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। परबत्ता सीट से विधायक रहे सतीश कुमार सिंह साल 1968 में पांच दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। इसके अलावा बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस सीट से साल 2000 में राजद के टिकट पर विधायक बने थे। इसके बाद साल 2005 में हुए दोनों चुनाव में उनको हार मिली, फिर साल 2010 में सम्राट चौधरी ने फिर से जीत दर्ज की थी। जदयू से इस बार डॉ. संजीव का टिकट कटना तय माना जा रहा है। संजीव के भाई राजीव कुमार बेगूसराय से कांग्रेस के टिकट पर एमएलसी हैं। माना जा रहा है कि संजीव कुमार भी इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी जगह जदयू पूर्व मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह के बेटे सुशील कुमार सिंह को टिकट दे सकती है। सुशील सिंह कुशवाहा जाति से आते हैं। वहीं एक चर्चा इस सीट से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के भी चुनाव लड़ने की है। इसके अलावा बीजेपी से सरला सिंह भी टिकट की दावेदार हैं।

बहरहाल, बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्दी ही होने वाली है और इससे पहले ही प्रदेश में चुनावी माहौल बन गया है। वहीं, विभिन्न सर्वे एजेंसियां भी अपने आंकड़े जुटाने में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में वोट वाइब ने बिहार चुनाव को लेकर एक सर्वे किया है

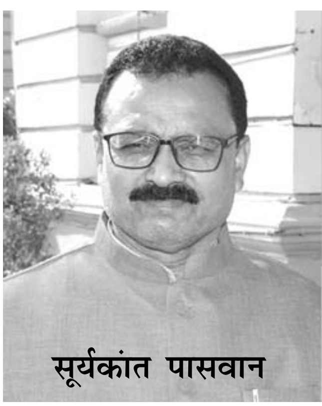
सूर्यकांत पासवान

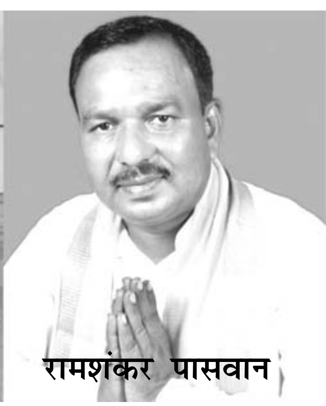
रामशंकर पासवान

डॉ० संजीव कुमार

दिगंबर तिवारी

जिसमें कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार यह सर्वे 3 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच किया गया है और कुल 5635 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। बता दें कि यह सर्वे और इसके आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि इससे पहले बीते 17 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चली थी। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने बिहार के 22 से अधिक जिलों का दौरा किया और वहां यात्रा निकाली। ऐसे में इसके बाद किए गए सर्वे में कई तथ्य उभरकर आए हैं, जो गौर करने लायक हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि जो सैंपल इकट्ठे किए गए हैं, उनमें विभिन्न वर्गों की भागीदारी कितनी है। इसमें पुरुष 52% और महिलाएं 48% हैं। इसमें भी जाति समुदाय के आधार पर अनुसूचित जाति के 20% लोगों की हिस्सेदारी है, जबकि अनुसूचित जनजाति के दो प्रतिशत लोगों से बात की गई है। अदर बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़े वर्ग के 44% लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जबकि अपर कास्ट के हिंदुओं में 16% से बात की गई है। जबकि मुस्लिमों की करीब 18% की भागीदारी रही है। इसके अलावा अन्य वर्गों के एक प्रतिशत लोगों से पूछा गया है। इसको कैटेगरी में बांटते हैं तो शहरी क्षेत्र के 30% और ग्रामीण आबादी के 70% लोगों से बात की गई है। अब आंकड़े जानते हैं। सर्वे में सबसे पहला सवाल था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार के संबंध में आप क्या सोचते हैं? सत्ता विरोधी रुझान है या समर्थन का रुझान है, इसको किस प्रकार देखते हैं? सर्वे में कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 48 प्रतिशत लोगों ने साफ तौर पर माना है कि बिहार में मजबूत सत्ता विरोधी लहर है, जबकि 27.1% लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सत्ता के समर्थन में लोग खड़े हैं। वहीं तटस्थ रहने वालों की संख्या भी काफी महत्वपूर्ण है और यह करीब 20.6% है जबकि, पता नहीं या फिर कह नहीं सकते कहने वालों की संख्या 4.3% है। इन आंकड़ों को गहराई से देखें तो शहरी वर्ग के लोगों में 48% लोगों ने साफ कहा कि हम मौजूद सरकार के खिलाफ हैं। वहीं 31% शहरी लोगों ने समर्थन में अपना मत व्यक्त किया, जबकि 17% लोग तटस्थ रहे। वहीं चार प्रतिशत लोगों ने

कहा कि पता नहीं या कह नहीं सकते। इसी प्रकार इसी सवाल पर ग्रामीण क्षेत्र के 48% लोगों ने सत्ता विरोधी बात कही तो 25% लोगों ने समर्थन में अपना मत जाहिर किया है, जबकि 22% लोगों ने तटस्थता की बात की। वहीं, 4% लोगों ने अपनी अभिज्ञता जाहिर की है, यानी उन्होंने कहा कि वह कह नहीं सकते या उन्हें कुछ पता नहीं है। इन आंकड़ों में और गहराई से जाएं तो आपको पता चलेगा कि पुरुषों और महिलाओं में 48-48 प्रतिशत की मजबूत एंटी इंकंबेंसी है, जबकि न्यूट्रल रहने वालों में 20% पुरुष हैं और 22% महिलाएं स्ट्रांग प्रो इनकंबेंसी वालों में 29% पुरुष हैं, जबकि 25% महिलाएं इसमें शामिल हैं। वहीं डोंट नो कहने वालों में 4% पुरुष है और 5% महिलाएं शामिल हैं। बता दें कि सर्वे उस समय हुआ जब राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' हाल ही में संपन्न हुई थी। हालांकि सर्वे यह स्पष्ट नहीं करता कि कांग्रेस या आरजेडी को इससे सीधा फायदा मिलेगा, लेकिन एंटी-इनकंबेंसी के संकेत जरूर हैं। बहरहाल, सर्वे से जाहिर हो रहा है कि नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति का चेहरा रहे हैं, लेकिन यह सर्वे बताता है कि जनता अब बदलाव की ओर देख रही है। खासतौर पर युवा, महिलाएं और ग्रामीण मतदाता अब विकल्प तलाशने लगे हैं। ●

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल

● संजय कुमार सिन्हा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सौ वर्ष पूरे हुए एक सौ एक वर्ष में प्रवेश, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी पहली शाखा महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में मोहितेके वाड़ा से आरंभ होकर महाराष्ट्र से होते हुये उत्तर प्रदेश के काशी (अब वाराणसी) में लगी उसके बाद मध्यप्रदेश गुजरात राजस्थान दिल्ली बिहार बंगाल असम झारखंड केरल होते हुये सम्पूर्ण भारत में संघ की शाखाएँ लगनी प्रारंभ होते गई , राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी गैरसरकारी संगठन है जो न कभी पंजिकृत हुई और न ही किसी स्वयंसेवक को संगठन का सदस्य बनने के लिए कोई आवेदन पत्र/फार्म नहीं देना पड़ाद्य राष्ट्रीय स्वाभिमान राष्ट्रीय संस्कृति एवं सनातन वैदिक विचारों को आगे बढ़ाता रहा, आम आदमी इस कारवां से जूड़ते रहे और बिखरा हिन्दू समाज के लोग एक परिवार बनते गयें , राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी किसी की आर्थिक स्थिति, जाति, क्षेत्र या भाषा के उलझनों में नहीं रही, सिर्फ मानवता समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाना जरुरतमंदों को मार्गदर्शन करना आपदाओं के स्थिति में पहले दुर्घटना स्थल पर मदद के लिए पहुँचना, जरूरत के हिसाब से स्वयंसेवकों दूरा अपने घरों से दो चार रोटीयां लेकर जरूरमंद को खिलाना, चिकित्सा या कपड़े बांटा करते हैं, जबकि 40

वर्षों पहले बिहार यूपी के कुछ शहरों में नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के लंबे हड़ताल होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता नाले की सफाई अभियान में जुट जाते थे, उस समय सन् 1975 से 1985 तक इन बस्तीयों में 90 प्रतिशत शौचालय कमाऊ (शौच को कर्मचारियों द्वारा टोकड़ी में उठाने) की परंपरा थी या कहें तो यही व्यवस्था हुआ करती थी, इन परिस्थिति में नाले में शौच का बहना आम बात हुआ करती थी, सड़क पर निकलना आफत जैसी हुआ करती थी, बहुत बदबू होती थीं, फिर भी स्वयंसेवक कुदाल फावड़ा बेलचा से गंदगी उठा कर रोड पर चढ़ा दिया करते थे और उसके दूसरे दिन उठा कर प्राईवेट ठेले रेरी से निश्चित स्थान पर फेका जाता थाद्य 80 के दशक में सरकारी कर्मचारी या फिर विधार्थियो अपने को जल्दी स्वयंसेवक बता कर समाज के कार्य करने से बचते थे, क्योंकि उस समय कांग्रेस वामपंथ से प्रभावित अधिकारी, शिक्षण संस्थानों के प्रधान वैसे कर्मचारी विधार्थी के साथ सौतेला व्यवहार एवं प्रतारणा जैसा व्यवहार करने से चुकते नहीं थे, संघ के सौ वर्षों की यात्रा कोई आसान नहीं था, संघ के कार्यकर्ता बहुत पीड़ा की यात्रा कर आज संघ को यहाँ तक पहुचाई है, राष्ट्रीय

स्वयंसेवक संघ पर कुछ चार बार प्रतिबंध भी लगाये गये सन् 1947 में स्वतंत्रता के तुरंत बाद जो सबसे कम 5 दिनों के लिए थी उसके बाद महात्मा गॉधी की मृत्यु उपरांत सन् 1948, सन् 1975 आपातकाल के दौरान जो सबसे लंबी रही,उसके बाद सन् 1992 में बाबरी विवादित ढाँचे गिरने पर इन सभी कारण के लिए तत्कालीन सरकार के पास कोई प्रमाणिक सबूत तर्क नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ आरोप बदनाम करने की षड्यंत्र और अपनी नकामी छिपाने की साजिश मात्र थी, संघ की स्थापना से 1980 के बीच में जिन स्वंयसेवक की संघ प्रवेश रहे हुए होगें वैसे स्वयंसेवक शायद ही 10-20 प्रतिशत जिवित हो? उन समय में समाज के कार्य तो करना है, परन्तु अपनी संगठन की पहचान भी बताने से बचनी थी, इसके कारण एक नहीं लगभग दर्जनों थे- उस समय के पत्रकार स्तंभकार वयंगकार कार्टूनिस्ट अपने को वामपंथी सोच से अपनों को जोड़ कर रखना निष्पक्ष पत्रकारिता मानते थे, अनेकों पत्रकार चंदन टीका लगाना अपने नाम के साथ पंडित लगाना, जनेऊ पहनना परंतु संघ के कार्य को या किसी मंदिरों के द्वारा किये गए कार्य को कभी महिमामंडन न करना उनकी ईमानदारी के पैमाने होते थे, जबकि दूसरी तरफ हिन्दुओं के द्वारा दिया गया ईफ्तार पार्टीयो में मुस्लिमों के पधारने मात्र को महिमामंडन होता था, परंतु ईफ्तार आयोजित करने वाले व्यक्ति हमेशा हासिये पर रहा करते थे, बिहार में एक शहर सीवान है वहाँ एक वैश्य व्यापारी ने अपने हरा भरा लहलहाती कई बीघे खेत को बे समय नष्ट कर मुस्लिमो के एक बड़े कार्यक्रम-आयोजन के लिए दे दिया गया था एवं अर्थ से भी सहयोग करने की काम किया थाद्य 90 के दशक से संघ के स्वयंसेवक थोड़ा आगे बढ़ कर अपने को संघी कहना पसंद करने लगे क्योंकि उस समय संघ के कई स्वयंसेवक रहे कई व्यक्ति केन्द्र सरकार में मंत्री मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री बनने लगे थे, आज तो सबसे ज्यादा नये स्वयंसेवक गर्व से अपने को संघ के स्वयंसेवक कहने से थकते नहीं हैद्य ऐसा नहीं है कि उस जमाने में संघ की कोई लोकप्रियता कम थी? उस समय कांग्रेसी वामपंथीयों ने व्यवस्था पर जबर्दस्त पकड़ बना रखा था, लोगों में अपने परिवार की चलाने की चिंता बहुत होती थी इस कारण संघ के कार्य को बताना या महिमामंडन करना खतरे से कम नहीं था, वैसे समाज के व्यक्ति अपने घर परिवार में संघ की कार्य की सराहना तो करते थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य के कायल तो महात्मा गाँधी जवाहरलाल नेहरू भीमराव आंबेडकर डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद सरदार पटेल सरीखे सभी नेता थे, परंतु उनके द्वारा ससार्वजनिक मंच से बोलना उनकी राजनीति को सुट नहीं करतीं थीं। आप सोच सकते हैं कि वो दौर कितना कठिन रहा होगा कि आप समाज की कार्य तो करो? परंतु संगठन के नाम नहीं बताओ अपने गणवेश नहीं पहनों फोटोशॉप नहीं करो यहाँ तक किसी समाचारपत्र में कोई खबर भी नहीं छपना इसे कहते हैं काम तो करो, परंतु बताना नहीं है उस दौर में संघ के कोई प्रचार तंत्र

पंच परिवर्तन सूत्र
अच्छे नागरिक का कर्तव्य

व्यक्तिगत प्रयास
1. टेक्स (कर) भरना 2. ट्रैफिक नियमों का पालन
3. मतदान करना, कराना
4. संविधान एवं कानून का सम्मान तथा पालन
5. राष्ट्रीय चारित्र्य का परिचय आचरण में
6. राष्ट्रीय सम्पत्ति की रक्षा तथा यथायोग्य उपयोग

पारिवारिक प्रयास
1. टेक्स (कर) भरना 2. ट्रैफिक नियमों का पालन
3. मतदान करना, कराना
4. संविधान एवं कानून का सम्मान तथा पालन
5. राष्ट्रीय चारित्र्य का परिचय आचरण में
6. राष्ट्रीय सम्पत्ति की रक्षा तथा यथा योग्य उपयोग

सांगठनिक प्रयास
1. टेक्स (कर) भरना 2. ट्रैफिक नियमों का पालन
3. मतदान करना, कराना
4. संविधान एवं कानून का सम्मान तथा पालन
5. राष्ट्रीय चारित्र्य का परिचय आचरण में
6. राष्ट्रीय सम्पत्ति की रक्षा तथा यथायोग्य उपयोग

सामाजिक प्रयास
1. चर्चा, प्रबोधन,
जागरण / आचरण के कार्यक्रम / उपक्रम

नई दिल्ली पत्रिका प्रभारी पत्रकार संजय कुमार सिन्हा संग आरएसएस अखिल भारतीय प्रचार सह प्रमुख नरेंद्र कुमार से आगामी संघ के कार्यक्रम 'पंच तत्व' पर वार्तालाप

पंच परिवर्तन सूत्र
स्व का बोध

व्यक्तिगत प्रयास
1. स्वभाषा, स्वभूषा, भोजन, पद्धति का आग्रह
2. हस्ताक्षर, घर के ऊपर स्वयं का नाम स्थानीय भाषा में
3. व्यक्तिगत वस्तु स्वदेशी हो...
(साबुन, टुथपेस्ट, वाहन, जूते, कपड़े, विविध अन्य वस्तु)
4. जन्मदिन में अपनी संस्कृति की पद्धति से
5. घर में मातृभाषा में बातचीत
6. ईसाई शालाओं में बच्चों को नहीं पढ़ाना

पारिवारिक प्रयास
1. स्वभाषा पद्धति, स्वभूषा, भोजन, स्वदेशी वस्तु का आग्रह
2. हस्ताक्षर, घर, दुकान, प्रतिष्ठान के उपर नामपट्टी स्थानीय भाषा में
3. ईसाई शालाओं में बच्चों को नहीं पढ़ाना

सांगठनिक प्रयास
1. पत्र व्यवहार, बैनर, हिन्दू तिथि
2. कार्यक्रमों में स्वदेशी वस्तुओं का आग्रह

सामाजिक प्रयास
1. चर्चा, प्रबोधन,
जागरण / आचरण के कार्यक्रम / उपक्रम

पंच परिवर्तन सूत्र
पर्यावरण

व्यक्तिगत प्रयास
1. पानी दाढ़ी करते समय-स्नान करने समय, कपड़े-गाड़ी धोते समय उपयोग में संयम
2. वृक्ष-विविध प्रसंगों पर वृक्ष लगाना, टिकाना,
3. प्लास्टिक - Singl Use plastic का उपयोग टालना
2. भोजन, चाय, पानी लेते समय प्लास्टिक टालना
3. प्लास्टिक बोतल का उपयोग नहीं करना

पारिवारिक प्रयास
1. पानी दाढ़ी करते समय-स्नान करने समय, कपड़े-गाड़ी धोते समय उपयोग में संयम
2. वृक्ष-विविध प्रसंगों पर वृक्ष लगाना, टिकाना,
3. प्लास्टिक - Singl Use plastic का उपयोग टालना
2. भोजन, चाय, पानी लेते समय प्लास्टिक टालना
3. प्लास्टिक बोतल का उपयोग नहीं करना
4. पारिवारिक कार्यक्रमों में उपयोग नहीं करना
5. बाजार से कुछ लेते समय कपड़े की थैली का उपयोग करना।

सांगठनिक प्रयास
1. सांगठनिक सारे कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं को परिवारिक जैसे ही आचरण का प्रबोध एवं प्रयास हो।
2. चर्चा, प्रबोधन, जागरण / आचरण के कार्यक्रम / उपक्रम
3. फ्लेक्स, बैनर का कम उपयोग 4. पानी के बॉटल का कम उपयोग.

सामाजिक प्रयास
चर्चा, प्रबोधन, जागरण / आचरण के कार्यक्रम / उपक्रम

पंच परिवर्तन सूत्र
कुटुम्ब प्रबोधन

व्यक्तिगत प्रयास
1. साप्ताहिक सत्संग
2. टी.वी., मोबाईल का संभावित उपयोग
3. अच्छे संस्कारों में स्वयं के आचरण का उदाहरण

पारिवारिक प्रयास
1. एकत्र भोजन 2. साप्ताहिक सत्संग
3. सामाजिक कुरीतियों के बारे में प्रबोधन
4. सामाजिक एवं राष्ट्रीय विषयों के बारे में चर्चा
5. हिन्दू संस्कारों का दृढीकरण
6. राष्ट्रीय चारित्र्य के बारे में संस्कार

सांगठनिक प्रयास
1. नव दंपतियों का प्रबोधन
2. परिवार में 2-3 बच्चे होना। 3. 25 वर्ष तक विवाह
4. अनेक परिवारों का एकत्रीकरण का कार्यक्रम

सामाजिक प्रयास समाज के विविध वर्गों को प्रेरणा
1. नव दंपतियों का प्रबोधन
2. परिवार में 2-3 बच्चे होना।
3. 25 वर्ष तक विवाह
4. अनेक परिवारों का एकत्रीकरण का कार्यक्रम

पंच परिवर्तन सूत्र
सामाजिक समरसता

व्यक्तिगत प्रयास
1. सभी जाति बिरादरी में मित्र बनाना
2. हिन्दू हम सब एक-विचार-उच्चार-आचार
3. बड़ी जाति, छोटी जाति ऐसा नहीं बोलना
4. जाति आधारित कहावतों का उपयोग नहीं

पारिवारिक प्रयास
1. परिवार के सम्पर्क में आने वाले छोटे काम करने वालों के साथ मधुर व्यवहार

सांगठनिक प्रयास
1. लक्षित करते हुए अनुसूचित जातियों में सम्पर्क कार्यकर्ता नेतृत्व खड़ा करना
2. रोजगार के लिए प्रयास
3. महापुरुषों के जीवन संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन एवं सहभाग
5. कार्यालयों में सभी के चित्र तथा बातचीत में उदाहरण
6. जहां अपनी समिति है, उस गांव में, नगर में, मंदिरों में सभी का प्रवेश
7. अनुसूचित बस्तियों में संत प्रयास करना।
8. बड़ी जाति, छोटी जाति ऐसा नहीं बोलना
9. जाति आधारित कहावतों का उपयोग नहीं

सामाजिक प्रयास
1. श्रम की प्रतिष्ठा का प्रबोधन
2. सेमिनार
3.. महापुरुषों के जीवन संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन
4. हिन्दू हम सब एक विचार- उच्चार-आचार प्रबोधन कार्यक्रम

विभाग नहीं हुआ करती थी और न ही किसी प्रोटल पर अखिल भारतीय या प्रांत स्तर के दायित्वान व्यक्ति के नाम, पहचान के नाम पर सिर्फ खाकी पैंट काली टोपी थी, संघ में पिछले पन्द्रह-सतरह वर्षों में काफी बदलाव आये हैं- जैसे नया गणवेश, प्रचार विभाग, संवाददाता सम्मेलन, जूआँईन आरएसएस, गुरुदक्षिणा का विस्तार, मुस्लिम मंच आदि के विस्तार प्रमुख है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अब बिखरे हुए हिन्दू जो जातियों में बटें हैं, उन्हें एकीकरण, एक भारत दो दिन हिन्दू त्योहार नहीं हो इसके लिए योजना बनाना, उलेमाओं के सामुहिक बैठक में ध्यान देने ज्यादा, मठ पीठ अखाड़े के अनेकों पीठाधीश्वर को एक सूत्र में बांधना जो एक दूसरे पीठाधीश्वर की आलोचना से बचना और आपस में सभी पीठाधीश्वरों में पारस्परिक संबंध अपनत्व बने इस पर चिंता करना और सनातन संस्कृति की टूटी हुई, खोई हुई धरोहरों की खोज जो सनातन संस्कृति की संचयन करना एक बड़ी सहयोग माना जायेगा, ऐसा नहीं है कि इस कार्य से किसी हिन्दू धर्म या सिक्ख धर्म की पक्षपात जैसा कुछ नहीं है, ये समूचे सनातन संस्कृति की उद्धार हेतु जिसके हम सभी जीवन पद्धति- जो अलग अलग तरीके से जी रहे हैं, उन सभी का भला होगा।

इसमें देश के सभी मतावलंबी सभी धर्मो की भलाई है। सनातन संस्कृति जोड़ते हैं सहयोग करते हैं दया दृष्टि रखते हैंद्य संघ अभी भी छुआछूतो पर ज्यादा ध्यान देती रहीं हैं और समरसता की बातें करतीं हैं, जो अब गुजरा हुआ जमाने की बातें रह गई, अब सभी समाज के लोगों एक साथ एक थाली में खाते हैं एक साथ विस्तर पर सोते भी हैं, समाज की कई महिला सखी एक डिजाइन की साड़ी खरीद कर शादी त्योहारों में पहनतीं हैं, एक दूसरे की बेटी वापस में दोस्त है लड़के अपने जाटव खटीक वाल्मीकि ब्राह्मण राजपूत यादव जाती के मित्रों की बहन से रक्षाबंधन बंधवातें हैं और वो सभी लड़के अपने मित्रों की बहन के लिए वो सबकुछ करने को तैयार रहते हैं, जो उनके सहोदर भाई कर सकते हैं? वो एक जमाना था जब गरीब वर्ग के पास दो वक्त के भोजन नहीं हुआ करती थे, अब तो केन्द्र सरकार राज्य सरकारें मुफ्त योजनाओं के तहत राशन सहित कई चीजें फ्री में या कम दरों पर जनता को ग्रदे रही है, आज 93 प्रतिशत लोगों इन्टरनेट का प्रयोग करते हैं मतलब एन्ड्रायड मोबाईल

खरीद चुके हैं, वातानुकूलित के सुख भी भारत में लगभग सभी वर्गों के पास 33 प्रतिशत हैं, टीवी फ्रीज वाशिंग मशीन गुजरा जमाना की शान माने जाते हैं, मतलब संघ 100 वर्षों में जवान हो गया है अब अगले 100 वर्षों की कार्य योजना बनाई जा सकतीं है, जिसमें अपने वीर सपूत के जीवन यात्रा को आर्दश मानना, अपनी खोई संस्कृति और सनातन पर चरण बद्र योजना बनाना, नवजात में अपनी संस्कृति की पहचान वेद पुराण गीता गुरुकुल एवं संस्कृत भाषा को जीवन में परोसना, पश्चिमी सभ्यता, कांन्वेन्ट स्कूल, विदेशी समान का वहिष्कार देश की जनता की पहली कर्तव्य बनाने पर जोर देना और एक भारत एक कानून का होना और अंत में नागरिकता की न्यूनतम कर्तव्य व जिम्मेदारी देश के लिए तय करना एवं तत्कालीन सरकारों पर कार्यान्वित करने पर जोड़ दिलवाना, अगामी योजना के संकल्प हो.

☞ **स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की भूमिका** :- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में संघ की क्या भूमिका रही? कुछ इससे भी आगे बढ़ जाते हैं और पूछते हैं कि संघ के किसी एक कार्यकर्ता का नाम ही बता दीजिए, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया हो? तो उनकी जानकारी के लिए संघ संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार जन्मजात देशभक्त थे। डॉ. हेडगेवार क्रांतिकारी भी रहे, कांग्रेस में रहकर राजनीतिक संघर्ष किया और जेल भी गए। बाद में, देश की सर्वांग स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को स्थायी बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। डॉ. हेडगेवार अकेले नहीं हैं, अपितु स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने वाले संघ के कार्यकर्ताओं की लंबी सूची है। कार्यकर्ताओं के लिए जिस संगठन में यह प्रतिज्ञा हो कि "मैं हिन्दूराष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना हूँ"। उसने कितने ही लोगों के मन में स्वतंत्रता प्राप्ति का भाव भरा होगा, उसकी कल्पना की जा सकती है।

सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अभी जो हमारे देश की राष्ट्रीय राजनीतिक दल- भारतीय काग्रेस है वह अपने नाम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मतलब आजादी के बाद भी नहीं बदली, आपको जानना जरूरी यह है कि सन् 1885 में कांग्रेस के स्थापना देश आजादी के लिए किया गया ये एक आंदोलन के लिए एक मात्र बैनर थे जो सभी छोटी मोटी संस्थाएँ जैसे- किसानों की संस्थान, पहलवानों की संस्थान, सनातन संस्कृति से जुड़े संस्थान, आर्यसमाज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी सभी संस्थानों के कार्यकर्ता एक मात्र बैनर (कांग्रेस) तले आंदोलन कर रहीं थी, जिससे एक संगठन का बड़ा प्रभाव हो और कोई गुटबाजी न हो स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिम लीग की स्थापना दिसम्बर 1906 में हुई उसके पहले ये मुस्लिम लीग के भी सभी आंदोलन कर्मी कांग्रेस के बैनर तले ही आंदोलन कर रहे थे, मुस्लिम लीग धर्म के आधार पर अलग देश की मांग रख दी जिससे आंदोलन कमजोर पर गई, अन्यथा आजादी सन् 1942 में ही मिल गई होती, अंततः दूसरे विश्व युद्ध समाप्ति 1945 के तुरंत बाद, इसलिए की कांग्रेस ने आजादी दिलाई या कुछ मात्र नेताओं ने तो ये गलत है और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के घोर अपमानाद्य क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य संस्थापक डॉ केशवराव बलिराम हेडगेवार कांग्रेस के सदस्य नहीं थे? उन्होंने कांग्रेस के सन् 1920 नागपुर अधिवेशन में व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाली थी और उस कांग्रेस अधिवेशन में डाक्टर हेडगेवार ने पहली बार खाकी निक्कर सफेद सर्ट को कार्यकर्ताओं को पहनाई थी उस समय संघ की कोई नामों निशान नहीं थे, ये खाकी निक्कर सफेद रंग के सर्ट की विचार उस समय 1920 में उन्होंने वही स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रयोग किया जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बनने के बाद ये संघ के ड्रेस कोड जिसे संघ के स्वयंसेवक गणवेश कहते हैं। भरतीय जनसंघ के निर्माणकर्ता के प्रमुख में से एक या कहें सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कांग्रेसी नेता थे और जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम सरकार में मंत्री भी थे। इसलिए ये कहना कि कांग्रेस ने आजादी दिलाई बिल्कुल असत्य एवं भ्रामक है, इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जैसे- किसी सभागार में कार्यक्रम हो और कार्यक्रम समापन के बाद कोई श्रोता मुख्य अतिथि के कुर्सी पर बैठकर फोटो सूट करवा ले और समाज को वह फोटो दिखलाये, बस ऐसा ही आज की या सन 1952 की कांग्रेस पार्टी थी।

केशवराव बलिराम हेडगेवार का जीवन

डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार के जन्म 1 अप्रैल, 1889 को नागपुर के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हिन्दू नववर्ष प्रतिपदा के दिन हुआ था। वे बचपन से ही क्रांतिकारी प्रवृति के थे उन्हें अंग्रेज शासको से घृणा थी, जब वो विद्यालय में ही पढ़ते थे तब एक दिन उनके विधालय में एक अंग्रेज इंस्पेक्टर निरीक्षण के लिए आया तो केशवराव ने अपने कुछ सहपाठियों के साथ उनका "वन्दे मातरम्" की जयघोष से स्वागत किया जिस पर वह अंग्रेज अधिकारी बिफर गया और उसने आदेश दिया केशवराव को स्कूल से बाहर करो फिर उन्हें विधालय से निकाल दिया गया, तब उन्होंने मैट्रिक तक अपनी पढाई पूना के नेशनल स्कूल से पूरी की 1910 में जब डॉक्टरी की पढाई के लिए कलकत्ता गये तो उस समय वहाँ देश की नामी क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति से जुड़ गए। 1915 में नागपुर लौटने पर वह कांग्रेस में सक्रिय हो गये और कुछ समय में विदर्भ प्रांतीय कांग्रेस के सचिव बन गये। 1920 में जब नागपुर में कांग्रेस का देश स्तरीय अधिवेशन हुआ तो डॉ० केशव राव बलीराम हेडगेवार ने कांग्रेस में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाने के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो उसे तब पारित नही किया गया। 1921 में कांग्रेस के असहयोग आन्दोलन में सत्याग्रह कर गिरफ्तारी दी और उन्हें एक वर्ष की जेल हुई। तब तक वह इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि उनकी रिहाई पर उनके स्वागत के लिए आयोजित सभा को पंडित मोतीलाल नेहरु और हकीम अजमल खा जैसे दिग्गजों ने संबोधित किया।

कांग्रेस में पुरी तन्मन्यता के साथ भागीदारी और जेल जीवन के दौरान जो अनुभव पाए, उससे वह यह सोचने को प्रवृत हुए कि समाज में जिस एकता और धुंधली पड़ी देशभक्ति की भावना के कारण हम गुलाम हुए है वह केवल कांग्रेस के जन आन्दोलन से जागृत और पृष्ट नही हो सकती। जनतन्त्र के परतंत्रता के विरुद्ध विद्रोह की भावना जगाने का कार्य बेशक चलता रहे लेकिन राष्ट्र जीवन में गहरी हुई विघटनवादी प्रवृति को दूर करने के लिए कुछ भिन्न उपाय की जरूरत है। डॉ० केशवराव बलीराम हेडगेवार के इसी चिंतन – मंथन का प्रतिफल थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम से संस्कारशाला के रूप में शाखा पद्दति की स्थापना जो दिखने में साधारण किन्तु परिणाम में चमत्कारी सिद्ध हुई। इसी संस्था के माध्यम से वे अंग्रेजों को धूल चटाते रहे और भारत की आजादी की लड़ाई में सहयोग देते रहे।

27 सितम्बर,1925 के दिन विजयदशमी को संघ कार्य की शुरुआत किया उसके बाद भी उनका कांग्रेस और क्रांतिकारीयो के प्रति रुख सकारात्मक रहा। यही कारण था कि दिसम्बर 1930 में जब महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून विरोधी आन्दोलन छेड़ा गया तो उसमे भी उन्होंने संघ प्रमुख (सरसंघचालक) की जिम्मेदारी अपने उम्र से बड़े एवं संस्थापक सदस्यों में से एक डॉ० लक्ष्मण वासुदेव परापंजे को सौप कर व्यक्तिगत रूप से अपने एक दर्जन सहयोगियों के साथ आंदोलन में भाग लिया जिसमे उन्हें 9 माह की कैद हुई। इसी तरह 1929 में जब लाहौर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पूर्व स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया और 26 जनवरी 1930 को देश भर में तिरंगा फहराने का आह्वान किया तो डॉ० हेडगेवार के निर्देश पर सभी संघ शाखाओं में 30 जनवरी को तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज प्राप्ति का संकल्प किया गया। इसी तरह क्रान्तिकारियों से भी उनके संबध चलते रहे द्य जब 1928 में लाहौर में उप कप्तान सांडर्स की हत्या के बाद भगतसिंह ,राजगुरु और सुखदेव फरार हुए तो राजगुरु फरारी के दौरान नागपुर में डॉ० हेडगेवार के पास पहुचे थे जिन्होंने उमरेड में एक प्रमुख संघ अधिकारी भय्या जी ढाणी के निवास पर ठहरने की व्ययस्था की थी। ऐसे युगपुरुष थे डॉ. केशवराव बलीराम हेडगेवार, उनकी मृत्यु 21 जून, 1940 को नागपुर में हुई।

भारत या कहें तो सनातन संस्कृति में प्रतिज्ञा का महत्व है। भीष्म प्रतिज्ञा का स्मरण होगा ही, राजा हरिशचंद्र की सत्य बोलने की प्रतिज्ञा, मुगलिया सल्तनत के अत्याचार के विरुद्ध महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा को भला कौन भूल सकता है? छत्रपति शिवाजी महाराज ने शिव को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा कर 'स्वराज्य' की नींव रखी, जिसे साकार करने में संपूर्ण समाज प्राण और आत्मा से जुट गया था। संघ के स्वयंसेवक भी इसी भाव के साथ प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं कि वह जो प्रतिज्ञा ले रहे हैं, उसको पूर्ण करने में अपना सर्वस्व देंगे और प्रतिज्ञा को आजन्म निभाएंगे।

मार्च 1928 में नागपुर के निकट एक पहाड़ी पर स्वयंसेवकों को एकत्र करके, भगवा ध्वज के समक्ष प्रतिज्ञा का पहला कार्यक्रम सम्पन्न कराया गया था। देश की पूर्ण स्वतंत्रता एवं विकास के लिए स्वयंसेवकों को वीरव्रती बनाने के निमित्त आयोजित प्रथम कार्यक्रम में 99 स्वयंसेवकों ने प्रतिज्ञा ली थी। इस अवसर पर डॉ. हेडगेवार का उद्‌बोधन स्वतंत्रता प्राप्ति की संघ की आकांक्षा को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य हिन्दू राष्ट्र की पूर्ण स्वाधीनता है। संघ का निर्माण इसी महान लक्ष्य के लिए हुआ है"। इस स्पष्ट अभिव्यक्ति के बाद कहने के लिए कुछ बचता है क्या? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता अपनी नित्य प्रार्थना में कहते हैं कि इस राष्ट्र को परम वैभव पर लेकर जाना है। क्या कोई पराधीन राष्ट्र परम वैभव पर जा सकता है? स्पष्ट है कि भारत की स्वतंत्रता का लक्ष्य संघ की स्थापना में निहित था।

डॉक्टर हेडगेवार ने 1929 में वर्धा में आयोजित प्रशिक्षण वर्ग में भी स्वयंसेवकों एवं नागरिकों की एक सभा में प्रखरता के साथ कहा, "ब्रिटेन की सरकार ने अनेक बार भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया है, परंतु वह झूठा साबित हुआ। अब यह साफ हो गया कि भारत अपने बल पर स्वतंत्रता प्राप्त करेगा"। स्मरण रहे कि डॉ. हेडगेवार ने महात्मा गांधी के आह्वान पर 'नमक सत्याग्रह' में शामिल होकर विदर्भ प्रांत में 1930 में 'जंगल सत्याग्रह' किया। इस आंदोलन में उनके साथ अनेक प्रमुख स्वयंसेवकों

ने हिस्सा लिया। 21जुलाई,1930 को यवतमाल में जंगल कानून तोड़ने के आरोप में डाक्टर हेडगेवार को और उनके साथ ग्यारह स्वयंसेवकों को अंग्रेज सरकार द्वारा बंदी बना लिया गया और देखते ही देखते दस बारह हजार लोग ईक्ठ्ठा हो गये उसमें पांच साल के बच्चों से लेकर 75 साल के महिला पुरुष शामिल थे, डाक्टर हेडगेवार को धारा-117 तथा 279 तहत आरोप तय कर 6 महीने व 3 महीने टोटल 9 महीने की कठोर कारावास की सजा दी गई जबकि उसी समय महात्मा गाँधी को भी इसी आंदोलन के लिए अलग स्थान पर पकड़ा गया और मात्र कुछ दिनों बाद बीना शर्त छोड़ दिया गया था, जबकि अन्य स्वयंसेवक पर धारा-379 के तहत 4 महिने की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और सभी सत्याग्रहियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। डॉक्टर साहब को नौ माह का कठोर कारावास दिया गया। इससे पूर्व 1921 के आंदोलन में भी डॉक्टर साहब को जेल की सजा हुई थी। महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को मध्यभारत में सफल बनाने के लिए स्वयंसेवकों ने अथक प्रयास किया। संघ के सरकार्यवाह जीएम हुद्दार, नागपुर के संघचालक अप्पा साहेब हलदे, बाबूराव बैद्य, संघ के सरसेनापति मार्तडराव जोग के साथ संघ के अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं को आंदोलन में शामिल होने के कारण चार-चार माह का सश्रम कारावास मिला। डाक्टर हेडगेवार को यवतमाल से अकोला जातें समय जगह जगह इनकी सत्कार होती रही एवं जय जयकार होती रही, ट्रेन के ठहराव वाली स्टेशनों पर लोगों का हूजूम लगता रहा और डाक्टर हेडगेवार को स्थानीय लोगों के द्वारा बनाई गई मंच से पांच मिनट बोलने के लिए आग्रह किया जाता था और लोगों के द्वारा लाई गई फलों के टोकरी ट्रेन में रखा जा रहा था, ट्रेन के आगे बढने के बाद डाक्टर हेडगेवार के संग जो इस्पेक्टर था वह अपने सिपाही को डाक्टर साहब को हथकड़ी पहनाने के आदेश दे रहा था जिसपर उनके साथ स्वयंसेवक अप्पा जी जोशी ने उस इन्स्पेक्टर को समझाया, उसपर इन्स्पेक्टर ने कहा कि मैं क्या करु डीएसपी साहब की ओर से आदेश आया है और मैं एक नौकर होने के कारण उसके आदेश का पालन करने होगें, इसपर डाक्टर साहब ने जबाब दिया कि अगर डीएसपी की ऐसी इक्छा होती तो सत्याग्रह से अब तक हथकड़ी पहनाई जा सकती थी,पर आपने देखा है डीएसपी ने ऐसा किया क्या? इन्स्पेक्टर ने झूठ बोलते हुए कहा कि अब ऐसा आज्ञा है, उसके जबाब में डाक्टर हेडगेवार ने कहा कि ये मेरे लिए कोई पहली बार कारावास नहीं है,हमनें अपनी ईच्छा से सत्याग्रह किया है, भाग कर जाने वालों में से हम नहीं है इसलिए हथकड़ी पहनाने के चक्कर में मत पड़ो और तुम ये न समझना

कि तुम्हारा डीएसपी मुस्लिम हैं तो वो तुम्हारी इस हरकत से खूश होगा? फिर भी इन्स्पेक्टर ने पून: अपने सिपाही को बोला 'राम सिंह हथकड़ी क्यों नहीं पहनाते?' इसपर डाक्टर हेडगेवार ने कड़े शब्दों में कहा कि तुम्हें विनती रास नहीं आती ऐसा प्रतीत होता है और कड़े शब्दों में कहा कि तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ? ऐसा लगता है, तुम हथकड़ी पहनाने पर तुले हो ऐसा जान पड़ता है फिर मुझे भी तुझे कुछ दिखाना होगा, फिर इन्स्पेक्टर ने बोला यानि आप मुझे हथकड़ी पहनाने नहीं दोगे उसके बाद डाक्टर साहब अत्यंत क्रोधित हो उठे अप्पा जी जोशी ने कहा कि मैने इतना क्रोधित उन्हें कभी नहीं देखा।

संघ स्थापना के कई वर्षो बाद कांग्रेस को जनमानस के दबाव के कारण 1929 में लाहौर अधिवेशन में रावी के तट पर पहली बार 'पूर्ण स्वराज्य' का प्रस्ताव पारित करना पड़ा। डॉक्टर हेडगेवार ने 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित कराने का प्रयास किया था। उन्होंने कांग्रेस की प्रस्ताव समिति के सामने सुझाव रखा था कि कांग्रेस का उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्र कर भारतीय गणतंत्र की स्थापना करना और विश्व को पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त करना होना चाहिए।

बहरहाल, सम्पूर्ण स्वतंत्रता का उनका सुझाव कांग्रेस ने 9 वर्ष बाद 1929 के लाहौर अधिवेशन में स्वीकृत किया। कांग्रेस का यह निर्णय संघ के घोषित उद्देश्य के अनुरूप था। इसलिए इससे आनंदित होकर सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार ने सभी शाखाओं को 26 जनवरी, 1930 को कांग्रेस का अभिनंदन करने, राष्ट्रध्वज का वंदन करने और स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही यह भी कहा कि शाखाओं पर भाषण करके स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ एवं महत्व को समझाया जाए। सरसंघचालक डाक्टर हेडगेवार के निर्देशानुसार, संघ की सभी शाखाओं पर 26 जनवरी, 1930 को सायं 6 बजे स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।

स्वयंसेवकों ने 1942 के 'अंग्रेजो, भारत छोड़ो' आंदोलन में भी सहभागिता की। अगस्त, 1942 में मुंबई के गोवलिया टैंक मैदान पर कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने आंदोलन की घोषणा की। दूसरे दिन से ही देशभर में आंदोलन प्रारंभ हो गया। विदर्भ में बावली (अमरावती), आष्टी (वर्धा) और चिमूर (चंद्रपुर) में हुए आंदोलनों में संघ के स्वयंसेवकों ने ही नेतृत्व किया। चिमूर के समाचार बर्लिन रेडियो पर भी प्रसारित हुए। यहां के आन्दोलन का नेतृत्व कांग्रेस के उद्धवराव कोरेकर और संघ के अधिकारी दादा नाईक, बाबूराव बेगडे, अण्णाजी सिरास ने किया। चिमूर के आन्दोलन में अंग्रेज की गोली से एकमात्र मृत्यु बालाजी रायपुरकर की हुई, जो संघ स्वयंसेवक थे। इस आंदोलन के अंतर्गत राजस्थान में प्रचारक जयदेवजी पाठक, आर्वी (विदर्भ) में डॉ. अण्णासाहब देशपांडे, जशपुर (छत्तीसगढ़) में रमाकांत केशव (बालासाहब) देशपांडे, दिल्ली में वसंतराव ओक एवं चंद्रकांत भारद्वाज और पटना (बिहार) में अधिवक्ता कृष्ण वल्लभप्रसाद नारायण सिंह (बबुआजी) ने भाग लिया।

अंग्रेज सरकार संघ के बढ़ते प्रभाव से घबरा गई थी। इसलिए उसने संघ पर आंशिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए ताकि संघरूपी आंदोलन को रोका जा सके। गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेज सरकार ने सबसे पहले 15 दिसंबर, 1932 को एक सर्कुलर निकालकर सरकारी कर्मचारियों को संघ में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया। वहीं, 05 अगस्त, 1940 को ब्रिटिश सरकार ने संघ की सैनिक वेशभूषा और प्रशिक्षण पर पूरे देश में प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि गुप्तचर रिपोर्ट में यह जानकारी मिलने लगी थी कि संघ के स्वयंसेवक पूर्ण स्वतंत्रता की ओर तेजी से अग्रसर हैं। राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़-चढ़ कर सहभागिता कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि संघ के प्रचारक बाबा साहब आप्टे ने 12 दिसंबर, 1943 को जबलपुर में गुरु दक्षिणा उत्सव पर स्वयंसेवकों से कहा, "अंग्रेजों का अत्याचार असहनीय है, देश को स्वतंत्रता के लिए तैयार हो जाना चाहिए"। संघ अपनी स्थापना के समय से ही देश की स्वतंत्रता का स्वप्न लेकर चल रहा था। भारत की सर्वांग स्वतंत्रता के लिए संघ के स्वयंसेवक प्रतिज्ञाबद्ध थे, इसलिए अवसर आने पर उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में सहभागिता की, जेल गए और बलिदान भी दिया।●

सपा का पीडीए फार्मूला बिहार में भी होगा लागू

● अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

पूजा पाल

अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में अपने पार्टी मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर तीखे हमले किए, साथ ही कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखी। अखिलेश ने चुनाव आयोग, कानून व्यवस्था, और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर गंभीर सवाल उठाए, जबकि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा की रणनीति और इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर भी जोर दिया। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर निष्पक्षता की कमी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों के सहारे सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है। अखिलेश ने विशेष रूप से मतदाता सूची में कथित हेरफेर और धांधली का मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्षी समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं लाई गई, तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा साबित होगा।

अखिलेश ने समाजवादी पार्टी की नेता पूजा पाल द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी अपनी बात रखी। पूजा पाल ने हाल ही में अपनी जान को खतरा होने की बात कही थी, जिसके जवाब में अखिलेश ने सवाल उठाया कि यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिलकर आता है और फिर विपक्षी नेता को खतरा बताता है, तो इसकी सच्चाई की जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच केंद्र सरकार द्वारा कराई जाए, न कि राज्य सरकार द्वारा, ताकि सत्य सामने आ सके। अखिलेश ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस प्रकरण की जांच की अपील भी की।प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने पूर्व उपराष्ट्रपति ओपी धनखड़ के अचानक इस्तीफे और उनकी वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति का अचानक गायब हो जाना गंभीर चिंता का विषय है। अखिलेश ने सरकार और भाजपा से मांग की कि वे धनखड़ के इस्तीफे की वजह और उनकी वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करें। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता से जोड़ते हुए कहा कि जनता को सच्चाई जानने का हक है। अखिलेश ने बुनकर समाज की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि बिचौलियों के कारण बुनकरों की आय प्रभावित हो रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि बुनकरों को पूंजी, आधुनिक उपकरण, और बाजार तक पहुंच प्रदान की जाए। इसके अलावा, उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की गिरती स्थिति और सरकारी स्कूलों की जमीनों पर कब्जे के आरोप लगाए। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर विफल रही है, जिसके कारण गरीब और वंचित वर्ग प्रभावित हो रहे हैं।

उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अखिलेश ने कहा कि भाजपा शासन में अफसरशाही बेलगाम हो गई है। उन्होंने कानपुर, कौशांबी, और बदायूं की घटनाओं का

जिक्र किया, जहां उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। अखिलेश ने यह भी कहा कि विपक्षी नेताओं को जनता से मिलने से रोका जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पास एक हिडन फोर्स है, जो उनके इशारे पर काम करती है। अखिलेश ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपनी रणनीति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सपा का पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूला, जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में शानदार सफलता दिलाई, अब बिहार में भी लागू किया जाएगा। अखिलेश 28 अगस्त को सीतामढ़ी में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की 'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन बिहार में नीतीश कुमार की एनडीए सरकार को कड़ी चुनौती देगा। अखिलेश ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की विदाई निश्चित है। उन्होंने मुद्रा योजना को झूठी योजना करार दिया और सवाल उठाया कि इसके तहत वितरित 33 लाख करोड़ रुपये कहां गए। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सांप्रदायिक रास्ता अपना रही है। अखिलेश ने दावा किया कि सपा और इंडिया गठबंधन जनहित के मुद्दों पर एकजुट होकर 2027 में सत्ता में वापसी करेगा। अखिलेश ने हालिया अहमदाबाद विमान हादसे पर भी सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने निजीकरण को बढ़ती घटनाओं का कारण बताया। उन्होंने योग दिवस और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर भी तंज कसा, जिसमें उन्होंने गंगा और यमुना जैसी नदियों की सफाई में सरकार की विफलता को उजागर किया। इसके अलावा, उन्होंने आरएसएस और भाजपा पर सोशल मीडिया के जरिए सपा को बदनाम करने का आरोप लगाया।अखिलेश यादव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में सपा की सक्रियता और रणनीति को स्पष्ट किया। उन्होंने न केवल भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, बल्कि सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, और आर्थिक समावेशन जैसे मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। 2025 के बिहार चुनाव और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, अखिलेश ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने का संकल्प लिया। ●

योगी की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं बीजेपी के नाकारा पार्षद

● संजय सक्सेना (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों जिस तरह से पार्षदों की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसने न केवल योगी सरकार की चिंता बढ़ा दी है बल्कि स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी की भविष्य की संभावनाओं पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हजारों पार्षदों ने सरकार की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि ये न तो जनता के काम आ पा रहे हैं और न ही खुद को जिम्मेदार जनप्रतिनिधि साबित कर पा रहे हैं। इन पर आरोप है कि इन्हें न तो अपने क्षेत्र के विकास की कोई फिक्र है और न ही जनता से जुड़े मुद्दों में इनकी कोई दिलचस्पी। उलटे इनमें से अधिकांश पार्षद अपने दफ्तरों और बैठकों से गायब रहते हैं, जबकि जब कहीं ठेकेदारी या कमीशन लेने का मामला आता है तो ये सबसे आगे कूद पड़ते हैं। यही वजह है कि विकास कार्य ठप पड़े रहते हैं और जनता का गुस्सा सीधे-सीधे योगी सरकार पर फूटने लगा है।

रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई नगर निगमों और नगर पालिकाओं के पार्षद पिछले लंबे समय से अपने क्षेत्र में नजर ही नहीं आए। जनता जब उनसे संपर्क करने जाती है तो या तो यह फोन पर उपलब्ध नहीं होते, या बहानेबाजी करके टालमटोल कर देते हैं। लखनऊ के आलमबाग इलाके का उदाहरण लें, वहां के लोग शिकायत कर रहे हैं कि पिछले चार महीने से सड़कों की मरम्मत रुकी हुई है, नालियों की सफाई नहीं हो रही, लेकिन स्थानीय पार्षद न तो मौके पर आ रहे हैं और न ही नगर निगम से कोई दबाव बना पा रहे हैं। यही हाल कानपुर नगर निगम के हर्ष नगर वार्ड में देखने को मिला, जहां पर लंबे समय से जलभराव की समस्या से लोग परेशान हैं। पार्षद से बार-बार निवेदन किया गया, लेकिन न उन्होंने खुद फील्ड में जाकर हालात देखे और न ही अफसरों पर कार्रवाई का दबाव बनाया। जनता का कहना है कि पार्षद सिर्फ टेंडर पास कराने में या कमीशन लेने में सक्रिय होते हैं, लेकिन जनता को राहत दिलाने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। यह समस्या किसी एक नगर निगम या पालिका तक सीमित नहीं है। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, अयोध्या जैसे बड़े नगरों से लेकर छोटे कस्बों तक हर जगह से ऐसी शिकायतें आ रही हैं। बलिया जिले में तो हाल यह है कि कई पार्षद अपनी मौजूदगी ही दर्ज नहीं कराते। वे न तो बैठकों में शामिल होते हैं और न ही जनता के बीच दिखाई देते हैं। परिणाम यह है कि जनता में यह धारणा तेजी से बन रही है कि पार्षद बस

राजनीतिक टिकट पाने और लाभ कमाने के लिए चुने जाते हैं, जनता की सेवा इनकी प्राथमिकता नहीं है। कुछ मामलों में तो शिकायतें इतनी गंभीर हो गई कि लोग आरटीआई के जरिए कामकाज की जांच करने लगे। मुरादाबाद नगर निगम में एक पार्षद के खिलाफ तो यह शिकायत भी आई कि उन्होंने नाली निर्माण के ठेकेदार से खुलेआम कमीशन मांगा। इस तरह की घटनाएं जब उजागर होती हैं तो सरकार की छवि पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि आखिरकार जनता इसकी जिम्मेदारी योगी सरकार पर ही डालती है। यूपी की जनता पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी और कानून-व्यवस्था जैसी समस्याओं से जूझ रही है और उस पर जब स्थानीय स्तर पर भी उसकी सुनवाई नहीं होती, तो गुस्सा और बढ़ना तय है। भाजपा के पार्षद जिस तरह से काम कर रहे हैं, उससे जनता के भीतर यह संदेश जा रहा है कि सत्ताधारी दल सिर्फ चुनाव जीतने और सत्ता पाने के लिए है, सेवा और विकास की बात बस कागजों पर होती है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को भुनाने का काम शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार यह आरोप लगा रही हैं कि भाजपा ने भ्रष्ट और नाकारा पार्षदों को टिकट देकर जनता के साथ धोखा किया है। योगी सरकार के विकास के दावों को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए विपक्ष यह कह रहा है कि जब जमीनी स्तर पर भाजपा के पार्षद ही काम नहीं करेंगे, तो विकास की कोई भी योजना धरातल पर कैसे उतर सकती है। दिलचस्प बात यह भी है कि जब जनता पार्षदों की शिकायत लेकर बीजेपी के स्थानीय नेताओं या मंत्रियों तक पहुंचती है तो वहां से भी उन्हें कोई खास राहत नहीं मिलती। कई मामलों में पार्षदों की शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी पहुंची हैं, लेकिन कार्रवाई न होने से लोगों के मन में निराशा और गुस्सा दोनों ही बढ़ रहा है। कानपुर ग्रामीण की एक घटना इसका स्पष्ट उदाहरण है। वहां एक पार्षद ने हैंडपंप लगवाने के नाम पर हजारों रुपए की वसूली की, लेकिन हैंडपंप आज तक नहीं लगा। जब इस शिकायत को जिले के आला अधिकारियों तक ले जाया गया तो उन्होंने भी टालमटोल कर दी। ऐसे में जनता का गुस्सा योगी सरकार की ओर मुड़ना बिल्कुल स्वाभाविक है। भाजपा के लिए यह स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनावों की राह में स्थानीय निकायों और पार्षदों की अहम भूमिका होती है। जनता का असंतोष सीधे-सीधे पार्टी की वोटबैंक पर असर डाल सकता है। योगी सरकार विकास और सुशासन को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानकर आगे बढ़ रही है, लेकिन जब उसी सरकार की रीढ़ समझे जाने वाले स्थानीय प्रतिनिधि ही जनता का विश्वास खोने लगें, तो पूरा ढांचा कमजोर पड़ने लगता है। यही कारण है कि भाजपा नेतृत्व अंदर ही अंदर इस मसले पर चिंतित है। सूत्र बताते हैं कि सरकार और संगठन स्तर पर ऐसे पार्षदों की रिपोर्ट मांगी जा रही है और कई जगहों पर चेतावनी देने की प्रक्रिया भी शुरू हुई है। हालांकि जनता को अब सिर्फ चेतावनी से तसल्ली मिलने वाली नहीं है, वह ठोस काम चाहती है।

दरअसल, जनप्रतिनिधियों से जनता की अपेक्षा होती है कि वे सिर्फ वोट मांगने तक सीमित न रहें, बल्कि रोजमर्रा की समस्याओं में जनता के बीच खड़े होकर उसकी मदद करें। पार्षद ही सबसे नजदीकी प्रतिनिधि होते हैं और जब वही जनता के साथ धोखा करते नजर आते हैं, तो इससे जनता का भरोसा पूरे शासन-प्रशासन पर से उठ जाता है। इसलिए यदि भाजपा सचमुच जनता का विश्वास बनाए रखना चाहती है, तो उसे अपने हजारों नाकारा पार्षदों पर सख्ती दिखानी होगी। वरना यह नाराजगी आने वाले चुनावों में बड़ा नुकसान साबित हो सकती है। योगी सरकार फिलहाल भले ही कानून-व्यवस्था और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है, लेकिन स्थानीय स्तर पर फैल रही भ्रष्टाचार और उदासीनता की यह लहर उस सारे काम को बेअसर करने की ताकत रखती है। आज यूपी की जनता को सिर्फ वादों की नहीं बल्कि जमीनी बदलाव की जरूरत है। भाजपा के पार्षद यदि इस जिम्मेदारी में विफल साबित होते रहे, तो जनता का भरोसा टूटना अब तय है और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि इस समय योगी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती सड़क, बिजली और पानी से ज्यादा अपने ही पार्षदों की कार्यशैली को सुधारना है, क्योंकि यही वे चेहरे हैं जो सीधे जनता और सरकार के बीच की कड़ी हैं। अगर ये कड़ी कमजोर पड़ गई तो भाजपा के मजबूत गढ़ को भी दरकने से कोई नहीं रोक पाएगा। ●

बिहार पर्यटन निगम में टेंडर घोटाले का बड़ा खुलासा

मुख्य अभियंता अशोक कुमार और लेखा प्रबंधक राकेश रोशन पर गंभीर आरोप

● शशि रंजन सिंह/राजीव कुमार शुक्ला

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (BSTDC) में एक बड़े वित्तीय घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें विभाग के मुख्य अभियंता श्री अशोक कुमार और संविदा लेखा प्रबंधक श्री राकेश रोशन की संलिप्तता सामने आई है। यह घोटाला विधानसभा में पूछे गए तारांकित प्रश्नों, विभागीय पत्राचार और आम नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर उजागर हुआ है। इस घोटाले में फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से टेंडर स्वीकृति, डीबार संवेदकों को अनुबंध देने, अनुभव प्रमाण पत्रों की गलत तरीके से पुष्टि और बिना वित्तीय स्वीकृति के वेतनमान में बढ़ोत्तरी कर सरकारी धन का गबन जैसी गंभीर अनियमितताओं का आरोप है।

❖ **फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र और डीबार संवेदक को टेंडर देने का आरोप :-** घोटाले की शुरुआत तब हुई जब बिहार विधानसभा में

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०
Bihar State Tourism Development Corporation Ltd.
Register office: बीरचन्द पटेल पथ / Beerchand Patel Path, पटना / Patna- 800 001
दूरभाष / Phone : -+91-612-2222622 फैक्स नं० / Fax No: - 0612-2506218
CIN: U63040BR1980SGC001486 web: www.bstdc.bihar.gov.in E-mail: contactbstdc@gmail.com
BSTDC

सं०सं०-208/Engg/2024
कार्यालय आदेश सं०- दिनांक-

कार्यालय आदेश

होटल जानकी बिहार, सीतामढ़ी के कैम्पस में बजट होटल के निर्माण कार्य हेतु निविदा में डिबार रहने के तथ्य को छुपाते हुए गलत शपथ पत्र जमा करने के कारण मेसर्स S.R. Construction, बेगूसराय को अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 378/अभि०/25 दिनांक 28.03.25 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया था। मेसर्स S.R. Construction, बेगूसराय द्वारा पत्रांक शून्य दिनांक 03.04.25 द्वारा इसका उत्तर समर्पित किया गया। इनका उत्तर संतोषप्रद नहीं होने के कारण अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 587 दिनांक 27.05.25 द्वारा कार्य स्थगित करने का आदेश दिया गया। इनके द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र को भी इसकी जाँच के लिए गठित जाँच समिति द्वारा सही नहीं पाया गया है। इनके द्वारा गलत e-mail Id एवं गलत पते का उपयोग करते हुए कार्यालय को सत्यापन प्रमाण पत्र भिजवाया गया।

अतः उक्त कारणों से मेसर्स S.R. Construction, बेगूसराय के एकरारनामा संख्या 28/SBD/24-25 को रद्द करते हुए इनके जमानत की राशि को राज्यसात किया जाता है। साथ ही साथ इनके निबंधन से संबंधित विभाग (Infrastructure Development Authority) को इन कारणों से बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के आलोक में उनके विरूद्ध नियमानुकूल कार्यवाही करने की अनुशंसा करने का निर्णय लिया जाता है।
2. आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
कार्यपालक अभियंता
(उत्तर बिहार)

ज्ञापांक-208/Engg/2024 दिनांक-____/07/2025
प्रतिलिपि- M/s S.R. Construction, Sashi Palace, Ramkrishna Nagar, Hemra Road, Ward No-20, Begusarai- 851101, email- srconstruction1966@gmail.com, को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
कार्यपालक अभियंता
(उत्तर बिहार)

ज्ञापांक-208/Engg/2024/769/Engg/05 दिनांक- 03/07/2025
प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, बेतिया जोन, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि० पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता
(उत्तर बिहार)

विधायक श्री महानंद सिंह ने 9 मार्च 2025 को तारांकित प्रश्न संख्या 17/14/3570 के माध्यम से यह मुद्दा उठाया कि कैसे एक डीबार संवेदक- M/S S.R. Construction, बेगूसराय को बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा कई टेंडर दिए गए। पर्यटन विभाग द्वारा विधानसभा में दिए गए उत्तर में यह दावा किया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा उक्त कंपनी की डीबार स्थिति पर रोक लगाई गई थी। लेकिन दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय ने डीबारमेंट को नहीं बल्कि ब्लैकलिस्टिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। इतना ही नहीं, IDA द्वारा 27 जुलाई 2024 को जारी शुद्धिपत्र में साफ तौर पर M/S S.R. Construction को डीबार यथावत रखा गया है। इसके बावजूद पर्यटन विभाग ने 3 जुलाई 2025 को कार्यालय आदेश संख्या-208/Engg/2024/769/Engg/25 के माध्यम से स्वीकार किया कि उक्त कंपनी को डीबार रहते हुए टेंडर दिया गया।

❖ **फर्जी ईमेल के जरिए अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन :-** श्री अशोक कुमार पर यह भी आरोप है कि उन्होंने M/S S.R. Construction द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों की सत्यता जाली ई-मेल आईडी का उपयोग करके की, जबकि संबंधित विभागों के आधिकारिक ई-मेल आईडी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, फिर भी जानबूझकर फर्जी ई-मेल के माध्यम से प्रमाण

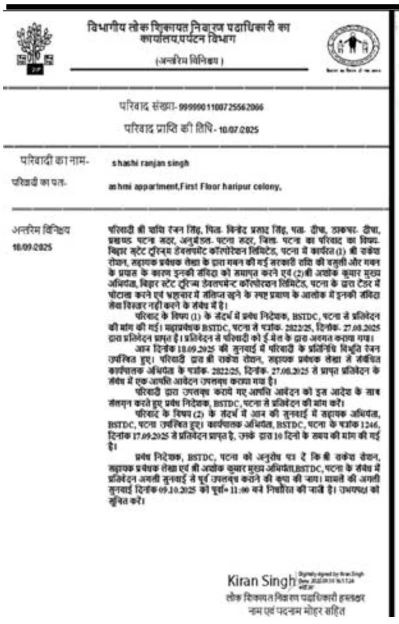

विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का
कार्यालय,पर्यटन विभाग
(अन्तरिम विनिश्चय)

परिवाद संख्या- 9999901100725562066
परिवाद प्राप्ति की तिथि- 10.07.2025

परिवादी का नाम- shashi ranjan singh
परिवादी का पता- ashmi appartment,First Floor haripur colony,

अन्तरिम विनिश्चय 18.09.2025

परिवादी श्री शशि रंजन सिंह, पिता- विनोद प्रसाद सिंह, पता- दीघा, डाकघर- दीघा, प्रखण्ड- पटना सदर, अनुमंडल- पटना सदर, जिला- पटना का परिवाद का विषय- बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना में कार्यरत (1) श्री राकेश रोशन, सहायक प्रबंधक लेखा के द्वारा गबन की गई सरकारी राशि की वसूली और गबन के प्रयास के कारण इनकी संविदा को समाप्त करने एवं (2) श्री अशोक कुमार मुख्य अभियंता, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना के द्वारा टेंडर में घोटाला करने एवं भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने के स्पष्ट प्रमाण के आलोक में इनकी संविदा सेवा विस्तार नहीं करने के संबंध में है।

परिवाद के विषय (1) के संदर्भ में प्रबंध निदेशक, BSTDC, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गई। महाप्रबंधक BSTDC, पटना से पत्रांक- 2822/25, दिनांक- 27.08.2025 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन से परिवादी को ई-मेल के द्वारा अवगत कराया गया।

आज दिनांक 18.09.2025 की सुनवाई में परिवादी के प्रतिनिधि विभूति रंजन उपस्थित हुए। परिवादी द्वारा श्री राकेश रोशन, सहायक प्रबंधक लेखा से संबंधित कार्यपालक अभियंता के पत्रांक- 2822/25, दिनांक- 27.08.2025 से प्राप्त प्रतिवेदन के संबंध में एक आपत्ति आवेदन उपलब्ध कराया गया है।

परिवादी द्वारा उपलब्ध कराये गए आपत्ति आवेदन को इस आदेश के साथ संलग्न करते हुए प्रबंध निदेशक, BSTDC, पटना से प्रतिवेदन की मांग करें।

परिवाद के विषय (2) के संदर्भ में आज की सुनवाई में सहायक अभियंता, BSTDC, पटना उपस्थित हुए। कार्यपालक अभियंता, BSTDC, पटना के पत्रांक 1246, दिनांक 17.09.2025 से प्रतिवेदन प्राप्त है, उनके द्वारा 10 दिनों के समय की मांग की गई है।

प्रबंध निदेशक, BSTDC, पटना को अनुरोध पत्र दें कि श्री राकेश रोशन, सहायक प्रबंधक लेखा एवं श्री अशोक कुमार मुख्य अभियंता,BSTDC, पटना के संबंध में प्रतिवेदन अगली सुनवाई से पूर्व उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। मामले की अगली सुनवाई दिनांक 09.10.2025 को पूर्वा० 11:00 बजे निर्धारित की जाती है। उभयपक्ष को सूचित करें।

Kiran Singh
लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम मोहर सहित

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०
Bihar State Tourism Development Corporation Ltd.
/Beerchand Patel Path, पटना / Patna- 800 001
Phone : -+91-612-2222622 / Fax No: - 0612-2506218
CIN: U63040BR1980SGC001486, Web: www.bstdc.gov.in E-mail: contactbstdc@gmail.com
BSTDC

सं.सं.- 185/E-33/2025/917/Engg/25 दिनांक- 23/07/25

प्रेषक,
मुख्य अभियंता,
बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना।

सेवा में,
विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,
पर्यटन विभाग,
बिहार पटना।

विषय- परिवादी श्री शशिरंजन सिंह परिवाद सं०- 9999901100725562066 के संदर्भ में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग- आपका पत्रांक- 61 दिनांक- 15.07.25

महोदय,
उपर्युक्त विषयक परिवाद में अंकित बिंदुओं के संबंध में बिंदुवार प्रतिवेदन निम्नवत है:-

1.	M/S S.R. Constrution को फर्जी ईमेल (Self Created) से फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन	M/S S.R. Constrution द्वारा निविदा में डाले गए प्रमाण प्रमाण पत्र में वर्णित संबंधित कार्यालय के ईमेल आई डी पर ही सत्यापन हेतु अनुभव प्रमाण पत्र भेजा गया है, तथा उसी ईमेल आई डी से अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन किया गया। फर्जी ईमेल आई डी की बात बिल्कुल ही निराधार एवं भ्रामक है। इसके अलावा डाक द्वारा भेजकर भी सत्यापन कराया गया तथा सत्यापन में प्रमाण पत्र सही होने की सूचना पर ही कार्य आवंटित किया गया। (अनु० परि०- 1 से 5 संलग्न)
2.	इस फर्म के IDA, Bihar सन 2023 से ही DEBAR होते हुए भी इस फर्म को कार्य दिया गया/ इसको सपोर्टिंग पेपर के रूप में पास कर, अन्य संवेदक को कार्य दिया गया।	संवेदक द्वारा निविदा में IDA के DEBAR संबंधी आदेश के स्थगन संबंधी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को निविदा में संलग्न किया गया था। इन्हीं कारणों से उन्हें निविदा में सफल किया गया। यद्यपि उसी आदेश को संशोधित कर IDA द्वारा उन्हें पुनः DEBAR कर दिया गया था। जिसकी जानकारी उनके द्वारा निविदा में छिपाया गया जिसके चलते उनके एकरारनामा को रद्द कर उनके जमानत की राशि को जब्त करने एवं उन्हें काली सूची में डालने की कार्रवाई की गई। (अनु० परि० – 6 से 9 संलग्न)

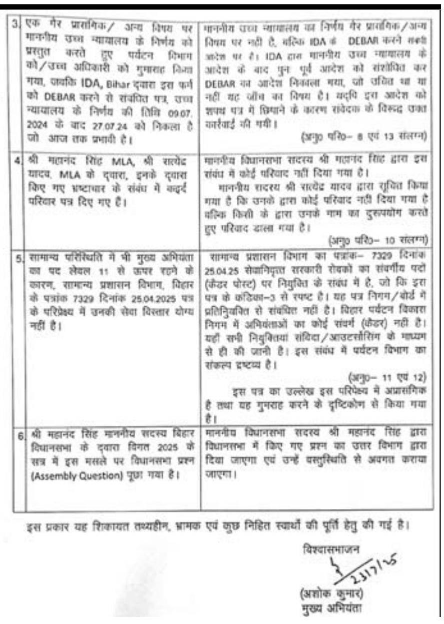

3.	एक गैर प्रासंगिक/ अन्य विषय पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को प्रस्तुत करते हुए पर्यटन विभाग को/उच्च अधिकारी को गुमराह किया गया, जबकि IDA, Bihar द्वारा इस फर्म को DEBAR करने से संबंधित पत्र, उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि 09.07.2024 के बाद 27.07.24 को निकला है जो आज तक प्रभावी है।	माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय गैर प्रासंगिक/अन्य विषय पर नहीं है, बल्कि IDA के DEBAR करने संबंधी आदेश पर है। IDA द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पुनः पूर्व आदेश को संशोधित कर DEBAR का आदेश निकाला गया, जो उचित था या नहीं यह जाँच का विषय है। यद्यपि इस आदेश को शपथ पत्र में छिपाने के कारण संवेदक के विरूद्ध उक्त कार्रवाई की गयी। (अनु० परि०- 8 एवं 13 संलग्न)
4.	श्री महानंद सिंह MLA, श्री सत्येंद्र यादव, MLA के द्वारा, इनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के संबंध में कई परिवार पत्र दिए गए हैं।	माननीय विधानसभा सदस्य श्री महानंद सिंह द्वारा इस संबंध में कोई परिवाद नहीं दिया गया है। माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र यादव द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा कोई परिवाद नहीं दिया गया है बल्कि किसी के द्वारा उनके नाम का दुरूपयोग करते हुए परिवाद डाला गया है। (अनु० परि०- 10 संलग्न)
5.	सामान्य परिस्थिति में भी मुख्य अभियंता का पद लेवल 11 से ऊपर रहने के कारण, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 7329 दिनांक 25.04.2025 पत्र के परिप्रेक्ष्य में उनकी सेवा विस्तार योग्य नहीं है।	सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक- 7329 दिनांक 25.04.25 सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संवर्गीय पदों (कैडर पोस्ट) पर नियुक्ति के संबंध में है, जो कि इस पत्र के कंडिका-3 से स्पष्ट है। यह पत्र निगम/बोर्ड में प्रतिनियुक्ति से संबंधित नहीं है। बिहार पर्यटन विकास निगम में अभियंताओं का कोई संवर्ग (कैडर) नहीं है। यहाँ सभी नियुक्तियां संविदा/आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही की जाती है। इस संबंध में पर्यटन विभाग का संकल्प द्रष्टव्य है। (अनु०- 11 एवं 12) इस पत्र का उल्लेख इस परिपेक्ष्य में अप्रासंगिक है तथा यह गुमराह करने के दृष्टिकोण से किया गया है।
6.	श्री महानंद सिंह माननीय सदस्य बिहार विधानसभा के द्वारा विगत 2025 के सत्र में इस मसले पर विधानसभा प्रश्न (Assembly Question) पूछा गया है।	माननीय विधानसभा सदस्य श्री महानंद सिंह द्वारा विधानसभा में किए गए प्रश्न का उत्तर विभाग द्वारा दिया जाएगा एवं उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा।

इस प्रकार यह शिकायत तथ्यहीन, भ्रामक एवं कुछ निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु की गई है।

विश्वासभाजन
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता

राकेश रोशन

पत्रों को सत्यापित कर, संवेदक को सफल घोषित किया गया। उसी कार्यालय आदेश में यह भी स्वीकार किया गया है कि अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच के लिए गठित समिति ने इन्हें "गलत ईमेल-आईडी एवं गलत पते" से भेजा गया बताया और उसी आधार पर संवेदक का अनुबंध रद्द कर जमानत राशि जब्त कर ली गई।

❖ **अन्य संवेदकों को अयोग्य ठहराकर मनचाहे ठेके दिए गए :-** दस्तावेजों के अनुसार, जिस संवेदक के अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, उसी के कागजों को "सपोर्टिंग पेपर" बनाकर अन्य टेंडर में भी चहेते ठेकेदारों को कार्य आवंटित किया गया। कई योग्य संवेदकों को छोटे तकनीकी कारणों से बाहर कर दिया गया, जिससे टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता खत्म हो गई।

❖ **मुख्य अभियंता द्वारा की गई इस योजना में प्रमुख रूप से निम्नलिखित परियोजनाएं शामिल थीं :-**

☞ इन्द्रपुरी बैराज (रोहतास) में गार्डन व मनोरंजन केंद्र का विकास।

☞ होटल कुटिल्य विहार के पीछे BSTDC

नंद किशोर

अशोक कुमार

कार्यालय भवन का निर्माण (पटना)।

☞ अशोकधाम (लखीसराय) के शिवगंगा तालाब का सौंदर्यीकरण।

☞ होटल विश्वामित्र विहार का नवीनीकरण (बक्सर)।

DETAILS OF FROD DONE BY SRI ASHOK KUMAR , CHIEF ENGINEER , BIHAR STATE TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED , PATNA

क्रम संख्या	बिहार विधान सभा में उत्तर हेतु प्रश्न का बिंदुवार विवरण (छाया प्रति संलग्न)	पर्यटन विभाग के पत्रांक 1430 दिनांक 13-05-2025 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा बिहार विधानसभा में दिया गया फर्जी / झूठा जवाब	बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यालय आदेश संख्या 208/Engg / 2024 769/Engg/25 दिनांक 03-07-25 (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार उजागर सहित तथ्य
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-		
1.	क्या यह बात सही है कि बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में M/S S.R. Construction बेगूसराय को आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (IDA, Bihar) द्वारा Debar रहने के बावजूद निविदा में	आधारभूत संरचना M/S S.R. Construction बेगूसराय को आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (I.D.A.) में Debar किया गया था परंतु उनके द्वारा निविदा के शपथ पत्र के साथ में ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपलोड किया गया था, जिसमें माननीय	माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी M/S S.R. Construction बेगूसराय के Debarment पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि Debarment के बाद की Blacklisting की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है (छाया प्रति संलग्न)। इस प्रकार श्री अशोक कुमार, मुख्य अभियंता, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश की भी झूठी व्याख्या की गई है, जो की माननीय उच्च न्यायालय के अवमानना का मामला बनता है। अंकनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 09-07-2024 को पारित हुआ है, जबकि के आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (I.D.A.) द्वारा को माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश की समीक्षा कर दिनांक 27-07-2024 को शुद्धि पत्र पत्रांक 3936/Tech दिनांक 27-07-2024 (छाया प्रति संलग्न) निकालते हुए M/S S.R. Construction बेगूसराय के Debarment को जारी रखा गया है। इस बात की जानकारी [illegible] माननीय [illegible] यादव, माननीय सदस्य, बिहार विधानसभा के द्वारा दिनांक 10-01-2025 को ही पर्यटन विभाग को दी गई थी परंतु इसे छुपाते हुए बिहार विधानसभा में गलत जवाब दिया गया।
	सफल घोषित कर कार्यादेश निविदा बनाकर मनचाहे संवेदकों को टेंडर दिया गया	उच्च न्यायालय द्वारा Debarment के आदेश को स्थगित कर दिया गया है शपथ पत्र में Debar किए जाने के उक्त आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश की बात लिखी गई है।	पर्यटन विभाग के द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 208/Engg / 2024 769/Engg/25 दिनांक 03-07-25 में लिखते हुए M/S S.R. Construction बेगूसराय के Debarment को स्वयं स्वीकार किया गया है "होटल जानकी विहार सीतामढ़ी के कैंपस में बजट होटल के निर्माण कार्य हेतु निविदा में Debar रहने के तथ्य कुछ छुपाते हुए गलत शपथ पत्र जमा रहने के कारण M/S S.R. Construction, बेगूसराय को अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 378/Engg/25 दिनांक 28-03-2025 के द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया था पूछा गया था। M/S S.R. Construction, बेगूसराय द्वारा पत्रांक शून्य दिनांक 03-04-2025 द्वारा इसका उत्तर समर्पित किया गया। इसका उत्तर संतोषप्रद नहीं रहने के कारण अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 587 दिनांक 27-05-2025 के द्वारा कार्य स्थगित करने का आदेश दिया गया।"
2.	जाली अनुभव प्रमाण पत्र का सीपीडब्ल्यूडी (CPWD) के SELF CREATED फर्जी ई-मेल के माध्यम से कार्य अनुभव का सत्यापन कर निविदा में सफल घोषित कर कार्यादेश निविदा बनाकर मनचाहे संवेदकों को टेंडर दिया गया है	इनके द्वारा समर्पित CPWD एवं IDA संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र की जांच डाक के माध्यम से भेज कर कराई गई है जिसका सत्यापन पत्र संबंधित संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया है केवल [illegible] फर्जी ईमेल के माध्यम से कार्य अनुभव का सत्यापन कराए जाने की बात सही नहीं है सत्यापन प्रतिवेदन हार्ड कॉपी में निबंधित डाक से प्राप्त है।	पर्यटन विभाग के द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 208/Engg / 2024 769/Engg/25 दिनांक 03-07-25 में लिखते हुए M/S S.R. Construction बेगूसराय के जाली अनुभव प्रमाण पत्र का सीपीडब्ल्यूडी (CPWD) के SELF CREATED फर्जी ई-मेल के माध्यम से कार्य अनुभव का सत्यापन को स्वयं स्वीकार किया गया है:- "इनके द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र को भी इसकी जांच के लिए गठित जांच समिति के द्वारा सही नहीं पाया गया है इनके द्वारा गलत email-id एवं गलत पते का उपयोग करते हुए कार्यालय को सत्यापन प्रमाण पत्र भिजवाया गया अतः उक्त कारण से M/S S.R. Construction बेगूसराय के एकरारनामा संख्या 28/SBD/24-25 को रद्द करते हुए इनके जमानत राशि को राजसात किया जाता है। साथ ही साथ इनके विभाग से संबंधित विभाग (Infrastructure Development Authority) को इस कारण से बिहार ठेकेदारी निबंध नियमावली 2007 के आलोक में उनके विरुद्ध नियमानुकूल कार्यवाही करने की अनुशंसा करने का निर्णय लिया जाता है। आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।"
3.	As Above	M/S S.R. Construction बेगूसराय को सीतामढ़ी में बजट होटल का निर्माण कार्य BOQ दर से 10.03 % कम पर कम दर पर आवंटित किया गया है	पर्यटन विभाग के द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 208/Engg / 2024 769/Engg/25 दिनांक 03-07-25 में लिखते हुए M/S S.R. Construction बेगूसराय के जाली अनुभव प्रमाण पत्र का सीपीडब्ल्यूडी (CPWD) के SELF CREATED फर्जी ई-मेल के माध्यम से कार्य अनुभव का सत्यापन को स्वयं स्वीकार किया गया है:- "इनके द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र को भी इसकी जांच के लिए गठित जांच समिति के द्वारा सही नहीं पाया गया है इनके द्वारा गलत email-id एवं गलत पते का उपयोग करते हुए कार्यालय को सत्यापन प्रमाण पत्र भिजवाया गया अतः उक्त कारण से M/S S.R. Construction बेगूसराय के एकरारनामा संख्या 28/SBD/24-25 को रद्द करते हुए इनके जमानत राशि को राजसात किया जाता है। साथ ही साथ इनके विभाग से संबंधित विभाग (Infrastructure Development Authority) को इस कारण से बिहार ठेकेदारी निबंध नियमावली 2007 के आलोक में उनके विरुद्ध नियमानुकूल कार्यवाही करने की अनुशंसा करने का निर्णय लिया जाता है। आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।"
4.	यदि हां तो सरकार कब तक उक्त मामले की जांच करवाकर फर्जीवाड़ा करने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है नहीं तो क्यों?		अभी तक फर्जीवाड़ा करने वाले पदाधिकारी श्री अशोक कुमार मुख्य अभियंता बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना पर सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई कर नहीं की गई है।

अमरेंद्र अजय

☞ होटल जानकी विहार (सीतामढ़ी) परिसर में बजट होटल निर्माण।

❖ **विधानसभा को भी किया गया गुमराह :-** सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि उक्त आरोपों को छिपाने के लिए विधानसभा में गलत जवाब प्रस्तुत किया गया। मुख्य अभियंता द्वारा तैयार किए गए उत्तर में झूठी जानकारी दी गई, जिससे मंत्री, प्रधान सचिव, प्रबंध निदेशक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी भ्रमित हुए। ऐसा कृत्य न केवल नैतिक पतन को दर्शाता है बल्कि यह विधायिका के अपमान के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।

❖ **लेखा प्रबंधक द्वारा 23 लाख रुपये के गबन का आरोप :-** वहीं दूसरी ओर सहायक प्रबंधक (लेखा) श्री राकेश रोशन पर यह आरोप है कि उन्होंने संविदा पद पर रहते हुए अपने पद को सहायक अभियंता के समकक्ष वेतनमान दिलाने का प्रयास किया। वित्त विभाग द्वारा यह प्रस्ताव स्पष्ट रूप से अस्वीकृत कर दिया गया, क्योंकि संविदा कर्मियों के वेतनमान में पुनरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद श्री राकेश रोशन ने पुरानी संचिका को

अभिजीत कुमार

श्री महानंद सिंह, मा॰स॰वि॰स॰ द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–17/14/3570 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे कि :– क्या यह बात सही है कि बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि॰, पटना में M/s S.R. Construction, राम कृष्ण, बेगूसराय को आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (I.D.A), द्वारा Debar रहने के बावजूद तथा जाली अनुभव प्रमाण पत्र का सीपीडबल्यूडी (CPWD) के SELF CREATED फर्जी ईमेल के माध्यम से कार्य अनुभव का सत्यापन कर निविदा में सफल घोषित कर, सपोर्टिंग निविदा बनाकर, मनचाहे संवेदकों को टेंडर दिया गया है, यदि तो सरकार कबतक उक्त मामले की जाँच से करवाकर फर्जीवाड़ा करने वाले पदाधिकारी पर कारवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	M/s S.R. Construction को आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण (I.D.A) में डिबार किया गया था, परन्तु उनके द्वारा निविदा में शपथ–पत्र के साथ CWJC No. 10160/2024 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपलोड किया गया था। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डिबारमेंट के आदेश को स्थगित कर दिया गया है। शपथ पत्र में डिबार किए जाने के उक्त आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश की बात लिखी गयी है। इनके द्वारा समर्पित I.D.A एवं CPWD संबंधी अनुभव प्रमाण पत्रों की जाँच डाक के माध्यम से भी भेज कर करायी गई है, जिसका सत्यापन पत्र संबंधित संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया है। Self created फर्जी ईमेल के माध्यम से कार्य अनुभव का सत्यापन कराये जाने की बात सही नहीं है। सत्यापन प्रतिवेदन हार्डकॉपी से नियमित डाक से प्राप्त है। M/s S.R. Construction को सीतामढ़ी में बजट होटल का निर्माण कार्य BOQ दर से 10.03% कम दर पर आवंटित किया गया है।

बिहार सरकार

पयर्टन विभाग

ज्ञापांक– प॰वि॰स॰ (ता॰)– 58/2025 1430 पटना, दिनांक– 13-5-2025

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को पाँच प्रतियों में/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/ आई॰टी॰ मैनेजर, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव,

पर्यटन विभाग, बिहार पटना।

महानंद सिंह
स.वि.स.
214–अरवल
सदस्य : पर्यटन उद्योग संबंधी समिति
(बिहार विधानसभा)

भाकपा माले जिला कार्यालय
एन.एच.-139, पटना-औरंगाबाद रोड, अरवल
मो॰ : 9470421281, 9006244096
Email ID : mahanand.cpiml@gmail.com

पत्रांक 98/25 दिनांक 13/07/2025

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष महोदय,
बिहार विधान सभा
पटना।

विषय:– विधान सभा में किए गए प्रश्न का उत्तर गलत देकर पूरे सदन को गुमराह करने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करने के संदर्भ में।

महाशय,

सदन में किए गए तारांकित प्रश्न संख्या–17/14/3570 " क्या यह बात सही है कि बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना में M/S SR Construction, रामकृष्ण, बेगुसराय को आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (IDR) द्वारा Debar रहने के बावजूद तथा जाली अनुभव प्रमाण पत्र का CPWD के Self Created फर्जी इमेल के माध्यम से कार्य अनुभव का सत्यापन कर निविदा बनाकर मनचाहे संवेदकों को टेंडर दिया गया है, यदि हॉ तो सरकार उक्त मामले की जांच करवाकर फर्जीवाड़ा करने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है ? "

इस सवाल का जवाब सदन में गलत तथ्यों के साथ दिया गया जिससे पूरे सदन की गरिमा गिराने का कार्य पदाधिकारी द्वारा किया गया है। हमने पदाधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की थी। लेकिन विभाग ने केवल संवेदक पर कार्रवाई कर दिया है। सवाल के जवाब के आधार पर संवेदक पर कार्रवाई (निविदा रद्द करना) करना तो उचित है। साथ ही गलत कागज के आधार पर टेंडर पारा करने के कारण संबंधित पदाधिकारी पर भी कार्रवाई करना जरूरी है।

इसी विभाग ने विभागीय पत्र लिखकर संवेदक पर कार्रवाई की गई है जिसमे मेरे द्वारा किए गए सवाल का जवाब सही नहीं दिया गया है। यानि विधान सभा में सवाल का जवाब अलग और विभाग द्वारा संवेदक पर कार्रवाई करते हुए जवाब अलग दिया जाना क्या दर्शाता है ?

यह बहुत ही गम्भीर मामला है जिसे संज्ञान में लेते हुए दो तरह के जवाब देकर सदन को गुमराह करने वाले पदाधिकारी पर कठोर कार्रवाई हो ताकि दुबारा किसी माननीय द्वारा पूछे गए सवाल का गलत जवाब नहीं दे सके।

संलग्न :–

1. सदन में माननीय द्वारा उठाए गए प्रश्न का जवाब की छायाप्रति।
2. विभाग को इसी मामले का दिया गया जवाब की छायाप्रति।
3. संबंधित कागजात इस पत्र के साथ संलग्न।

भवदीय

13/07/2025
(महानंद सिंह)

गायब करवा दिया और नए अधिकारियों को भ्रमित कर 23 लाख रुपये का एरियर एवं नियमित वेतन स्वीकृत करवा लिया। यह पूर्णतः गबन की श्रेणी में आता है।

❖ **कई शिकायतें दर्ज, लेकिन जांच लंबित :-** इन घोटालों के संबंध में आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और स्वयं शिकायतकर्ताओं द्वारा दर्जनों शिकायतें की जा चुकी हैं, जिनमें CPGRAMS, मुख्यमंत्री सचिवालय और पर्यटन विभाग को संबोधित पत्र शामिल हैं। फिर भी छह महीने बीतने के बाद भी जांच पूरी नहीं हुई है और कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है।

❖ **क्या कहता है नियम और कानून? :-** बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 25 अप्रैल 2025 को जारी आदेश पत्रांक-7329 में स्पष्ट किया गया है कि राजपत्रित अधिकारी स्तर (Level-11 और उससे ऊपर) के पदों पर संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। इस संदर्भ में श्री अशोक कुमार की संविदा सेवा न केवल इस नियम का उल्लंघन करती है, बल्कि उन्हें

राजू सिंह

मिले अधिकारों का दुरुपयोग भी स्पष्ट रूप से सामने आता है।

❖ **जनप्रतिनिधियों की मांग : तत्काल कार्रवाई हो :-** माननीय विधायक सत्येंद्र यादव, महानंद सिंह और अन्य कई जनप्रतिनिधियों ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री से मांग की है कि :-

☞ मुख्य अभियंता श्री अशोक कुमार की संविदा सेवा को तत्काल समाप्त किया जाए।

☞ उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आर्थिक अपराध की जांच शुरू की जाए।

☞ श्री राकेश रोशन से गबन की गई राशि की वसूली कर उनकी सेवा समाप्त की जाए।

☞ पूरे टेंडर घोटाले की न्यायिक जांच कराई जाए।

❖ **निष्कर्ष : पारदर्शिता की परीक्षा में विफल होता पर्यटन विभाग :-** बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि राज्य में पर्यटन के विकास हेतु एक अहम निकाय है, अब भ्रष्टाचार, अनियमितता और वित्तीय कदाचार का केंद्र बनता दिख रहा है। यह प्रकरण केवल कुछ अधिकारियों की जवाबदेही का मामला नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पर सवाल खड़ा करता है। यदि शीघ्र और सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो यह न केवल शासन की छवि को धूमिल करेगा, बल्कि राज्य के पर्यटन विकास प्रयासों को भी गहरा नुकसान पहुंचाएगा। ●

● शशि रंजन सिंह/राजीव कुमार शुक्ला

भारत की सभ्यता और संस्कृति का एक प्रमुख स्तंभ रहा बिहार, प्राचीन काल से ज्ञान, सत्य और सामाजिक न्याय की भूमि माना जाता है। यहाँ सम्राट अशोक ने धर्म और करुणा का संदेश दिया, चाणक्य ने राजनीति और अर्थनीति की आधारशिला रखी, गौतम बुद्ध ने शांति का मार्ग दिखाया और आधुनिक युग में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने सम्पूर्ण क्रांति का बिगुल बजाया। यह भूमि आर्यभट्ट, विद्यापति, बाबू कुंवर सिंह, राजेंद्र प्रसाद और भीमराव आंबेडकर के विचारों को आत्मसात करने वाले आंदोलनों की साक्षी रही है। बिहार की आत्मा हमेशा "सत्य और सेवा" रही है लेकिन इसी गौरवशाली धरती पर भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें जम चुकी हैं। विशेषकर स्वास्थ्य क्षेत्र, जहां गरीब और असहाय जनता जीवन की अंतिम उम्मीद के रूप में सरकार की ओर देखती है, वहीं पर भ्रष्टाचार ने व्यवस्था को खोखला कर दिया है। इसी पृष्ठभूमि में सामने आता है डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे का मामला, जिसने जनता के विश्वास को गहराई से हिलाया है।

भारतीय प्रशासन में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वे पूरे तंत्र को खोखला कर रही हैं। डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे, 2011 बैच के आईएएस अधिकारी, जो कभी स्वास्थ्य विभाग के बड़े पदों पर विराजमान थे, आज भ्रष्टाचार की मिसाल बन चुके हैं। एमबीबीएस से आईएएस बने इस अधिकारी पर गंभीर आरोप हैं :- दवाओं और एम्बुलेंस की खरीद में घोटाले, संपत्ति घोषणा में धोखाधड़ी और आय से कहीं ज्यादा संपत्ति जमा करना। क्या यह अधिकारी जनता की सेवा के लिए आया था या लूटने? महात्मा गांधी की वो बात याद आती है- "भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा दुश्मन लालच है", लेकिन देवरे जैसे लोग लालच को ही अपना धर्म बना लेते हैं। इस तीखे आलेख में हम इन आरोपों की चीरफाड़ करेंगे, दस्तावेजों के आधार पर सच्चाई उजागर करेंगे और समाज की आवाजों से इस घृणित खेल की गहराई दिखाएंगे।

Declaration of Assets and Liabilities

Year 2024-25

I, **Dr. Nilesh Ramchandra Deore** son of Shree R.D.Deore, Aged 39 years, belonging to **Indian Administrative Service (I.A.S.)** service and presently working as **Managing Director, North Bihar Power Distribution Company Limited** give herein below the details of the assets (immovable, movable, bank balance, etc.) of myself, my spouse and dependants*:

A. Details of movable assets

(Assets in joint name indicating the extent of joint ownership will also have to be given)

Sr. No.	Description	Self	Spouse Name(S) (Saee S)	Dependant-1 Name (Ira Deore)	Dependant-2 Name (Sara Deore)
(i)	Cash	Rs. 31,000/-	Smt Saee S has not created any assets out of my income and we do not any joint property.	Rs. 85,000/-	NIL
(ii)	Deposits in Banks, Financial Institutions And Non-Banking Financial Companies	Savings A/C - Rs. 8,13,787/- Fixed deposits - Rs. 26,83,935/- PPF- Rs 26,09,930/-		PPF A/C Rs.15,46,000/- Sukanya Samruddhi A/C Rs. 15,78,501/-	PPF A/C Rs.7,06,000/- Sukanya Samruddhi A/C Rs. 7,20,800/-
(iii)	Bonds, Debentures and Shares in companies	Shares of 19 listed companies worth of Rs. 13,11,868/-		NIL	NIL
(iv)	Other financial institutions, NSS, Postal Savings, LIC Policies, etc	LIC Policy Sum Amount Rs. 2,50,000 Yearly premium Rs 9430 paying since 2009		NIL	NIL
(v)	Motor Vehicles (details of make, etc.)	Hero Honda Hunk Year 2008 worth not assessed		NIL	NIL
(vi)	Jewellery (give details of weight and value)	Gold Jewellery around 150 gm worth 12,00,000 Rs Diamond Jewellery worth of around 2,60,000 Rs		Gold Jewellery around 270 gm worth Rs 21,60,000/- received as gift from grand parents.	Gold Jewellery around 250 gm. Worth Rs. 20,00,000/- received as gift from grand parents.
(vii)	Other assets, such as values of claims / interests	Fridge, Micro Oven, Washing Machine, DVD player, Philips Home system, Split AC worth around 1,50,000 Rs Godrej Home furniture includes 2 Complete Bed Room Sets, Modular Kitchen, Sofa, Coffee Table, Sofa Cum bed, Cot etc worth around 4,50,000 Rs Two Laptops both Sony Vaio makes. One apple laptop worth of 1,09,000 Rs	--	--	--

Note: Value of Bonds / shares / Debentures as per the latest market value in Stock Exchange in respect of listed companies and as per books in the case of non listed companies should be given.

* Dependant here means a person substantially dependent on the income of the employee.

B. Details of Immovable assets

[Note: Properties in joint ownership indicating the extent of joint ownership will also have to be indicated]

Sr. No.	Description	Self	Spouse Name(S)	Dependant-1 Name	Dependant-2 Name
(i)	Agricultural Land - Location(s) - Survey number(s) - Extent (Total measurement) -Current market value	Gram-Tamaswadi Taluka-SakriDistt.-Dhule (MH) Gut no.-104/1 Area-1.63 Hec. Class 2 irrigated land. Current market value- 15 lakh	NIL	NIL	NIL
(ii)	Non-Agricultural Land - Location(s) - Survey number(s) - Extent (Total measurement) -Current market value	Gram- Hartali Taluka-khandala Distt.-Satara(MH) Gut no-299 Area-557.79 sqM C.M.V.- 8 Lakh	NIL	NIL	NIL
(iii)	Buildings (Commercial and residential) Location(s) - Survey /door number(s) - Extent (Total measurement) - Current market value	NIL	NIL	NIL	NIL
(iv)	Houses / Apartments, etc. - Location(s) - Survey /door number(s) - Extent (Total measurement) - Current market value	NIL	NIL	NIL	NIL
(v)	Others (such as interest in property)	NIL	NIL	NIL	NIL

My share in ancestral properties yet to be decided as we are living as joint family.

(2) I give herein below the details of my liabilities / overdues to public financial institutions and government dues:-

[Note : Please give separate details for each item)

Sr. No.	Description	Name & address of Bank / Financial Institutions(s) / Department (s)	Amount outstanding as on 31.03.2019
(a)	(i) Loans from Banks	NIL	NIL
	(ii) Loans from financial institutions	NIL	NIL
	(iii) Government Dues: (a) dues to departments dealing with government accommodation	NIL	NIL
	(b) dues to departments dealing with supply of water	NIL	NIL
	(c) dues to departments dealing with supply of electricity	NIL	NIL
	(d) dues to departments dealing with telephones	NIL	NIL
	(e) dues to departments dealing with government transport (including aircraft and helicopters)	NIL	NIL
	(f) Other dues, if any	NIL	NIL
(b)	(i) Income Tax including surcharge [Also indicate the assessment year upto which Income Tax Return filed. Give also Permanent Account Number (PAN)]	Income tax paid Rs. 3,73,054/- till date with Pan No- AJPPD1513R	NIL
	(ii) Wealth Tax [Also indicate the assessment year upto which Wealth Tax return filed.]	NIL	NIL
	(iii) Sales Tax [Only in case of proprietary business]	NIL	NIL
	(iv) Property Tax	NIL	NIL

C. Personal Detail

GPF/CPF/PRAN No. :- 110092480095

Gender :- M (M/F)

Date of Birth :- 1 3 1 2 1 9 8 5 (DD/MM/YYYY)

Class/Group :- A (A/B/C)

Cadre :- Indian Administrative Service

Home District :- Nashik, Maharashtra

I hereby declare that the above details are true to the best of my knowledge and belief.

Signature -

Name of Employee: Dr. Nilesh R. Deore

Designation: Managing Director

Department: North Bihar Power Distribution Co. Ltd.

Place: New Delhi
Date: 12.02.2025

Note: **Please sign each page of the declaration. Asset declaration form must be in A4 size white paper with computer typed (single side) in prescribed format.**

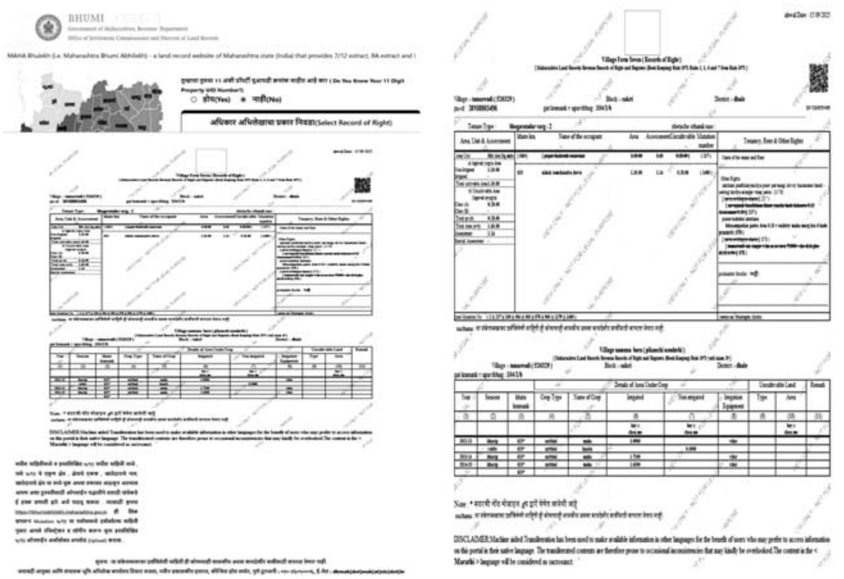

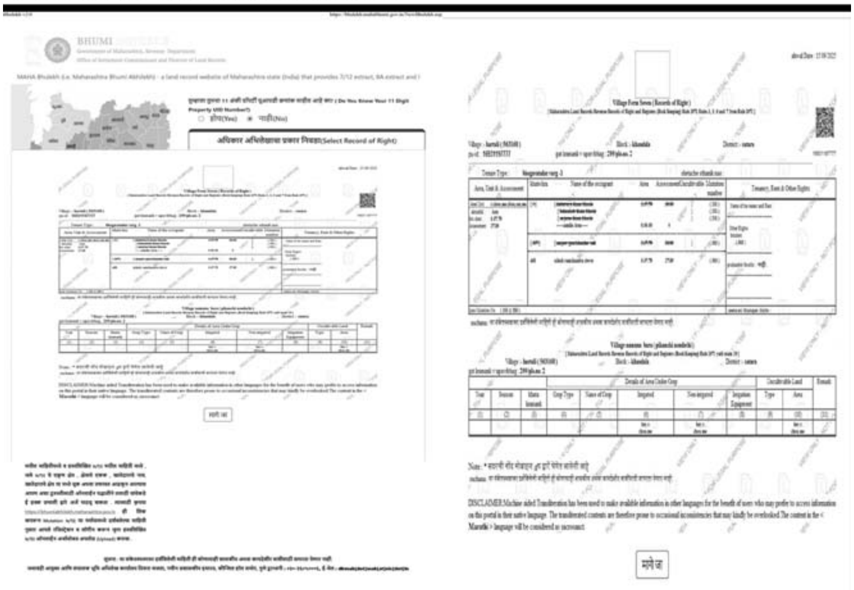

2011 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे ने मुंबई के टॉपिवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहते हुए वे बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMSICL) के प्रबंध निदेशक (MD) जैसे उच्च पद पर कार्यरत हैं। लेकिन इनकी सेवा-यात्रा पर लगे भ्रष्टाचार, गलत संपत्ति घोषणा और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों ने पूरे प्रशासनिक ढांचे की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। BMSICL में देवरे का कार्यकाल घोटालों का अड्डा हो गया है।

❖ **दवाओं की खरीद में कमीशनखोरी, एम्बुलेंस टेंडर में धांधली :-** ये आरोप नहीं, सबूत हैं! 2013 में आईएएस पदोन्नति के लिए जमा फॉर्म में उन्होंने संपत्ति छिपाई, जबकि जांच में पता चला कि उन्होंने निजी फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचाया। क्या स्वास्थ्य जैसी संवेदनशील सेवा में ऐसा खिलवाड़ माफ है? शिकायतें UPSC, DoPT और CVC तक पहुंची हैं, जहां आरोप है कि देवरे ने GEM पोर्टल पर खरीद में नियम तोड़े और करोड़ों की दवाएं बिना जरूरत खरीदीं। एक शिकायत में कहा गया, "देवरे ने 2024 में पदोन्नति के लिए फॉर्म 13(1)(क) में झूठे विवरण दिए, जबकि उनकी संपत्ति आय से 5-7 गुना ज्यादा है।" यह भ्रष्टाचार नहीं, जनता की जान से खिलवाड़ है!

सामाजिक कार्यकर्ता धीरेंद्र सिंह पासवान ने तीखे शब्दों में कहा, "भ्रष्टाचार न केवल पैसा चुराता है, बल्कि लोगों की जिंदगियां भी। देवरे जैसे अधिकारी गरीबों की दवाओं पर डाका डालते हैं!" उनकी यह आवाज बिहार की राजनीति में गूंज रही है, जहां स्वास्थ्य तंत्र की लूट आम है।

❖ **भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग :-** देवरे पर आरोप है कि BMSICL में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद-फरोख्त में गंभीर अनियमितताएँ कीं :-

☞ निजी कंपनियों को लाभ पहुँचाने के लिए नियमों की अनदेखी की गई।

☞ दवाओं की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रही।

☞ कमीशन लेने के आरोप कई शिकायत पत्रों में दर्ज हैं।

यह स्थिति केवल भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि गरीब जनता के स्वास्थ्य अधिकारों पर सीधा हमला है। जब स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार होता है, तब गरीब मरीजों को दवाएँ नहीं मिलतीं, अस्पताल खाली रहते हैं और मौतें बढ़ती हैं। महात्मा गांधी ने कहा था-"भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा दुश्मन लालच है।" दुर्भाग्य से इस मामले में लालच ने सेवा भावना को पूरी तरह निगल लिया।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए हर पदोन्नति से पूर्व संपत्ति का सटीक विवरण (Asset Declaration) देना अनिवार्य है :-

☞ 2013, 2024 और 2025 में देवरे पर गलत विवरण देने के आरोप हैं।

☞ अपनी पत्नी के सम्पत्ति का विवरण उन्होंने एसेट डिक्लेरेशन में नहीं दिया।

☞ महाराष्ट्र के धुले और सातारा जिलों में उनके और रिश्तेदारों के नाम पर दर्ज कृषि भूमि करोड़ों की कीमत की है। इस प्रकार की गलत घोषणाएँ न केवल सेवा नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि यह प्रशासनिक नैतिकता के लिए भी खतरे की घंटी है।

❖ **आय से अधिक संपत्ति : लालच की पराकाष्ठा :-** शिकायतों और रिपोर्टों में यह आरोप बार-बार दोहराया गया है कि देवरे की कुल संपत्ति उनकी ज्ञात आय से पाँच से सात गुना अधिक है :-

☞ **महाराष्ट्र में भूमि :** 80 एकड़ से अधिक कृषि भूमि, मूल्य 2-3 करोड़ रुपये।

☞ **बैंक और निवेश : लाखों के संदिग्ध लेनदेन :-** पूर्व प्रवर्तन अधिकारियों का कहना है, "जब किसी अधिकारी की संपत्ति उसकी आय से मेल न खाए, तो यह मनी लॉन्ड्रिंग और

धीरेन्द्र सिंह पासवान

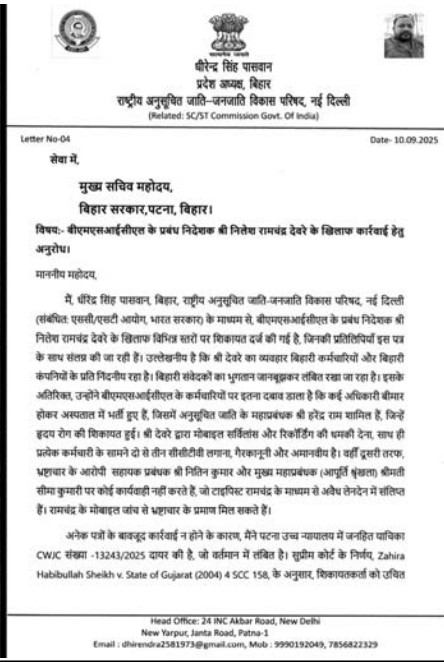

धीरेन्द्र सिंह पासवान
प्रदेश अध्यक्ष, बिहार
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति–जनजाति विकास परिषद, नई दिल्ली
(Related: SC/ST Commission Govt. Of India)

Letter No-04 Date- 10.09.2025

सेवा में,

मुख्य सचिव महोदय,
बिहार सरकार,पटना, बिहार।

विषय:- बीएमएसआईसीएल के प्रबंध निदेशक श्री नितेश रामचंद्र देवरे के खिलाफ कार्रवाई हेतु अनुरोध।

माननीय महोदय,

मैं, धीरेंद्र सिंह पासवान, बिहार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति विकास परिषद, नई दिल्ली (संबंधित: एससी/एसटी आयोग, भारत सरकार) के माध्यम से, बीएमएसआईसीएल के प्रबंध निदेशक श्री नितेश रामचंद्र देवरे के खिलाफ विभिन्न स्तरों पर शिकायत दर्ज की गई है, जिनकी प्रतिलिपियाँ इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि श्री देवरे का व्यवहार बिहारी कर्मचारियों और बिहारी कंपनियों के प्रति निंदनीय रहा है। बिहारी संवेदकों का भुगतान जानबूझकर लंबित रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बीएमएसआईसीएल के कर्मचारियों पर इतना दबाव डाला है कि कई अधिकारी बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के महाप्रबंधक श्री हरेंद्र राम शामिल हैं, जिन्हें हृदय रोग की शिकायत हुई। श्री देवरे द्वारा मोबाइल सर्विलांस और रिकॉर्डिंग की धमकी देना, साथ ही प्रत्येक कर्मचारी के सामने दो से तीन सीसीटीवी लगाना, गैरकानूनी और अमानवीय है। वहीं दूसरी तरफ, भ्रष्टाचार के आरोपी सहायक प्रबंधक श्री नितिन कुमार और मुख्य महाप्रबंधक (आपूर्ति श्रृंखला) श्रीमती सीमा कुमारी पर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं, जो टाइपिस्ट रामचंद्र के माध्यम से अवैध लेनदेन में संलिप्त हैं। रामचंद्र के मोबाइल जांच से भ्रष्टाचार के प्रमाण मिल सकते हैं।

अनेक पत्रों के बावजूद कार्रवाई न होने के कारण, मैंने पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका CWJC संख्या -13243/2025 दायर की है, जो वर्तमान में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, Zahira Habibullah Sheikh v. State of Gujarat (2004) 4 SCC 158, के अनुसार, शिकायतकर्ता को उचित

Head Office: 24 INC Akbar Road, New Delhi
New Yarpur, Janta Road, Patna-1
Email : dhirendra2581973@gmail.com, Mob : 9990192049, 7856822329

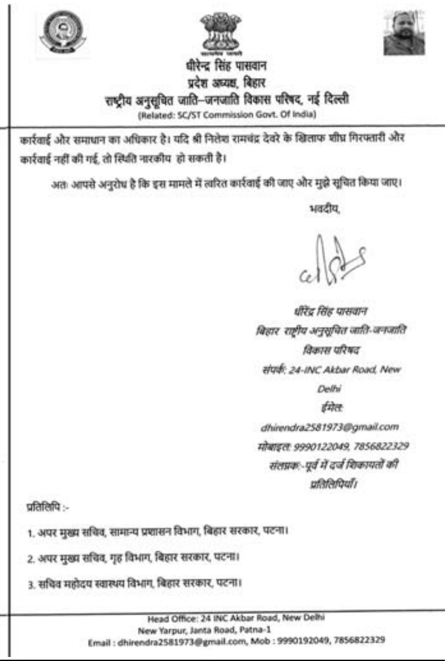

धीरेन्द्र सिंह पासवान
प्रदेश अध्यक्ष, बिहार
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति–जनजाति विकास परिषद, नई दिल्ली
(Related: SC/ST Commission Govt. Of India)

कार्रवाई और समाधान का अधिकार है। यदि श्री नितेश रामचंद्र देवरे के खिलाफ शीघ्र गिरफ्तारी और कार्रवाई नहीं की गई, तो स्थिति नारकीय हो सकती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए और मुझे सूचित किया जाए।

भवदीय,

धीरेंद्र सिंह पासवान
बिहार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति विकास परिषद
संपर्क: 24-INC Akbar Road, New Delhi
ईमेल: dhirendra2581973@gmail.com
मोबाइल: 9990122049, 7856822329
संलग्नक:-पूर्व में दर्ज शिकायतों की प्रतिलिपियाँ।

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. सचिव महोदय स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।

Head Office: 24 INC Akbar Road, New Delhi
New Yarpur, Janta Road, Patna-1
Email : dhirendra2581973@gmail.com, Mob : 9990192049, 7856822329

भ्रष्टाचार का पक्का संकेत है।"

❖ **समाज की प्रतिक्रिया और जनआक्रोश :-** भ्रष्टाचार के इस मामले पर समाज के विभिन्न वर्गों में गहरा आक्रोश है–

☞ **सामाजिक कार्यकर्ता :-** "भ्रष्टाचार केवल सरकारी धन की चोरी नहीं है, यह गरीबों की जिंदगी की चोरी है।"

☞ **महिला अधिकार संगठनों की आवाज :-** "स्वास्थ्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार का सीधा असर महिलाओं और बच्चों के जीवन पर पड़ता है।"

☞ **युवा वर्ग :-** "भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई किए बिना बिहार का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता।"

☞ **वरिष्ठ राजनेता और चिंतक :-** "भ्रष्टाचार बिहार की राजनीति और प्रशासन दोनों की विश्वसनीयता पर हमला है।"

स्वामी विवेकानंद ने कहा था, "भ्रष्टाचार राष्ट्र का कैंसर है"। आज यह कैंसर बिहार की स्वास्थ्य प्रणाली को खोखला कर रहा है।

❖ **बिहार के महानुभावों की सीख :-**

☞ **चाणक्य :-** "राजनीति का मूल उद्देश्य लोककल्याण है।"

☞ **लोकनायक जयप्रकाश नारायण :-** "जनता जब भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ खड़ी होती है, तब बदलाव निश्चित होता है।"

☞ **डॉ. राजेंद्र प्रसाद :-** "लोकतंत्र तभी टिक सकता है जब जनता जागरूक और सशक्त हो।"

यह सीख हमें याद दिलाती है कि बिहार की जनता ने हमेशा अन्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई है। डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे का मामला केवल व्यक्तिगत आरोप नहीं है, बल्कि यह बिहार की प्रशासनिक प्रणाली की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न है। जब तक UPSC, DoPT, CVC और बिहार सरकार इस पर निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई नहीं करते, तब तक जनता का भरोसा टूटता रहेगा। अब यह जनता और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है कि बिहार की गौरवशाली परंपरा को बचाया जाए। यह समय है भ्रष्टाचार को समाप्त करने और एक नए, पारदर्शी और न्यायपूर्ण बिहार की नींव रखने का।

डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे

बिहार की पहचान हमेशा से ज्ञान, सत्य और संघर्ष की रही है। यही भूमि थी जहाँ सम्राट अशोक ने धम्म और करुणा का संदेश दिया।

☞ चाणक्य ने राजनीति और अर्थनीति के सूत्र लिखे।

☞ आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान की नींव रखी।

☞ गौतम बुद्ध ने शांति और मध्यम मार्ग का प्रचार किया।

☞ लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने सम्पूर्ण क्रांति का बिगुल फूंका।

यह गौरवशाली धरती हमें सिखाती है कि "सत्य और न्याय ही समाज का वास्तविक आधार है" लेकिन आज यही धरती भ्रष्टाचार के बोझ से कराह रही है, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में, जहाँ जनता की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है।●

जीत हमारी तय है, बनायेंगे सरकार : तेजस्वी

● सोनू यादव

बिहार में बहुत जल्द विधान सभा के चुनाव होने हैं और 243 सीटों की दलीय भिडंत को लेकर एनडीए, इंडी गठबंधन सहित जनसुराज सभी सीटों पर अपनी जीत का ताल ठोक रहे हैं, पर चुनावी परिणाम क्या होंगे, यह अभी कह पाना मुश्किल होगा। हालांकि वोट चोरी का बड़ा मुद्दा बनाकर इंडी गठबंधन नेताओ ने खूब लोकप्रियता हासिल की है, कहना गलत ना होगा। किंतु वोट चोरी को लेकर इतनी बड़ी वोटर अधिकार यात्रा का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गाँधी और बिहार विधान सभा में विरोधी दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार तेजस्वी यादव के लिए जनता के विश्वास पर खड़ा उतर पाना कितना सफल होगा, ये चुनावी परिणाम बतायेंगे। बात अगर एनडीए सरकार की करे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सड़कों और पुलों का शिलान्यास व उद्घघाटन के साथ ही हर नये दिन महिलाओं और युवाओं को प्रोत्साहन को लेकर रोजगार की घोषणा कर कैबिनेट मंजूरी दिलाकर अमल में लाया जा रहा है। इससे आवाम में सरकार के प्रति विश्वास जग रहे हैं। इन तमाम गतिविधियों को लेकर केवल सच के पत्रकार सह सामाजिक कार्यकर्ता सोनू यादव ने पूर्व उप मुख्यमंत्री एवम आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तथा राज्यसभा सांसद संजय यादव से शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा की इस बार हम एनडीए की सरकार की तख्त हिला देंगे। जिस प्रकार नीतीश कुमार जी और सहयोगी बीजेपी ने रोजगार और शिक्षा का झूठ फैलाकर जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं किंतु बिहार के युवा इसबार उनको हार का मुह दिखाने का कार्य करेगी। हमने पहले ही कहा है की हमारी इंडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और हम माई बहन योजना को अमल में लायेंगे। वही संजय यादव जो 2024 से बिहार से राज्यसभा के सांसद के रूप में कार्यरत हैं एवम राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सदस्य हैं, तथा तेजस्वी यादव के वरिष्ठ राजनीतिक सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने केन्द्र की मोदी सरकार के सह पर बिहार के मतदाताओं के नाम काटे जाने को लेकर निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाते हुए बिहार में इंडी गठबंधन द्वारा किये गए वोटर अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए तेजस्वी यादव और राहुल गाँधी के साथ ही इंडी गठबंधन के नेताओ को धन्यवाद दिया। संजय यादव ने साफ कहा की जीत हमारी तय है और तेजस्वी जी बहुत जल्द बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं।●

पुरानी पेंशन के लिए विशाल रैली का आयोजन

● **श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव**

कर्मचारी-शिक्षक ने पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर पटना के मिलर स्कूल मैदान में हुंकार भरी। 'वोट फॉर OPS' एवं 'पेंशन चोर-गद्दी छोड़' के नारे से मिलर स्कूल मैदान गूंज उठा। पुरानी पेंशन बहाली हेतु प्रतिबद्ध राष्ट्रीय संगठन (NMOPS) की बिहार इकाई द्वारा NPS और UPS का लगातार विरोध किया जा रहा है। कुछेक महीनों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के दरम्यान इस आंदोलन को और सशक्त बनाने के लिए दिनांक 14/09/2025, रविवार को मिलर स्कूल मैदान पटना में महारैली का सफल आयोजन किया गया। इसमें पूरे बिहार के लाखों NPS कर्मियों ने भाग लिया।

इस महारैली को NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु, राष्ट्रीय महासचिव श्री स्थित प्रज्ञा, भाकपा माले के सांसद कॉमरेड राजाराम सिंह, विधान पार्षद श्रीमती शशि यादव, गोप गुट के सम्मानित अध्यक्ष रामबली प्रसाद, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत सिंह, हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर, बिहार अध्यक्ष वरूण पांडेय, AICCTU के राष्ट्रीय सचिव रणविजय कुमार, बिहार के शिक्षक नेता नागेन्द्र सिंह, मार्कण्डेय पाठक, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे एम्पलाई यूनियन के जोनल अध्यक्ष संतोष पासवान के साथ-साथ कई संघों के अध्यक्ष एवं महासचिव सहित सभी जिला के अध्यक्षों द्वारा इस सभा को संबोधित किया गया। सभी वक्ताओं द्वारा एक सुर से बिहार सरकार से पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की अपील की गई। इस मंच से बिहार सरकार को खुली चुनौती दी गई की अगर बिहार सरकार अपने सरकारी सेवकों को पुरानी पेंशन नहीं देती है तो इस स्थिति में सभी सरकारी कर्मियों द्वारा इस का विरोध किया जाएगा एवं सरकार को बदलकर पुरानी पेंशन लिया जाएगा।

इस मंच का संचालन संजीव तिवारी, मनोज कुमार यादव, राजीव रंजन एवं संतोष कुमार ने सम्मिलित रूप से किया। जहानाबाद जिला से संदीप पासवान, मुकेश भारती, संतोष कुमार, रवि कुमार, रामसुन्दर कुमार सहित हजारी शिक्षकों ने अपनी आवाज को पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर बुलंद किया। ●

बिहार की जनता चाहती है बदलाव : तुषार गांधी

● श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव

महात्मा गांधी के पपौत्र तुषार गांधी ने कार्यक्रम में मसौढ़ी सौभाग्य उत्सव हॉल में शिरकत किए। बिहार में लेकर बिहार साझा मंच के तत्वाधान में मसौढ़ी के दमड़ीचक स्थित सौभाग्य उत्सव हॉल में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की दिशा में बिहार को नयी दशा देने के लिए जनता को जागरुक करने के उद्देश्य से 'सत्ता से सवाल, बदलो सरकार' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, बुद्धिजीवी और राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मंच पर बिहार प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं की उपस्थिति आयोजन को विशेष बना दिया। इस कार्यक्रम में गांधीवादी विचारक तुषार गांधी ने कहा कि समाज को पारदर्शी व्यवस्था की आवश्यकता है, जहां हर नागरिक की आवाज सुना जाए। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर बिहार में बदलाव लाना है, उसके लिए जनता को संगठित होना होगा। इस अवसर पर पूर्व बिहार विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार की जनता बदलाव की पक्षधर रही हैं। यह साझा मंच जनता की आवाज को बुलंद करने का एक अच्छा प्रयास है। मसौढ़ी एवं दीघा की पूर्व विधायक पूनम देवी कार्यक्रम की

अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि आज का यह मंच सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार से अपेक्षा है कि वह जनता के हितों को सर्वोपरि रखे और के सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व दें, जिससे समाज के दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग एवं शोषित वर्ग के लोगों का उत्थान हो सके।

कार्यक्रम का संचालन रमाकांत रंजन ने किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय नेता सुनिलम, फुलवारीशरीफ विधायक गोपाल रविदास, शुभ मूर्ति (संयुक्त किसान मोर्चा), पंकज कुमार सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। महात्मा गांधी बापू ने जिस बिहार का सपना देखा था, वह अभी अधूरा है। बापू के सपने को साकार करना है। मुख्य वक्ताओं में प्रतीक पटेल, बिट्टू यादव, उमेश शर्मा, सोनेलाल, सिपाही यादव, शशि यादव, पालटन सिंह, दिलखुश सहित कई गणमान्य लोगों ने अपने विचारों से जनसमूह को प्रेरित किया। अंत में शिवपूजन सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया कार्यक्रम में सामाजिक आर्थिक मुद्दों, किसानों के अधिकार और बेहतर शासन पर गहन चर्चा की गयी।●

APK लिंक भेजकर ठगी करने वाले तीन गिरफ्तार

● श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव

पटना में APK लिंक भेजकर डरा धमकाकर ठगी करने वाले को साइबर थाना पुलिस ने MEESHO और APK लिंक भेजकर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पटना साइबर थाना के डी. एस.पी. नीतीश चन्द्रधारिया ने बताया कि साइबर अपराधियों द्वारा रुपए निकालने के लिए लड़के हायर किए थे। वह एटीएम के आसपास दिन भर रहते थे। पुलिस ने छापेमारी कर तीन अपराधियों अभय कुमार (29, बेतिया के बंसवरिया), नीतीश कुशवाहा (23) और राहलु सिंह (27, गोपालगंज कटेया) को गिरफ्तार किया है। साइबर थाना डी.एस.पी नीतीश चंद्रधारिया ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया की साइबर अपराधी अब व्हाट्स ऐप पर एपीके फाइल भेजकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। इन फाइलों को सरकारी संस्थाओं के नाम से भेजा जा रहा है, जिससे फोन का पूरा एक्सेस ठगों के पास चला जाता है। इसके बाद खाते में जमापूंजी हो या निजी डेटा, अपराधी सारी चीजें उड़ा लेते हैं। पुलिस ने लोगों को इस खतरे के प्रति जागरुक किया है। ठग लोगों को उनके व्हाट्स ऐप नंबर पर सरकारी योजनाओं, बैंक खाता या एटीएम अपडेट, शादी के निमंत्रण पत्र, KYC, बिजली-पानी के बिल समेत अन्य की पीडीएफ की तरह एपीके फाइल बनाकर भेज रहे हैं। हमें मोबाइल पर अनजान नंबर से भेजे लिंक को कभी नहीं टच करना है। APK लिखा हुआ फाइल को भी नहीं खोले। हाल ही में एक शिक्षक के खाते से 12 लाख रूपये की ठगी APK फाइल खोलने से हुआ है। इसलिए हम सजग और सतर्क रहें।●

भाजपा-जदयू क्यों नहीं रोकना चाहती हैं अपराध और भ्रष्टाचार?

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

बिहार के भाजपाई और जदयू क्यों नहीं रोकना चाहती है अपराध और भ्रष्टाचार छिपा है रहस्य? अपराधी और भ्रष्टाचारी उनके वोटर हैं। अपराधी और भ्रष्टाचारियों के पास जितना वोट है इतना वोट सामान्य व्यक्ति के पास नहीं है। चुनाव में एक एक वोट का भी काफी महत्व है। जनता को मूर्ख बनाने के लिए कभी कहेगा कि कानून और टाइट कर दिया गया है। जनता को मूर्ख बनाने के लिए भ्रष्टाचारियों को तबादला कर दी जाती है। तबादला के नाटक के बाद क्या भ्रष्टाचारी सत्य हरिश्चन्द्र बन जाती है। भ्रष्टाचारी बिहार की समृद्धि को खोखला करने पर लगे हैं। सत्ता के चापलूसों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। प्रखंड स्तर से लेकर राज्यस्तर के कर्मचारी और अधिकारी दिन रात अपराध को बढ़ाने में लगे हैं। कोई भी काम किसी भी कार्यालय में बगैर घूस

दिए नहीं होता है। जनता परेशान है लेकिन भाजपा और सत्ता में बने रहने के उपाय ढूंढने में लगी है। क्योंकि भाजपा में भ्रष्ट नेताओं की भरमार है। बताया जाता है भारी संख्या में निर्दोष व्यक्ति को जेल भेजा जाता है। थाना एक दिन में निर्दोष साबित कर जेल से छूटकारा एक दिला सकता है परन्तु नयायालय से निर्दोष सावित करने में दो, चार, दस साल भी लग सकता है। प्रखण्ड में सबसे बड़ी समस्या आती है जन्म प्रमाण पत्र। माता पिता से ज्यादा जन्म का समय कौन जान सकता है। मंत्री डांट दे कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए बदमाशी करोगे। एक मिनट में समस्या समाप्त हो जाएगी। जाती कभी बदलाता है कि बार बार जाती प्रमाण पत्र मांगा जाता है। मंत्री एक डांट में समाप्त हो जाएगी। ऐसी समस्या को यदि भाजपा बनाए रखना चाहता है तो भाजपा के वोट मत दो बदलाव कर जन सुराज को वोट दें।●

सत्ता की मलाई चाभने के लिए नहीं आया हूँ

बुराइयों से लड़ने का औजार है राजनीति : डॉ. लक्ष्मीनारायण सिंह पटेल

● त्रिलोकी नाथ प्रसाद

फतुहा के नामी होमियोपैथीक चिकित्सक सह भाजपा नेता डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह पटेल ने अपने राजनीति में आने के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि, मेरा भाजपा में आने कारण सत्ता के मलाई चाभने के लिए नहीं बल्कि अन्याय के बिरुद्ध दो-दो हांथ करने के लिए आया हूँ। हमारे देश के नेता असाधारण प्रतिभा के होते हैं, लेकिन देश को समाज को प्रेरित करने की अपनी क्षमता के कारण नहीं बल्कि निचता, संकीणर्ता, निकम्मेपन, बेईमानी के कारण कोई भी संवेदनशील नागरिक आज अपने नेताओं को मुख्यत: चार वर्गो में बांटकर देखता है। स्वाभिमानी नेता, कमीशनखोर नेता, मौसमी नेता और ईमानदार नेता।

स्वाभिमानी नेता का पोशाक से पहचान नहीं होती है। स्वाभिमानी नेता को अन्याय के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला को धधकने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया में आज तक जो भी स्वाभिमानी नेता हुए उनका पहचान पोशाक से नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद,भगत सिंह, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, राम मनोहर लोहिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामाप्रसाद प्रसाद मुखर्जी नेता हुए उनका पहचान कपड़ा नहीं स्वाभिमान था। स्वाभिमानी नेता धनहीन और अभावग्रस्त रह सकते हैं किंतु उनके मन में शांति और संतोष होता है। उनका चरित्र निर्माण पृष्ठभूमि पर आधारित होता है। उन्हें यह झीझक या संदेह नहीं रहता की कोई किसी दिन आकर उसके बेईमानी को पकड़ लेगा और उनका मानहानि होगी। दूसरे होते हैं कमिशनखोर नेता जिनके जोशीले नारों और ख्वाबों से अभिभूत होकर आप उन्हें अपना कर्नहआर मानकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा देते हैं। कुर्सी मिलते ही विकास योजनाओं में बनी बनाई कमीशन मिलना शुरू हो जाता है। यह कड़वा सच है कि आज के युग में माननीय बनना सबसे मुनाफे का पेशा है। यह आम धारणा बन गई है कि जिस राज्य में इतना ज्यादा विकास योजनाएं बनेगी उतना ही वहां के नेता खुशहाल होंगे। क्योंकि उन्हें मोटा

कमीशन मिलेगा तथा कमीशन के पैसे से अपनी मांसपेशियां मजबूत के अलावा उनके पास महलों और गाडियों की कतारे सज जाती है। तीसरी हैं मौसमी नेता तो सड़कों को शोभा बढ़ाने वाला इंसानियत के सारे बस्त्र उतार कर राजनीति के समुद्र में धन बटोरने के लिए गोता लगाते रहते हैं। अपने विषैले दांत से विकास योजना पर डंक मार कर एक कतरा चूसने के लिए बेताब रहते हैं। इनका प्रत्येक चुनाव में महत्व बढ़ जाता है। प्रत्याशी दुलहे की तरह सजते हैं तो मौसमी नेता प्रत्याशी के बारात में जाने के लिए तरह-तरह से सज कर शोभा बढ़ाते चलते हैं। मौसमी नेता का नहीं कोई स्वाभिमान होता है और नहीं अन्याय, चोरी, घूसखोरी, कालाबाजारी के विरोध करने का साहस होता है। एक दूसरे को आंखों में धूल झोककर सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं विकास योजनाओं के पैसे बटोर कर महल बनाने के फिराक रहते हैं। नीती शास्त्र में कहा गया है कि एक लज्जा का त्याग देने से आप सर्वत्र सुखी हो जाएंगे। सत्ता के सभी दलों के नेताओं ने अपने सारे वसत्र उतार कर फेक दिया है।

राजीव गांधी ने भी यह स्वीकार किया था कि सरकारी योजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि का सिर्फ 15% ही वास्तव में खर्च होता है । जबकि 85% हिस्सा नेता, अधिकारी और उनके दलाल हड़प जाता है। मोदी जी की नीतियां अच्छी ही नहीं बहुत अच्छी है। क्योंकि लूट खसोट ,गवण ,घोटाला, कमीशन खोरी ,कालाबाजारी ,घूसखोरी विकास योजना में गुणवत्ता, उनको पोषण अशिक्षा के लिए त्राहि त्राहि होने के बावजूद सत्ता धारियों में कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। समुचे बिहार में अपराध से चित्कार मची है दूसरी ओर भ्रष्टाचार का साम्राज्य होने के बावजूद भाजपाई को नींद हराम नहीं हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनहित में 300 से ज्यादा योजनाएं चलाई जा रही है अधिकांश योजनाएं सरकारी फाइलों की शोभा बढ़ा रही है तथा लूट खसोट का भेंट चढ़ रही है। डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा बड़े बड़े पद पर बैठे भाजपाईयों से दो हाथ करना पड़ रहा है।●

भाजपा में ईमानदारों की खैर नहीं, बेइमानों से वैर नहीं

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

बिहार के पूर्व सहकारिता मंत्री औरंगाबाद के पूर्व विधायक रामाधार सिंह ने भाजपा छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा छोड़ेंगे तथा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को इस्तीफा सौंपेंगे। पूर्व मंत्री ने कहा

कि उन्होंने भाजपा को अपने खून पसीने से सींचा है लेकिन अब भाजपा की राजनीति से संन्यास लेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा को खड़ा करने के लिए उन्होंने 30 बीघा जमीन बेची थी। अब भाजपा को बर्बाद करने के लिए 60 बीघा जमीन बेंच सकते हैं। यह दर्द छलकने का प्रमाण है कि ईमानदारों का भाजपा में खैर नहीं है तथा बेईमानों से बैर नही है।●

पीएमसीएच में दलालों का गिरोह सक्रिय

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में आपरेशन जैसा महंगा हो गया है। कारण ओपीडी से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक दलालों का सक्रीय सिंडिकेट यहां भर्ती मरीजों और उनके परिजनों का आरोप है कि यह सिंडिकेट है,डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से चलता है। हड्डी टूटने जैसी सामान्य सर्जरी के लिए भी इंप्लांट राड और प्लेट के साथ ही दवाएं और एनेस्थेसिया बाहर से मंगवाई जाती है। मरीजों को यह सामान खरीदने के लिए कुछ दलालों के माध्यम से विशेष मेडिकल स्टोर पर भेजा जाता है जहां काफी अधिक रकम वसूली जाती है।

☞ **केस नंबर 1 :-** मनोज ने बताया कि मोटरसाइकिल दुर्घटना में उनके बहनोई सुजीत कुमार गुप्ता के दोनों पैर की हड्डी टूट गई थी। पैसे की अभाव में उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर ई ओ 2548 था। यहाँ कहा गया है कि दोनों पैरों का ऑपरेशन करना होगा। इंप्लांट रड लगाने होंगे। जूनियर डॉक्टर ने एक व्यक्ति से बात करवा दी और कहा कि इसी के पास पैसे जमा कर दीजिए। यह इंपलाट लाकर दे देगा। उस व्यक्ति ने दोनों पैरों में लगाने के लिए इंप्लांट लाकर दिए। एक पैर का 17000 रुपए और दूसरे पर का 24000 रुपए था। उसने एक प्राइवेट स्टोर के नाम से रसीद दी। इसकी कीमत दूसरी जगह पता की तो 3500 रुपये की थी दवाएं और बेहोश करने के लिए 1800 रुपए की दवा मंगवाई गई, जिसका प्रमाण उनके पास मौजूद है।

☞ **केस नमबर 2 :-** मरीज सोनाली के बाएं पैर का ऑपरेशन होना है। वेहद गरीब परिवार के सोनाली के परिजनों को बताया गया कि पैर में राड लगते होंगे जो पीएमसीएच में नहीं मिलता है उसे बाहर से खरीदना होगा। जूनियर डॉक्टरों ने एक दलाल से मिलवाया है जिसने बताया कि 36 हजार रुपये लगेगें। बाहर में पता किया तो वही रोड 3000 से 4500 रुपए का बताया गया डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करवाना है तो वहीं से इंप्लांट लाना होगा जहां से बताया गया है। एक अन्य मरीज के परिजन रणजीत राम ने बताया कि उनके बेटे को ऑपरेशन के लिए 28000 रुपए का इंप्लांट और 16000 रुपए का दवाई मंगवाई गई। उनका आरोप है कि एक तो ऑपरेशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। उस पर भी इतना अधिक पैसा लग जाता है।●

पहले कट्टर विरोधी होते हुए भी एक ही गाड़ी से प्रचार के लिए निकलते थे लहटन चौधरी और परमेश्वर कुंअर

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

राजनीति में कटुता, बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप आम बात है, आज के समय में विरोधी दलों के नेता एक दूसरे से नजरे मिलाने तक से बचते हैं, लेकिन कोसी में एक ऐसा दौड़ भी था, जब चुनाव में कांटे की टक्कर के बावजूद नेताओं के रिश्ते निजी स्तर पर मधुर रहते थे। यह कहानी है लहटन चौधरी और परमेश्वर कुंअर की।

दो स्वतंत्रता सेनानी, दो बड़े जननेता और दो कट्टर प्रतिद्वंद्वी जिन्होंने अपनी राजनीति को कभी व्यक्ति कड़वाहट में नहीं बदला। उस दौर में न तो चुनाव में पैसा बाहुबल हावी था और नहीं कटु प्रचार। चुनाव में हार के बाद ही मनाते थे जश्न। सुपौल से 1952 में लहटन चौधरी विधायक चुने गए। 1957 और 62 में परमेश्वर कुंअर जीते चुनाव में। दोनों एक दूसरे को पराजित करते रहे। दशकों तक दोनों के बीच कांटे के मुकाबले रहा, दूसरी ओर दोनों के बीच आपसी संबंध भी उतना ही

प्रगाढ़ था। लहटन चौधरी से हारने के बाद परमेश्वर कुंअर और परमेश्वर कुंअर हारन के बाद लहटन चौधरी जलेबी मंगाकर प्रतिद्विंद्वी की जीत का जश्न मनाते थे।हार पर मिठाई, जीत पर बधाई। जब भी चुनाव परिणाम आते हारने वाला मिठाई बाटते, लहटन चौधरी हारते तो कुंअर जी के घर मिठाई भेजी जाती। कुंवर जी हारते तो लहटन चौधरी के गांव में जलेबी बांटकर जश्न मनाते।

आज की राजनीति के लिए सबक आज राजनीति में अक्सर दुश्मनी बन जाता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मतभेद लोकतंत्र की खूबसूरती है,मनभेद नहीं,लहटन चौधरी और परमेश्वर कुंअर ने दिखाया कि राजनीति का असली मतलब है जनता के साथ रहना चाहे एक आपस में कितने भी बड़े प्रतिद्वंद्वी हो। डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि धन्य थे पहले के लोग।●

यूरिक एसिड की होम्योपैथी में है कारगर इलाज

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

भाजपा कार्यालय मां तारा उत्सव पैलेस गोविंदपुर पटना में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया इसका मुख्य उदेश्य यूरिक एसिड और उसकी होम्योपैथिक चिकित्सा। इस आयोजन का अध्यक्षता पूर्व भाजपा फतुहा नगर मंडल के मंत्री अकुंश कुमार, मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध होमियोपैथी चिकित्सक डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल। मुख्य अतिथि डॉ० लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि आजकल यूरिक एसिड बीमारी का संख्या तेजी से बढती जा रही है। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी में यूरिक एसिड का कारगर दवा है। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी में लक्षण के आधार पर दवा दी जाती है। कभी-कभी यूरिक एसिड के साथ गठिया आदि जुड़ जाने के कारण परेशानियां बढ़ जाती है जिसका भी होम्योपैथी में है :-

☞ बहुत दर्द होना जोड़ो में सूजन लाल पीला

मांसपेशियों में दर्द, कट कट आवाज होना दवा का नाम कालचिकम 30 एक बूंद तीन बार रोज।

☞ उच्च स्तर पर बढे हुए यूरिक एसिड के लिए लीडम पाल 30 बहुत बेहतर है। एक बूंद तीन बार रोज।

☞ रोगी को गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पुराने यूरिक एसिड की बीमारी। सिर ,गर्दन तक दर्द पहुंच जाती है। ग्वायकम 30 एक बूंद तीन बार रोज।

☞ पेशाब गहरा भूरा एवं अत्यंत दुर्गंध पूर्ण होता है। सच तो यह है कि जिस व्यक्ति ने इस दवा के रोगी को यदि एक बार भी पेशाब देखा है उसे जीवन भर याद रहेगी। वेंजोइक एसिड, 6/12/30 एक बूंद तीन बार रोज लेना चाहिए। कोई भी दवा चिकित्सा के सलाह से इस्तेमाल करें।

इस अवसर पर रेखा शर्मा सीमा कुमारी, अनामिका पटेल, मिल्ली, कुमारी, शोभा पटेल। अरुण पटेल आदि शामिल हुए। ●

बच्चों के लिए खतरे की घंटी है स्मार्टफोन

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

जर्नल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कैपिटल एबिलिटी में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक यदि 12 साल या इससे कम उम्र के बच्चों को स्मार्ट फोन दिया जाता है तो उनमें 24 साल के उम्र तक आते-आते आत्मघाती विचार, आक्रमाता, भावनात्मक विचार, आक्रामकता भावनात्मक स्थिरता और काम आत्म सम्मान की शिकायतें ज्यादा देखी जाती है। यह बताया जाता है कि बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल स्पेस बनाने या 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने जैसी नीतियों की कितनी आवश्यकता है इस दिशा में ऑस्ट्रेलिया के कॉफी अच्छा काम किया है उसने अपने संसद में एक ऐसा विधेयक पारित किया इसका उद्देश्य 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना था उसने कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित कर दिया है। यह एक जरूरी कदम है क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में ही यह इस दिशा में काम हो रहा है। फ्रांस, नीदरलैंड इटली, न्यूजीलैंड जैसे देशों में स्कूलों में स्मार्टफोन पर

प्रतिबंध लगा दिया है या फिर इसका प्रयोग काफी सीमित कर दिया है। अमेरिका के ही कई राज्यों के स्कूलों में स्मार्टफोन का उपयोग का सीमित करने वाले कानून बनाए जा चुके हैं। ऐसे में यह समझ जा सकता है कि अपने देश में भी ऐसी व्यवस्था की कितनी जरूरत है। भारत की बात करें तो यहां बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन दिखता है कई मां-बाप तो खुद बच्चों को फोन थमा देते हैं ताकि वे उनकी परेशानी को सबक न बने।यह गलत प्रवृत्ति है इसका कितना नुकसान होता है यह तमाम अध्ययनों से साबित हो चुका है कि नए शोध में ही बताया गया है कि बच्चों को स्मार्टफोन देना उसकी उनकी शराब और तंबाकू जैसे नशे का आदि बनाना है। ऐसे में जरूरत ही है कि हम अपने बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रखें हमारी सरकार को भी चाहिए कि वह ऐसा नियम बनाएं की बच्चों को मोबाइल की जरूरत नहीं है। इस मामले में सामाजिक जागरूकता भी बढ़ानी होगी और स्कूलों को यह निर्देश देना होगा कि वह बच्चों का होमवर्क मोबाइल पर भेजना बंद करें अपने नौनिहालों को सुरक्षित रखने के लिए हमें समग्रता में कदम उठाने होंगे। ●

चुनाव से पहले नीतीश सरकार की घोषणाओं की बौछार

कल्याणकारी कदम या चुनावी जुमला?

● मिथिलेश कुमार

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही सत्ता का संग्राम तेज हो गया है। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले इस चुनाव में वर्तमान एनडीए सरकार, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 से (कुछ अंतरालों को छोड़कर) सत्ता पर काबिज है, ने पिछले कुछ महीनों में आम जनता के लिए एक के बाद एक घोषणाएं की हैं। वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि से लेकर जीविका दीदियों को 10 हजार रुपये की सहायता, निर्माण मजदूरों को 5 हजार की एकमुश्त राशि और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय वृद्धि तक ये घोषणाएं लाखों लोगों को सीधे प्रभावित करने वाली हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है: क्या ये वास्तविक कल्याणकारी प्रयास हैं या फिर 20 साल पुरानी सरकार का चुनावी हथकंडा? पिछले एक महीने में हुई इन घोषणाओं की संख्या 20 वर्षों के औसत से कहीं अधिक है, जो विपक्ष और विश्लेषकों के बीच बहस का विषय बनी हुई है।

नीतीश कुमार सरकार ने जून से सितंबर 2025 के बीच कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है, जो मुख्य रूप से महिलाओं, बुजुर्गों, मजदूरों और ग्रामीण स्तर की कार्यकर्ताओं पर केंद्रित हैं। इनका कुल मूल्यांकन अरबों रुपये में है, और ये सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर होने वाली हैं। पेंशन राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये मासिक। विधवा और दिव्यांग पेंशन भी 700 रुपये बढ़ाई गई। 1.09 करोड़ से अधिक लाभार्थी, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जीविका दीदियों (स्वयं सहायता समूह महिलाओं) को उद्यम शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की एकमुश्त सहायता। पहली किस्त सितंबर में लाखों जीविका महिलाएं। निर्माण मजदूर सहायता वार्षिक वस्त्र सहायता योजना के तहत प्रत्येक पंजीकृत मजदूर को 5,000 रुपये एकमुश्त। कुल 802 करोड़ रुपये। 16.05 लाख निर्माण मजदूर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानदेय वृद्धि सेविका (कार्यकर्ता) का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये, सहायिका का 4,000 से 4,500 रुपये मासिक। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका। इनके अलावा, छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 12वीं पास छात्रों को ब्याज-मुक्त शिक्षा ऋण और घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली जैसी अन्य घोषणाएं भी की गई हैं। पटना जिले में ही 1,159 करोड़ रुपये की 17 योजनाओं का शिलान्यास इसी कड़ी का हिस्सा है। सरकार का दावा है कि ये कदम 'सामाजिक न्याय' और 'महिला सशक्तिकरण' की दिशा में हैं, जो नीतीश कुमार के लंबे शासनकाल की निरंतरता हैं।

नीतीश कुमार 2005 से बिहार की राजनीति के केंद्र में हैं, जब जेडीयू-बीजेपी गठबंधन ने लालू प्रसाद यादव के आरजेडी को सत्ता से हटाया था। 20 वर्षों में बिहार ने सड़कें, बिजली और शिक्षा में प्रगति की है, लेकिन बेरोजगारी, प्रवासन और गरीबी जैसे मुद्दे बरकरार हैं। विश्लेषकों का कहना है कि 2005-2020 के बीच ऐसी श्बड़े पैमाने कीश घोषणाएं दुर्लभ थीं। उदाहरण के लिए, वृद्ध पेंशन में पिछली बड़ी वृद्धि 2019 में हुई थी, जब इसे 300 रुपये किया गया था। लेकिन 2025 में, चुनाव से महज चार-पांच महीने पहले, इन घोषणाओं की बौछार ने सवाल खड़े कर दिए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, जून से सितंबर तक जारी की गई राशि ही 1,247 करोड़ रुपये से अधिक है।

☞ **क्या है चुनावी हथकंडा? विश्लेषण और आलोचना** :- ये घोषणाएं निश्चित रूप से स्वागत योग्य हैं। वृद्धों को अतिरिक्त 700 रुपये मासिक से सालाना 8,400 रुपये का लाभ, जीविका महिलाओं को उद्यम के लिए प्रोत्साहन, और मजदूरों को तत्काल राहत। लेकिन टाइमिंग संदिग्ध है। विपक्षी दलों, खासकर आरजेडी और कांग्रेस ने इन्हें 'चुनावी जुमला' करार दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, '20 साल सत्ता में रहने के बाद अब जागे हैं? ये घोषणाएं वादों की तरह ही रह जाएंगी।' कांग्रेस ने भी केंद्रीय बजट की बिहार-केंद्रित घोषणाओं को श्चुनावी उपहारश बताया। आलोचकों का तर्क है कि ये एकमुश्त या सीमित अवधि की हैं, जैसे मजदूरों को 5,000 रुपये की एकबारगी सहायता, जो दीर्घकालिक रोजगार सृजन का विकल्प नहीं। इसके अलावा, बिहार का राजकोषीय घाटा (GDP का 3.5% से अधिक) इन योजनाओं पर दबाव डाल सकता है, जिससे भविष्य में कटौती का खतरा है। दूसरी ओर, समर्थक इन्हें 'जन-केंद्रित शासन' का प्रमाण मानते हैं। नीतीश कुमार ने कहा, 'ये योजनाएं पहले से चली आ रही हैं, चुनाव से कोई लेना-देना नहीं।' वास्तव में, जीविका कार्यक्रम 2007 से चल रहा है, और पेंशन वृद्धि महामारी के बाद की आवश्यकता थी। लेकिन डेटा बताता है कि पिछले एक महीने (अगस्त-सितंबर 2025) में घोषणाओं की संख्या असामान्य रूप से अधिक है। सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी है, जहां कुछ यूजर्स इन्हें 'लॉलीपॉप' कह रहे हैं, जबकि अन्य श्वास्तविक राहतश मान रहे हैं। ग्रामीण बिहार, जहां 90% आबादी रहती है, इन घोषणाओं से प्रभावित होगी। सर्वे बताते हैं कि महिलाओं और बुजुर्ग वोटर निर्णायक भूमिका निभाएंगे, लेकिन अविश्वास भी है। 2020 चुनाव में भी इसी तरह के वादे किए गए थे, लेकिन कई योजनाओं का कार्यान्वयन धीमा रहा। यदि ये घोषणाएं समय पर लागू हुई, तो एनडीए को फायदा हो सकता है; अन्यथा, विपक्ष 'गरीबी हटाओ' के नारे को मजबूत करेगा। नीतीश सरकार की ये घोषणाएं बिहार की आर्थिक कमजोरी को दूर करने का प्रयास हैं, लेकिन उनका चुनावी संदर्भ नकारा नहीं जा सकता। 20 साल के शासन में मूलभूत सुधारों की कमी ने जनता को सतर्क बना दिया है। असली परीक्षा इनके कार्यान्वयन में होगी। क्या ये जनता की जेब मजबूत करेंगी या सिर्फ वोट बैंक? चुनावी मैदान में ये घोषणाएं हथियार तो बनेंगी, लेकिन अंतिम फैसला बिहार की 12 करोड़ जनता का होगा। ●

कर्पूरी के मूल अतिपिछड़ा कि हकमारी कि तो होगी 2025 में नीतीश की विदाई

● अमित कुमार सिंह/अनीता सिंह

28 अगस्त को महापंचायत लगाकर डॉ रामबली ने नीतीश कुमार को खुली चुनौती देकर कहा कि अगर ये काला कानून वापस नही लिया तो 45: अति पिछड़ा वोट कि चोट से 2025 मे सता से बाहर कर देगी। इसकी आवादी बिहार कि आवादी का लगभग 6 करोड़ कि आवादी वाला अति पिछड़ा इस वार किसी के झासे मे नही आने वाली है। 'माल महाराज का मिर्जा खेले होली', वोट हमारा राज तुम्हारा नही चलेगा। नही चलेगा। लालू ने 90 के दशक से 15 साल नीतीश ने 20 वर्षो तक अति पिछड़ा का वोट लेकर उसी पर हुकुमत चलाया 2015 मे ये काला कानून आया जब से न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के सारे नौकरीयो पर 90 से 95 प्रतिशत तक तेली, तमोली (चौरसीया) का कब्जा है। इस तरह से 111 जाति का आरक्षण शुन्य हो गया और मुल अति पिछड़ा समाज के मुख्य धारा से 200 वर्शो तक पीछे चला गया नीतीश और लालु ने जाति आधारित जनगणना कराया। उसके अनुसार ही ब्ड अति पिछड़ा का होना चाहिए ना ही मंत्रालय में 40 से 45% हिस्सेदारी दिया। आज तक इस तरह से तेजी से प्रतिनिधित्व घट रहा है। इसके पूर्व कई बार विधान सभा में धरणा, विधान सभा घेराव, मिलर स्कूल मे कई बार कार्यक्रम, कई तरह से सड़क से सदन तक तेली, तमोली (चौरसीया) दांगी के खिलाफ पूर्व एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी आवाज उठाते रहे। अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के संयोजक

एवं पूर्व एमएलसी डॉ० रामबली सिंह चंद्रवंशी ने कहा जननायक कर्पुरी ठाकुर के मूल अतिपिछड़ा की हकमारी बर्दाशत नही होगा। बिहार की एनडीए सरकार अगर समय रहते जल्द ही हमारी मांगो को पूरा नही करती है तो इस बार सरकार कि बिदाई तय है। प्रो० चंद्रवंशी ने यह बाते अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा द्वारा आयोजित अतिपिछड़ा महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा। इसका आयोजन पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान मे किया गया। डॉ० चंद्रवंशी ने तेली, तमोली (चौरसीया), दांगी को अतिपिछड़ा वर्ग में लाकर 2015 में एक नया काला कानून लाया, जिससे मूल अति पिछड़ो कि हकमारी हुई। इस हकमारी के खिलाफ पूरे बिहार के अतिपिछड़ा लगातार आवाज को बुलंद कर रही है। महापंचायत में सभी प्रखण्ड पंचायत के प्रतिनिधियो ने भाग लिया। अतिपिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा ने पाँच सूत्री मांगो को लेकर मिलर हाई स्कूल के मैदान मे महापंचायत का आयोजन किया था। इसमे राज्यभर से अतिपिछड़ा समाज के लोग काफी संख्या मे एकजुट हुए और अपनी मांगो को लेकर बुलंद किये। इस कार्यक्रम में बिहार के 38 जिले के सभी प्रखण्ड एवं सभी पंचायत के लोगों ने अपनी भागीदारी दी।

कार्यक्रम के अध्यक्षता मोर्चा से संयोजक पूर्व एमएलसी डॉ० रामबली सिंह चंद्रवंशी ने किया। मंच संचालन फिरोज मंशुरी ने किया। इस अतिपिछड़ा महापंचायत को बसंत चौधरी दानी, प्रजापति, अजय कानू, शिव पूजन ठाकुर, प्रयाग सहनी, गणेश मंडल विश्वकर्मा, आशीष नारायण, नितू सिंह निशा, अनिता कुमारी, मनोज चंद्रवंशी, प्रमोद चंद्रवंशी समेत हजारो हजार कि संख्या में पूरे बिहार से लोग पहुँचे। ●